नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 20 फरवरी 2026

> एआई की सफलता का असली पैमाना यह है कि वह रोजमर्रा की समस्याओं को कितने प्रभावी ढंग से हल कर सकता है।
> – *सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO*

AI का मानव मंत्र

नई तकनीक अपने साथ उत्साह लाती है और आशंकाएं भी। इतिहास में मानवता ने जितने भी बड़े बदलाव देखे, वे इन्हीं मिली-जुली भावनाओं के साथ अपनाए गए। AI के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार भावनाएं ज्यादा तीव्र हैं। वजह कि बदलाव की रफ्तार बेहद तेज है और असर व्यापक। ऐसे में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विजन और जिम्मेदारी की बात कही है, उसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। इसी से तय होगा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आगे चलकर क्या रंग लाता है।

समिट के संदेश

मानवतावादी दृष्टिकोण । पीएम मोदी ने AI के लिए 'MANAV' मंत्र दिया है। यह वो मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो पारदर्शिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और साझा विकास की बात करता है। जब कुछ देश तकनीक और संसाधनों पर कब्जा चाहते हैं, तब भारत का संदेश है कि एकाधिकार टूटना चाहिए। कुछ देश प्रॉड्यूसर और बाकी केवल यूजर बनकर नहीं रह सकते। गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयर ब्रैड स्मिथ ने भी तकनीक के जरिये इसी समानता की बात कही है।

पारदर्शिता और भरोसा । AI से उम्मीद है कि वह विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है। ऐसा भरोसा कभी इंटरनेट ने भी जगाया था, पर विभिन्न देशों के विभिन्न नियम-कायदों ने उसे कई खांचों में बांट दिया। लेकिन, AI की क्षमता इससे आगे की है। इसकी बढ़त का फायदा सभी को मिल सकता है, बशर्ते पारदर्शिता हो। समिट में भारत ने अपनी सोच रखी कि कोड ओपन हों और शेयर किए जाएं, तभी उन्हें ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है।

नियमों की जरूरत । वैश्विक साझेदारी इसलिए भी जरूरी है ताकि AI के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। डीपफेक और फर्जी ऑडियो-विडियो-फोटो कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती हैं और इनका सामना कमोबेश सारे देश कर रहे। इसी वजह से भारत ने पिछले दिनों डिजिटल नियमों को ज्यादा सख्त किया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कही है, जो वक्त की जरूरत है।

क्षमता का प्रदर्शन । इस समिट के जरिये भारत ने दिखाया है कि उसके पास AI के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम बनाने की क्षमता है। UPI इसका उदाहरण है, जिसकी तारीफ इस आयोजन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की। रिलायंस और अडाणी जैसे बड़े समूहों का आगे आना अच्छे संकेत हैं। दूसरे दिग्गजों के पास भी अवसर है कि वे भारत में बन रहे मौकों का इस्तेमाल कर ऐसे प्रॉडक्ट डिवेलप करें, जो फिर बाकी दुनिया के काम आएं।

तिराहा

नवाचार के दुश्मन

प्रेम शंकर मिश्र

सुधर्मा सुबह से ही किताबें पलट रही थीं। आज उनका रोबोटिक्स पर व्याख्यान है। पढ़ाती तो वह पॉलिटिक्स हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में नए खुले AI-रोबोटिक्स विभाग की भी समन्वयक हैं। सुधर्मा की चिंता सुखनंदन भांप गए। वैसे भी वह प्राचीन से आधुनिक शिक्षा की यात्रा के सारथी हैं। दो दशक से कुलपति के पद पर हैं। उनके शोध पत्रों की शुद्धता, मौलिकता और गुणवत्ता पर शोधार्थी से संसद तक शोध व विमर्श कर चुके हैं। अंकपत्र और प्रमाणपत्र तो पूछिए ही नहीं, कई विश्वविद्यालयों का तो प्रादुर्भाव ही इन डिग्रियों में हुआ है।

सुधर्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, 'प्रिये! कहां कागजों में उलझी हो, मैं रास्ता निकालता हूं।' उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया, रोबोटिक्स के 121 फायदे बताओ! चंद सेकंड में नोट्स तैयार। प्रिंट आउट निकाल विजयी मुद्रा में उसे सुधर्मा को थमा दिया। सुधर्मा ने हिचकते हुए कहा, 'लेकिन, यह तो नकल हुई, शिक्षक को तो ज्ञान व मौलिकता पर ध्यान देना होता है। किसी ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी।'

'प्रिये! ऐसा करने वाला नवाचार के दुश्मन हैं। ज्ञान कहता है- आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अर्थात पूरे विश्व से कल्याणकारी और शुभ विचार आते रहें। वैश्विक खोज, वैचारिकी का लाभ न उठाना अज्ञानता है। रही बात मौलिकता की, तो मौलिक केवल असत्य है, जो मनुष्य खुद गढ़ता है। सत्य तो शाश्वत है। एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति - सत्य एक ही है, उसे अलग-अलग ढंग से कहा जाता है। अतः मौलिकता रूपी असत्य के भ्रम में विद्वान नहीं पड़ते। वैसे भी विश्वविद्यालयों का कार्य सर्च नहीं रिसर्च है।' सुखनंदन ने समझाया। 'लेकिन! कुछ तो नया देना होगा विद्यार्थियों को?' सुधर्मा की हिचक जारी थी। 'प्रिये! तुम स्वयं सुधर्मा हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय... का मंत्र आत्मा की अमरता ही नहीं शिक्षा में भी लागू है। जैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करती है, वैसे ही पुराना नोट्स नए शिक्षक और छात्र को धारण कर लेता है। अतः शिक्षा को नहीं परीक्षा को छात्रोन्मुखी बनाओ, कभी प्रश्न नहीं उठेगा।'

एकदा

संकलन : **सुभाष चंद्र शर्मा**

कलाम की पसंद

यह घटना 2002 की है, जब अन्ना यूनिवर्सिटी में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अध्यापन कर रहे थे। एक दिन वह कक्षा लेने के बाद कैंटीन में सहकर्मी प्रफेसरों के साथ चाय पी रहे थे, तभी सूचना मिली कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण फोन आया है। फोन पर बताया गया कि प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि देश ने आपकी सेवाएं देखी हैं और अब हम चाहते हैं कि आप देश के अगले राष्ट्रपति बनें। यह सुनकर डॉ. कलाम कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। उन्होंने विनम्रता से कहा कि उन्हें पढ़ाना अधिक प्रिय है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राष्ट्रपति रहते हुए भी आप पढ़ा सकते हैं। आधे घंटे का समय सोचने के लिए दिया गया। साथियों से चर्चा के बाद डॉ. कलाम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निर्णय के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और शीघ्र ही वह दिल्ली रवाना हुए। इस प्रकार 2002 में देश को एक लोकप्रिय, सरल और प्रेरणादायक राष्ट्रपति मिला, जिन्हें हम आज भी एक महान शिक्षक के रूप में याद करते हैं।

Subrata Dhar

महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच मुस्लिम वोट बैंक को साधने की होड़

ये झगड़ा क्या कहलाता है

गंगाधर ढोबले

मालेगांव महानगर पालिका की उपमहापौर और सपा नेता 'शान-ए-हिंद' निहाल अहमद के केबिन में लगी टीपू सुल्तान की फोटो राजनीतिक संग्राम के बाद प्रशासन ने हटा ली है। हालांकि आसार कम हैं कि विवाद यहीं थम जाए। विवाद के तीन मुख्य कारण हैं, पहला- इस फोटो को लगाते समय अन्य राष्ट्रीय नेताओं की फोटो कमरे से पूरी तरह हटा देना, दूसरा- टीपू को स्वतंत्रता सेनानी मानना और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज से उनकी तुलना करना, और तीसरा- BJP के खिलाफ मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश।

विवाद थमा नहीं । टीपू सुल्तान की फोटो हटाने के साथ हिंदू संगठनों की मांग पर उपमहापौर निहाल अहमद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन, निहाल अहमद फोटो फिर से लगाने पर अड़ी हैं। उन्होंने कहा कि दफ्तर की मरम्मत के लिए फोटो उतारी गई थी।

कांग्रेस का कूदना । इस विवाद ने इसलिए और तूल पकड़ा, क्योंकि निहाल अहमद के पक्ष में कांग्रेस आ गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एक कदम आगे बढ़कर टीपू की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। उन्होंने कहा कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में जो वीरता दिखाई, उससे उन्हें शिवाजी महाराज के समकक्ष माना जा सकता है। इन टिप्पणियों के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और सपकाल से माफी की मांग की जाने लगी।

स्थानीय राजनीति का असर । विवाद की पृष्ठभूमि में मालेगांव की स्थानीय राजनीति है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। मालेगांव मनपा में कुल 84 सीटें हैं। नई-नवेली इस्लाम पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस दल की स्थापना पूर्व विधायक आसिफ शेख ने दो साल पहले की थी।

नए समीकरण । यहां सपा ने 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं है, उसने बाहर से ही अपनी 3 सीटों का समर्थन गठबंधन को दे दिया। इन तीनों के गठबंधन की कुल संख्या 43 होती है, यानी स्पष्ट बहुमत। इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद महापौर बनीं और सपा की निहाल अहमद उपमहापौर। लेकिन, दोनों ने दोस्ती नहीं चुनी। दोनों इस्लामिक पार्टियों का टकराव देशभर में नए समीकरण बनाएगा।

कांग्रेस का डर । इस्लाम पार्टी ने बीते हफ्ते (16 फरवरी) राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न अंचलों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अब मेड़ पर बैठी हुई है और उसे अपना मुस्लिम आधार खोने का डर है। सपकाल के टीपू के समर्थन में उतरने का राज यही है।

विवादित तुलना । छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना समय-समय पर कुछ राजनेताओं और लेखकों ने की है, लेकिन यह विषय हमेशा विवादित रहा। मुगल और ब्रिटिश इतिहासकारों ने शिवाजी महाराज की तुलना में टीपू को ही तवज्जो दी और यही इतिहास हम पढ़ते रहे हैं। शिवाजी महाराज (1630-1680) और टीपू सुल्तान (1751-1799) के कालखंड अलग-अलग थे और भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी पृथक रहीं। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और स्वराज्य की स्थापना की, जबकि टीपू ने मैसूर रियासत के शासक के रूप में अंग्रेजों से चार युद्ध लड़े।

आरोपों में टीपू । शिवाजी को समन्वयवादी माना जाता है, जबकि टीपू कुछ मामलों में विवादित रहे और इतिहासकारों का एक वर्ग उन्हें 'धार्मिक कट्टर शासक' मानता है। टीपू पर आरोप है कि वर्तमान केरल के मालाबार अंचल में बगावत रोकने के दौरान उसने हिंदुओं और ईसाइयों के कुछ समुदायों का कत्लेआम किया। इस दौरान मालाबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। कूर्ग और मंगलूर क्षेत्र में भी कमोबेश ऐसा हुआ। दूसरे पक्ष के इतिहासकारों का कहना है कि ब्रिटिश स्रोत अतिरंजित है। सभी धर्मांतरण जबरन नहीं हुए, कुछ राजनीतिक कारणों से हुए। टीपू ने श्रृंगेरी मठ समेत कई मंदिरों को दान भी दिए।

जयंती पर रार । लगभग 10 साल पहले कर्नाटक से यह विवाद उछला। 2015 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 10 नवंबर को 'टीपू जयंती' मनाने का निर्णय किया। इसके बाद राज्यभर में विरोध प्रदर्शन हुए। 2018 में जब राज्य में बीएस येदियुरप्पा की BJP सरकार आई, तो उसने 'टीपू जयंती समारोह' रद्द कर दिया। अब सरकारी समारोह नहीं होते, लेकिन कुछ संगठन निजी तौर पर आज भी टीपू जयंती मनाते हैं। मतलब विवाद अब भी जिंदा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

AI Image

विवाद की वजह

- मालेगांव उपमहापौर ने अपने केबिन में लगाई थी टीपू सुल्तान की तस्वीर
- महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने टीपू की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी
- नई पार्टी ISLAM समर्थन बढ़ाने की कोशिश में, AIMIM भी जुटी

आपकी ट्रेन इसलिए बार-बार लेट हो रही

गुलशन राय खत्री

भारतीय रेलवे में बीते 10 बरसों में बड़े पैमाने पर बदलाव और सुधार हुए हैं। अनुमान के मुताबिक, बीते एक दशक में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसी दौरान मिशन रफ्तार शुरू हुआ, ताकि ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सके। हाल में संसद में रेलवे पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पेश हुई। यह बताती है कि 2021-22 में 90% से अधिक ट्रेनें तय वक्त पर या उससे पहले पहुंचीं। लेकिन, 2023-24 में आंकड़ा 78.67% और अगले साल 73.62% ही रह गया।

स्पीड में कमी । यह स्थिति तब है, जब भारत में 15 मिनट की देरी को काउंट नहीं किया जाता। नीदरलैंड में यह पैमाना 3 मिनट, जर्मनी और रूस में 5 मिनट, जबकि जापान में तो चंद सेकंड का है। मिशन रफ्तार के तहत लक्ष्य था कि मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 25 किमी से बढ़ाकर 50 किमी प्रतिघंटे की जाए। वहीं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत रफ्तार को 50 से बढ़ाकर 75 पर पहुंचाया जाए। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 97% मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की गति निर्धारित लक्ष्य से कम है। कुल 2951 ट्रेनों की स्पीड के आंकड़े जांचे गए। महज 62 की गति औसतन 75 से ऊपर मिली। 60 ट्रेनों की एवरेज स्पीड तो 30 या इससे भी कम थी।

ट्रैक पर दबाव । कानपुर सेंट्रल जंक्शन के समीप रेलवे लाइन की क्षमता का 175% उपयोग हो रहा था, यानी जिस ट्रैक पर सौ ट्रेन दौड़नी चाहिए, वहां 175 दौड़ रही थीं। पटना जंक्शन के समीप राजेंद्र नगर में यह औसत 172, प्रयागराज में 137 और दानापुर खंड में 170 मिला। देश को रेल लाइन बढ़ाने की जरूरत है। अगर ट्रेनें बढ़ीं, पर ट्रैक उतने ही रहे तो रफ्तार कम हो जाएगी।

आउटर का संकट । देरी की एक और वजह यह है कि कई बार ट्रेनों को आउटर पर ही रोक दिया जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं होते। यह स्थिति लंबी दूरी की ट्रेनों की है, जिनकी निगरानी होती है। छोटी दूरी की लोकल और पैसेंजर ट्रेनों की हालत और खराब है। रेलवे अफसर राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनों को टाइम पर चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे पैसेंजर ट्रेनों को कई बार साइड में रुकना पड़ता है।

कॉमन रूम

उत्तर भारत में सर्दियों में कोहरे के कारण भी देरी होती है। ड्राइवर के लिए सिग्नल देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गाड़ियों की अधिकतम गति को कम कर दिया जाता है। घने कोहरे में तो स्पीड केवल 25 किमी तक रखी जाती है।

इंफ्रा पर काम । सरकार को देरी पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, जैसा जर्मनी ने किया। उसने गाड़ियों की लेटलतीफी पर रेलवे के सीईओ को हटाकर कड़ा संदेश दिया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है, जिस पर काम हो रहा है। नई पटरियां बिछाने में समय लगता है, इसलिए इसका असर दिखने में भी वक्त लगेगा। मेंटिनेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें टेक्नॉलजी का इस्तेमाल हो, ताकि समस्या का जल्द पता लग सके। एक बड़ा बदलाव रोलिंग स्टॉक में हो रहा है। अब रेलवे वंदेभारत ट्रेनों का प्रॉडक्शन कर रहा है। इस तरह की ट्रेनें जल्द रफ्तार पकड़ती हैं और जल्द रुकती हैं, जिससे समय की भी काफी बचत होती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

सभी में शंकर मौजूद, बस जागृत करने की देर

आनन्दमूर्ति गुरुमां

शिवपुराण में भगवान शंकर की कई लीलाओं का वर्णन है। महादेव के भक्त उनकी हर बात को लीला मानकर आनंदित होते हैं। मगर, ज्ञान की दृष्टि से देखने पर लीला का आध्यात्मिक अर्थ होता है। अगर हम उसे जान लेते हैं तो हमारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। इसलिए इन लीलाओं को समझना उतना भी सरल नहीं है।

श्रीराम और श्रीकृष्ण का जन्म कब हुआ था, यह हमें पता है। मगर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के जन्म का ज्ञात किसी को नहीं। ये तीनों बाहरी के साथ-साथ आध्यात्मिक स्वरूप भी हैं। भोले शंकर को मृत्यु का देवता कहा जाता है। किंवदंती है कि समस्त प्राणियों की मौत इनकी मर्जी से होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के योग वाला व्यक्ति अगर महामृत्युंजय जप करता है, तो उसकी मौत टल जाती है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि वह अमर हो जाएगा। हां, उसके भीतर मौत का भय खत्म हो जाएगा।

AI Image

महामृत्युंजय मंत्र बस एक शुरुआत है। वास्तविकता है कि देह मरती है और वह मरेगी। मगर, उस देह पर हमारा असली स्वरूप वही है, जो भगवान शंकर का है। देह संग आसक्त व्यक्ति कभी शिव को नहीं समझ सकता। शिव यानी कल्याण स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंदस्वरूप। जिसने भी सच्चिदानंद स्वरूप शिवात्मा को जान लिया वह सदैव जन्म-मरण चक्र से बाहर निकल जाता है।

भगवान शंकर की तरह हमारे मस्तक के बीच भी तीसरा नेत्र है। भोलेशंकर के तीसरी आंख खोलने पर प्रलय आ जाती है। जब तक हमारा तीसरा नेत्र बंद है, तब तक माया, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हमारे चित में हैं। जिस दिन ध्यान से यह नेत्र खुलता है ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है। उस रोज हमारे चित से माया, ममता खत्म हो जाएगी। लेकिन, इसे खोलने के लिए साधना करनी होगी।

भगवान शंकर की तरह ही हमारे शरीर पर भी नाग है, पर वह कुण्डली मारे सोया है। इसलिए ही उसे कुण्डलिनी कहते हैं। यह जब तक सुप्त है, तब तक हम कितनी बार भी राम-राम रटते रहें, कुछ नहीं होने वाला। किसी संत अथवा जागृत ब्रह्मज्ञानी गुरु की विधि से अभ्यास करने पर यह शक्ति जागृत होने लगती है।

कांटे की बात

> हम भारत के साथ सच्चा और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं। कूटनीतिक जटिलताओं के कारण विश्व कप नहीं खेल सके। यदि वे मुद्दे पहले ही बातचीत से सुलझा लिए गए होते, तो हमारी टीम शायद विश्व कप खेल रही होती।

अमीनुल हक,
बांग्लादेश के नए खेल मंत्री

सप्ताह की शख्सियत

यूक्रेन की यादों को हेरास्केविच ने अपने सिर पर सजाया

यूक्रेन के स्केलेटन रेसर Vladyslav Heraskevych को एक हेलमेट की वजह से विंटर ओलिंपिक्स से बाहर कर दिया। हेलमेट पर रूस-यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले यूक्रेनी खिलाड़ियों की तस्वीर थी। इसे हेलमेट ऑफ मेमरी कहा जा रहा है।

रफ्तार का पुराना खेल

स्केलेटन बर्फ से ढके ट्रैक पर खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी एक छोटी स्लेज पर पेट के बल लेटकर तेज रफ्तार में स्लाइड करते हैं। इसमें हेरास्केविच को महारत हासिल है। अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक संघ (IOC) के उनको बाहर करने के फैसले पर उन्होंने कहा, 'लोगों के जीवन से बड़ा मेडल नहीं।'

पिता से मिली ट्रेनिंग

12 जनवरी, 1999 को कीव में जन्मे हेरास्केविच ने कम उम्र से ही स्केलेटन खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता भी इस खेल से जुड़े थे और उन्होंने ही इसकी ट्रेनिंग दी। हेरास्केविच 2018 विंटर ओलिंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा स्केलेटन एथलीट्स में से एक थे। उन्होंने विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया है।

प्रस्तुतिः अभिषेक मिश्र

जनता जंक्शन

इरफ़ान

दग़ाबाज़ी के दर्द से टेंशन में कांग्रेस

भूपेंद्र शर्मा

अप्रैल में राज्यसभा में 10 राज्यों की 37 सीटें खाली हो रही हैं। इनके लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। राज्यसभा में संख्या के लिहाज से BJP लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन, असल समस्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के सामने है। कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है, मगर इतिहास गवाह है कि क्रॉस वोटिंग के कारण उसने कई बार जीती सीटें भी गंवाई हैं। इसलिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए इस बार जीतने से ज्यादा जरूरी क्रॉस वोटिंग रोकना होगा।

एकजुटता दिखाने का मौका

इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के जरिये कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सबकुछ ठीक है और एकजुटता है। ये इलेक्शन विपक्षी एकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए अपने विधायकों को एक साथ रखने की चुनौती होगी। पिछली बार कांग्रेस को हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार कांग्रेस और सहयोगी दलों को सावधान रहना होगा। कुछ सीटों के नतीजे तय माने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्रॉस वोटिंग नहीं रोक सका तो सीट गंवाएगा।

हरियाणा से BJP सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होने वाला है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में एक सीट BJP और एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मगर, यहां अभी से ही खेल शुरू हो गया है। अगस्त 2022 में क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के अजय माकन हार गए थे, जबकि BJP व JJP के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई थी। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। BJP के पास 48 व कांग्रेस के 37 विधायक हैं।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

हिमाचल-बिहार में पेच

68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होगा। 40 विधायक होने के बाद भी कांग्रेस को सावधान रहना होगा। 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी बहुमत होने के बावजूद हार गए थे। तब कांग्रेस के कुछ विधायकों और निर्दलीय ने BJP प्रत्याशी को जिता दिया था। अभी BJP के 28 विधायक हैं। कांग्रेस को चिंता सता रही है कि इस बार ऐसा कुछ न हो।

बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की दरकार है। NDA के 202 विधायक हैं। इस लिहाज से उसकी 4 सीटें तय हैं। आशंका है कि 35 सीटों वाला विपक्षी गठबंधन INDIA अपने बूते एक सीट भी नहीं जीत पाएगा। ऐसे में 5 विधायकों वाली AIMIM की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां अगर पूरा विपक्ष साथ आ जाए तो एक सीट उसके खाते में आ सकती है। ऐसे में RJD, कांग्रेस, वामदल और अन्य सहयोगियों की एकजुटता जरूरी होगी।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

AI: तकनीकी अवसर

नई दिल्ली में सजा तकनीकी संसार आज पूरे विश्व से आए देशों का ध्यान खींच रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 एआई इंपैक्ट समिट 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' भारतीय मूल्यों पर आधारित है। जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना, जिम्मेदार और नैतिक एआई को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को तेज करना है। यह समिट भारत को एक 'सेतु शक्ति' के रूप में स्थापित करती है जो AI नवाचार को 'पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस' के मानव केंद्रित सिद्धांतों के साथ जोड़ता है।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com
पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

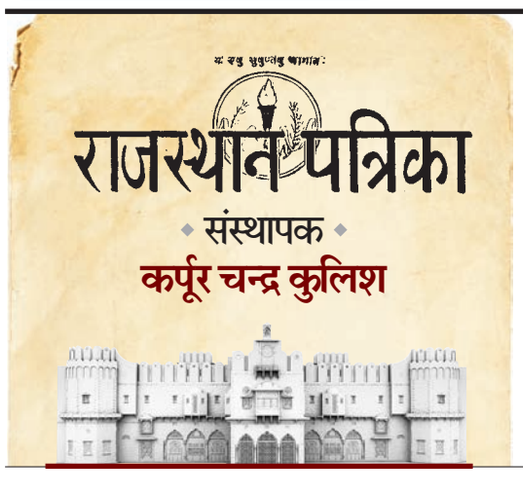

मुफ्त की योजनाओं पर नकेल कसने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने चुनावी राजनीति में बढ़ती 'फ्रीबीज संस्कृति' पर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार को मुफ्त की योजनाओं पर फटकार लगाते हुए दूसरे राज्यों को भी कड़ा संदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि मुफ्त सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से बांटकर आखिर देश में किस तरह की संस्कृति विकसित की जा रही है। मामला तमिलनाडु सरकार के बिना आय स्तर की परवाह किए सभी को मुफ्त बिजली देने के ऐलान से जुड़ा था।

गंभीर बात यह है कि फ्रीबीज योजनाओं के जरिए जनता को उपकृत करने से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ने का संकट रहता है। फ्रीबीज योजनाएं देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र तक प्रभावित हुए हैं। राज्य कर्ज लेकर खपत बढ़ा रहे हैं। आर्थिक सर्वे 2025-26 ने भी चेतावनी दी कि ये योजनाएं उत्पादक निवेश को दबाती हैं। अधिकांश राज्य राजस्व की कमी से जूझ रहे हैं, फिर भी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के बजाय मुफ्त योजनाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। सीमित संसाधनों वाले राज्यों के सामने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसी दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं। यदि बजट का बड़ा हिस्सा मुफ्त वितरण में खर्च हो जाएगा, तो पूंजीगत व्यय और रोजगार सृजन की योजनाएं प्रभावित होंगी। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दोनों पर असर पड़ेगा। हालांकि यह भी सच है कि भारत जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानता वाले देश में लक्षित सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अनिवार्य हैं। गरीब और वंचित तबकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच दिलाना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए सटीक पहचान, आय-आधारित पात्रता और पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता है। सार्वभौमिक मुफ्त वितरण अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकता है, परंतु दीर्घकाल में यह वित्तीय अनुशासन को कमजोर कर सकता है।

फ्रीबीज की राजनीति लोकतांत्रिक विमर्श को भी प्रभावित करती है। चुनावी बहसें विकास, रोजगार, शासन-सुधार और संस्थागत मजबूती से हटकर तात्कालिक लाभों की प्रतिस्पर्धा में बदल जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी किसी विशेष राज्य की आलोचना मात्र नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतावनी है। यह समय है कि राजनीतिक दल और राज्य सरकारें 'मुफ्त' की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर टिकाऊ विकास मॉडल पर ध्यान दें। कल्याणकारी योजनाएं हों, परंतु लक्षित और वित्तीय रूप से उत्तरदायी। संसाधन सीमित हैं, आकांक्षाएं असीमित। ऐसे में संतुलित नीति ही दीर्घकालिक समृद्धि की राह दिखा सकती है।

आर्थिक समृद्धि : जर्मन चांसलर ने वर्क-लाइफ बैलेंस और चार-दिवसीय सप्ताह को पर्याप्त नहीं कहकर छेड़ी नई बहस

कार्य-संस्कृति, उत्पादकता और विकास की चुनौती

के.एस. तोमर
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

सिकुड़ता कार्यबल पेंशन और स्वास्थ्य-व्यय का भार उठाता है। यदि उत्पादकता पर्याप्त न बढ़े, तो कर-राजस्व ठहरेंगे और व्यय बढ़ेगा, जिससे नवाचार और अवसंरचना निवेश प्रभावित होगा। निर्यात-प्रतिस्पर्धा भी चुनौती में है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में जर्मनी का आर्थिक आत्ममंथन बर्लिन से कहीं आगे तक गूंजने वाली बहस बन चुका है। जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रमुख नागरिकों से समृद्धि बनाए रखने के लिए 'अधिक काम' करने का आह्वान करता है, तो यह सांस्कृतिक आलस्य नहीं, बल्कि संरचनात्मक दबाव का संकेत होता है। मर्ज ने 'लाइफस्टाइल पार्ट-टाइम वर्क' अत्यधिक बीमार अवकाश व चार-दिवसीय कार्य-सप्ताह की अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा है कि 'वर्क-लाइफ बैलेंस और चार-दिवसीय सप्ताह वर्तमान समृद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।' उन्होंने ग्रीस जैसे देशों में अधिक कार्य-घंटों की भी सराहना की है।

आलोचक तर्क देते हैं कि जर्मनी की प्रति घंटा उत्पादकता अब भी विश्व में अग्रणी है (ओईसीडी के अनुसार), किंतु मर्ज कुल कार्य-परिमाण पर बल देते हैं। 2026 में जर्मनी का अनुमानित जीडीपी 5.33 ट्रिलियन डॉलर (आइएमएफ अनुमान) है- जो उसे अधिकांश देशों से आगे रखता है, पर लगभग 32 ट्रिलियन डॉलर की अमरीकी अर्थव्यवस्था और 21 ट्रिलियन डॉलर के चीन से काफी पीछे है। भारत, लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ, समग्र आकार में अंतर घटा रहा है, भले ही प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर कायम है। स्पष्ट है कि यह बहस केवल जर्मनी की नहीं, बल्कि वृद्ध होती आबादी और बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना के बीच विकास बनाए रखने की चुनौती का प्रतीक है। यह प्रश्न पूरे विकसित विश्व के सामने है। जर्मनी यूरोप की औद्योगिक धुरी और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का प्रमुख चालक है। उसका इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, रसायन और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र एशिया और भारत से गहराई से जुड़ा है। वहां की किसी भी संरचनात्मक मंदी का असर मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग, तकनीकी साझेदारी और निवेश प्रवाह पर पड़ता है।

श्रम नीति में परिवर्तन एशियाई उत्पादन नेटवर्क तक लहर पैदा करता है और निर्यात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की रणनीतियों को प्रभावित करता है। पिछले दो दशकों से जर्मनी की जनसंख्या लगभग स्थिर है, प्राकृतिक वृद्धि नकारात्मक रही है, जिसे आप्रवासन ने संभाला है। समृद्धि बढ़ने के साथ प्रति श्रमिक वार्षिक कार्य-घंटे घटे हैं। 2024-25 के यूरोस्टेट और ओईसीडी आंकड़ों के अनुसार औसत साप्ताहिक कार्य-घंटे 33.9-34.6 हैं- यूरोपीय संघ में सबसे कम में से- जो लगभग 1,350 वार्षिक घंटों के बराबर है, जबकि ग्रीस में यह लगभग 39.8 है। यह एक परिपक्व कल्याणकारी समाज की प्रवृत्ति है, जहां भौतिक सुरक्षा के बाद अवकाश को महत्व मिलता है। इसके विपरीत, चीन ने विशाल श्रम-निवेश और निर्यात-उन्मुख विस्तार से कुल आकार में जर्मनी को पीछे छोड़ा, जबकि अमरीका ने बेहतर जनसांख्यिकी, श्रम-लचीलापन और नवाचार से बढ़त बनाए रखी। भारत के लिए संकेत स्पष्ट हैं। जर्मन कंपनियां उच्च श्रम-लागत और जनसांख्यिकीय दबाव के बीच लागत-कुशल बाजारों की ओर रुख कर सकती हैं। जनवरी 2026 में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसके तहत 2032 तक यूरोपीय निर्यात दोगुना होने और 96% से अधिक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती का अनुमान है, भारत-जर्मनी व्यापार (जो 29 अरब डॉलर से अधिक है) को गति दे सकता है। परंतु केवल जनसांख्यिकीय लाभ पर्याप्त नहीं। कौशल, उत्पादकता और नियामकीय सुधार अनिवार्य हैं।

मर्ज का तर्क है कि समग्र 'कार्य-प्रदर्शन' अपर्याप्त है। दशकों में प्रति कर्मचारी वार्षिक कार्य-घंटे घटे हैं- यह आलस्य नहीं, बल्कि उच्च आय वाले समाज का तर्कसंगत व्यवहार है। जब वेतन ऊंचे हों, तो श्रमिक अतिरिक्त आय की बजाय अवकाश चुन सकते हैं। मजबूत श्रम-सुरक्षा और कड़े कार्य-समय नियमों ने कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित किया है, पर लचीलापन सीमित किया है। तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कठोर संरचनाएं बाधा बन सकती हैं। जनसांख्यिकीय दबाव और गंभीर है। डेस्टाटिस के अनुसार 2035 तक 67 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की हिस्सेदारी 25-27% तक पहुंच सकती है। वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात भी तेजी से बढ़ेगा। यदि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी नहीं बढ़ती या उत्पादकता में उछाल नहीं आता, तो विकास दर पर दबाव रहेगा। यूरोप के ऊर्जा-परिवर्तन और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच उद्योगों की लागत बढ़ी है। उच्च श्रम-लागत, कम कार्य-घंटे और महंगी ऊर्जा मिलकर औद्योगिक गतिशीलता कमजोर कर सकते हैं।

धीमी वृद्धि भू-राजनीतिक प्रभाव को सीमित करती है। 2026 के लिए 1% के आसपास का विकास अनुमान दर्शाता है कि जर्मनी की गति अपेक्षाकृत सुस्त है। सिकुड़ता कार्यबल पेंशन और स्वास्थ्य-व्यय का भार उठाता है। यदि उत्पादकता पर्याप्त न बढ़े, तो कर-राजस्व ठहरेंगे और व्यय बढ़ेगा, जिससे नवाचार और अवसंरचना निवेश प्रभावित होगा। निर्यात-प्रतिस्पर्धा भी चुनौती में है। यदि लागत-संरचना एशियाई उत्पादकों से अधिक रही, तो उत्पादन और बाजार-हिस्सा पूर्व की ओर खिसक सकता है। भारत के लिए यह अवसर है- बशर्ते लॉजिस्टिक्स, नीति-स्थिरता और कौशल-आधार सुदृढ़ हों। समाधान प्रोत्साहनों के पुनर्संतुलन में है। कर-प्रणाली अतिरिक्त श्रम को दंडित न करे, ऊर्जा-नीति को पर्यावरण और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन साधना होगा। जर्मनी की यह बहस एक सार्वभौमिक संदेश देती है- समृद्धि स्थिर नहीं रहती। वैश्विक अर्थव्यवस्था में न तो केवल उच्च वेतन और न ही केवल लंबे कार्य-घंटे सफलता की गारंटी हैं। दीर्घकालिक स्थिरता का आधार है निरंतर उत्पादकता, संतुलित जनसांख्यिकी और समयानुकूल नीतिगत अनुकूलन। यही विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान रूप से प्रासंगिक सत्य है।

प्रसंगवश

फुटपाथ का हक लौटाइए, तभी सुरक्षित होंगे हमारे शहर

सड़कें चौड़ी हुईं, पर फुटपाथ या तो बने ही नहीं, या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए

शहर तेजी से फैल रहे हैं, पर पैदल चलने वालों की जगह सिकुड़ती जा रही है। सड़कें चौड़ी हुईं, फ्लाईओवर बने, वाहन बढ़े, पर फुटपाथ या तो बने ही नहीं, बने तो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। नतीजा बाजार जाती महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांगजन सभी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में हादसों की आशंका बढ़ती जा रही है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर या जोधपुर- हर जगह दृश्य लगभग एक-सा है। फुटपाथ पर पार्किंग, ठेले, अस्थायी ढांचे या निर्माण सामग्री कब्जा जमाए दिखते हैं। नगरीय निकाय कभी-कभी कार्रवाई करते हैं, पर समस्या स्थायी समाधान मांगती है।

सवाल यह है कि क्या हमारे शहरी नियोजन में पैदल यात्री प्राथमिकता में हैं? न्यायपालिका के इस मुद्दे पर स्पष्ट संकेत हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं, पैदल यात्रियों का भी समान अधिकार है। सड़क सुरक्षा पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी राज्यों को सुरक्षित फुटपाथ बनाने को कह चुकी। हाईकोर्ट भी पैदल मार्ग सुरक्षित रखने पर राज्य सरकार और नगर निकायों को समय-समय पर निर्देश दे चुका है। जमीनी सच्चाई यह है कि शहरी विकास की प्राथमिकता वाहन-केंद्रित ही है। 'स्मार्ट सिटी' के दावे तब तक अधूरे हैं, जब तक शहर 'वॉकएबल' यानी पैदल चलने योग्य नहीं बनते। पर्यटन प्रधान शहर उदयपुर में झीलों और बाजारों के आसपास पैदल यात्री सबसे अधिक घूमते हैं, पर वहीं फुटपाथ या तो हैं नहीं, जहां है वहां बाधित मिलते हैं। कुछ वीआइपी रास्तों को छोड़ दें तो जयपुर के प्रमुख मार्गों पर भी लगातार सुरक्षित पैदल मार्ग का अभाव है। अब समय है नीति बदलने का। 'पैदल पहले' सिद्धांत को शहरी नियोजन का आधार बनाया जाए। न्यूनतम चौड़ाई के निरंतर, बाधारहित फुटपाथ सुनिश्चित हों। वैकल्पिक वेंडिंग जोन विकसित किए जाएं। हर वार्ड में वॉकएबिलिटी ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। शहर की असली पहचान सड़कों की चौड़ाई से नहीं, बल्कि इससे होती है कि वहां पैदल चलना कितना सुरक्षित है। अगर एक बच्चा या बुजुर्ग बिना डर के सड़क पार नहीं कर सकता, तो विकास का दावा खोखला है। **- राजीव जैन**

rajiv.jain@in.patrika.com

बुक इनसाइट

स्काईलार्क : साहस की कहानी

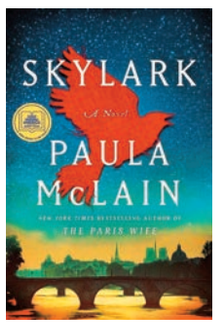

पाउला मैकलेन की किताब 'स्काईलार्क' एक ऐसी कहानी है, जो हमें पेरिस के अंडरग्राउंड इतिहास की गहराई में ले जाती है। यह उपन्यास दो अलग-अलग समयों की घटनाओं को जोड़ता है, जो दोनों ही साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता की खोज से जुड़ी हुई हैं। कहानी की पहली धारा 1660 के दशक की है, जब एक महिला अलौएट, जो अपने गांव के खदानों में काम करती थी, ने एक अनोखा रंग बनाने की कला खोजी। इस रंग के कारण वह रंगाई करने वाले पुरुषों के विरोध का सामना करती है और अंततः पेरिस के पागलखाने में बंद कर दी जाती है। इसके बाद, कहानी समय की लकीरों को पार करती हुई 20वीं सदी के पेरिस में पहुंचती है, जहां एक मनोचिकित्सक क्रिस्टोफ अपने यहूदी पड़ोसियों को बचाने के लिए पेरिस की भूमिगत सुरंगों का उपयोग करता है। मैकलेन का लेखन न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी बहुत गहरे स्तर पर काम करता है। यह समझने का अवसर देती हैं कि किस तरह व्यक्ति और समाज की निरंतर संघर्ष की कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं।

फैक्ट फ्रंट

सकर फुटेड बैट: उल्टे नहीं लटकते

मेडागास्कर का 'सकर-फुटेड बैट' एक अनोखा और रोचक जीव है, जो इस द्वीप की विशिष्ट जैविक विविधता का हिस्सा है। इसे खासतौर पर इसकी चिपकने वाली पैड वाली कलाई और टखनों से पहचाना जाता है। ये पैड चमगादड़ों को ताड़ के पेड़ों की चिकनी, मुड़ी हुई पत्तियों से चिपककर आराम से बसेरा बनाने में मदद करते हैं। इसके पैड में एक गीली चिपकने की क्षमता होती है, जिससे यह सतह से जुड़ता है, बिना किसी सक्शन का इस्तेमाल किए। मेडागास्कर के इस खास चमगादड़ की आदतें भी अन्य चमगादड़ों से अलग हैं। यह आमतौर पर उल्टे लटकने की बजाय, सिर ऊपर करके अपने बसेरे में आराम करता है। ये जीव मेडागास्कर के ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट और कुछ मामलों में सूखे पश्चिमी जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक बनावट भी काफी दिलचस्प है। सकर-फुटेड बैट का शरीर मीडियम आकार का होता है, इसके कान बड़े होते हैं और इसका फर सुनहरा-भूरा रंग का होता है। यह पतंगे और कॉकरोच जैसे कीड़ों का शिकार करता है।

उच्च शिक्षा संवेदनशीलता से ही आएगा बदलाव

उपस्थिति नियमों को लचीला बनाने की आवश्यकता

प्रो. देविंदर सिंह
कुलगुरु, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विवि
@patrika.com

आज जब हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की बात करते हैं, तब हमें उन युवा प्रतिभाओं की याद आती है, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के कठोर निर्णयों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के एक विधि विद्यार्थी ने उपस्थिति संबंधी नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए निलंबन के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ली।

निलंबन, पुनःनामांकन या प्रतिबंध का सामना करने वाले छात्र गंभीर मानसिक आघात से गुजरते हैं। वे अवसाद, चिंता और सामाजिक अलगाव के शिकार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में पिछले वर्ष 17 जनवरी को न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की पीठ द्वारा पारित आदेश में शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल उपस्थिति की कमी के आधार पर छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित करना उचित नहीं है। यह निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता।

न्यायिक विधिशास्त्र में यह सिद्धांत स्थापित है कि किसी भी नियम का उद्देश्य छात्रों की बेहतरी होना चाहिए, न कि उन्हें दंडित करना। अब समय आ गया है कि शैक्षणिक संस्थान यह समझें कि छात्रों की उपस्थिति, निलंबन, पुनःनामांकन और प्रतिबंध से संबंधित निर्णयों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन पर है। यह केवल नियमों का पालन करने का मामला नहीं है- यह जीवन और भविष्य की रक्षा करने का मामला है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें अपनाना चाहिए।

यूजीसी, एआइसीटीई, बीसीआइ, पीसीआइ जैसे सभी नियामक प्राधिकरणों को अपनी नीतियों का पुनरीक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवा-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप करना चाहिए। द्वितीय, संस्थानों को छात्रों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करना चाहिए व उनकी कठिनाइयों को गंभीरता से समझना चाहिए। तृतीय, उपस्थिति नियमों को लचीला बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो चिकित्सीय, पारिवारिक या अन्य वैध कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते। चतुर्थ, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए संरक्षक (मेंटर) आवंटित किए जाने चाहिए जो उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में सहायता करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

सर्दी की कठोरता और सौंदर्य की झलक

जर्मनी का श्वेरिन पैलेस

__जर्मनी__ के मेक्लेनबुर्ग-वोर्पोम्मर्न राज्य की राजधानी श्वेरिन की झील के बीच स्थित महल किसी स्वप्निल संसार जैसा प्रतीत होता है। चारों ओर बर्फ से ढकी झील और महल के आसपास टहलते लोग सर्दी की कठोरता के साथ सौंदर्य का अनुभव लेते दिखाई देते हैं। कभी यह महल मेक्लेनबुर्ग के ड्यूकों और ग्रैंड ड्यूकों का निवास था, जहां से क्षेत्र की सत्ता और सांस्कृतिक जीवन संचालित होता था।

नजरिया संतुलित व टिकाऊ भविष्य के लिए जरूरी

मानव कल्याण हो भारत की उन्नति का मूल आधार

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
स्वतंत्र लेखक एवं शोधार्थी
@patrika.com

विकास को सामान्यतः आंकड़ों के माध्यम से मापा जाता है, जीडीपी की वृद्धि, निवेश में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगिक उत्पादन जैसे संकेतक लंबे समय से प्रगति के मानक बने हुए हैं। दुनियाभर के देश अपनी आर्थिक रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। भारत भी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां वह वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।

इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है कि क्या केवल आर्थिक विकास ही प्रगति की सही पहचान हो सकता है, या फिर विकास के केंद्र में मानव जीवन की भलाई और खुशहाली को रखना अधिक आवश्यक है? यह बहस आर्थिक प्रगति के महत्व को नकारने की नहीं, बल्कि विकास की परिभाषा को ऐसे बदलने की है, जिससे अर्थव्यवस्था इंसान की सेवा करे, न कि इंसान केवल अर्थव्यवस्था का साधन बनकर रह जाए। आर्थिक विकास निश्चित रूप से अवसरों के नए द्वार खोलता है। भारत की आर्थिक उदारीकरण के बाद की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कैसे खुली अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से विकास की गति तेज हो सकती है। करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, शहरों का विस्तार हुआ और भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। ये उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी भी देश के लिए मजबूत आर्थिक आधार के बिना सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना संभव नहीं होता।

चुनौती यह है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं और आर्थिक आंकड़ों तथा आम नागरिकों के वास्तविक जीवन अनुभवों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जब आर्थिक सफलता के साथ पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षा भी बढ़े, तो यह विकास की स्थिरता पर सवाल खड़े करता है। ऐसा विकास, जो प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए, अंततः आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी कमजोर करता है। इसलिए आवश्यक है कि अल्पकालिक लाभों की जगह दीर्घकालिक और मानव-केंद्रित विकास दृष्टि को अपनाया जाए। यदि भारत विकास की व्यापक और मानवीय दृष्टि अपनाता है, तो वह दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है, ऐसा मॉडल जिसमें आर्थिक वृद्धि और मानवीय कल्याण साथ-साथ आगे बढ़ें और एक समावेशी, संतुलित तथा टिकाऊ भविष्य का निर्माण करें।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

संदिग्ध सामग्री को रिपोर्ट करें

डीपफेक से फैलने वाली भ्रामक जानकारी समाज और देश के माहौल को प्रभावित कर सकती है। एआइ से तैयार सामग्री पर वाटरमार्क या मेटाडेटा अनिवार्य किया जाए, ताकि उसकी पहचान संभव हो सके। किसी भी संदिग्ध सामग्री को रिपोर्ट करें। **- लता अग्रवाल,** चित्तौड़गढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'डीपफेक कंटेंट की रोकथाम के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/q9gRn

आज का सवाल

किशोरों को व्यवस्थित जीवनशैली के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

नीति व नुकसान कई देश अब एक-दूसरे के साथ अधिक और अमरीका के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार कर रहे हैं

वैश्विक अर्थव्यवस्था से पीछे हटना यूएस के प्रभाव को करेगा कम

स्कॉट लिन्सिकम
केटो इंस्टीट्यूट से जुड़े अर्थशास्त्री तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ
ब्लूमबर्ग
वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

संभवतः 2025 की व्यापार नीति से जुड़ा सबसे आश्चर्यजनक घटनाक्रम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ नहीं थे, बल्कि विदेशी सरकारों का उसी तरह जवाबी कार्रवाई करने से इनकार था। आर्थिक दृष्टि से यह संयम भले ही उचित हो, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से नेता आमतौर पर 'जैसे को तैसा' वाली प्रतिक्रिया अपनाते हैं। इसलिए जब केवल चीन और कनाडा ने ट्रंप की संरक्षणवादी नीति का अनुसरण किया, तो अपेक्षाकृत सन्नाटा एक असामान्य, हालांकि स्वागतयोग्य परिणाम था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकारें, कंपनियां और यहां तक कि कई व्यक्ति निष्क्रिय बैठे थे।

इसके बजाय उन्होंने अधिक समझदारी से 'जवाबी कार्रवाई' की- ऐसे अमरीका पर अपनी भविष्य की निर्भरता कम करके, जिसने कम से कम 2016 से लगातार संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है। विडंबना यह है कि यही संरक्षणवाद उन देशों की मदद कर सकता है, जिन्हें टैरिफ के जरिये रोकने की कोशिश की गई थी।

अमरीका का वैश्विक व्यापार के केंद्र से हटना वर्षों पहले शुरू हुआ था और हाल के महीनों में यह प्रवृत्ति तेज हुई है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, तीसरी तिमाही में वैश्विक माल व्यापार (आयात और निर्यात) में अमरीका की हिस्सेदारी उस अवधि के लिए 2014 के बाद सबसे कम रही और 2024 से आई गिरावट 2015 से 2024 के बीच कुल गिरावट से भी अधिक थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी अमरीका के बंदरगाहों से आने वाले कंटेनर- जिनमें लगभग 80 प्रतिशत अमरीका के होते हैं- पिछले वर्ष 'विश्व अग्रणी से पिछलग्गू' बन गए। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण 2024 में विश्व व्यापार में अमरीका की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से घटकर 2034 तक 9 प्रतिशत रह जाएगी।

सतह के नीचे और भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर चीन को लेकर। 2018 में जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ लगाए थे, तब चीनी निर्यात का लगभग 19 प्रतिशत अमरीका जाता था, लेकिन पिछले वर्ष के अंत तक यह घटकर 11 प्रतिशत रह गया। इसके बावजूद चीन का कुल निर्यात और व्यापार अधिशेष बढ़ता रहा, क्योंकि वहां के निर्यातकों ने दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान), अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमरीका जैसे अन्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया- जिसे व्यापार अर्थशास्त्रियों ने 'द ग्रेट रिएलोकेशन' कहा है। इनमें से कई देश अब एक-दूसरे के साथ अधिक और अमरीका के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत का निर्यात चीन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को बढ़ा, जबकि अमरीका में ऊंचे टैरिफ के कारण बिक्री प्रभावित रही। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और पेरू ने भी रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, जिसका प्रमुख कारण चीन और अन्य वैश्विक बाजारों के साथ बढ़ता व्यापार था, न कि अमरीका।

यह सही है कि आसियान देश अभी भी अमरीका को बड़ी मात्रा में सामान भेजते हैं, लेकिन अक्सर यह एशियाई आपूर्ति शृंखला का हिस्सा होता है, जो चीनी निवेश और कच्चे माल पर निर्भर है। आज वैश्विक व्यापार वृद्धि का प्रमुख इंजन विकासशील देशों, खासकर पूर्वी एशिया और अफ्रीका के बीच बढ़ता व्यापार है, जबकि उत्तरी अमरीका और यूरोप अपेक्षाकृत ठहरे हुए हैं। बेशक, अमरीका अभी भी एक विशाल अर्थव्यवस्था है और सभी बाजारों ने चीन की राह नहीं पकड़ी है। कनाडा और मैक्सिको अभी भी अमरीकी अर्थव्यवस्था पर काफी निर्भर हैं और उत्तरी अमरीकी आपूर्ति शृंखलाओं में गहराई से जुड़े हैं। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भी अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं, जो एक दशक पहले से भी अधिक है।

दीर्घकाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था से अमरीका का पीछे हटना वाशिंगटन के प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि अन्य देश नए व्यापार मानक तय करेंगे जिनमें अमरीका शामिल नहीं होगा। अन्य देशों का ट्रंप की संरक्षणवादी नीति का अनुसरण न करना दिखाता है कि अधिकांश सरकारें और कंपनियां इन लागतों को समझती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था से अमरीका के 10 वर्षों के पीछे हटने के बाद, अब यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन में भी कोई इन परिणामों को समझ रहा है या नहीं।

https://t.me/AllNewsPapersPad1

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

संघ प्रमुख और भारत राष्ट्र

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत के लखनऊ में दिये गये बयान को सम्पूर्ण राष्ट्रीय सन्दर्भों में देखने की जरूरत इसलिए है कि भारत की संस्कृति हिन्दू मूलक होने की वजह से ही समावेशी व सहिष्णुता से परिपूर्ण रही है। आठवीं सदी में भारत में इस्लाम धर्म के आने से पहले इसकी संस्कृति के मूल मानक सर्वग्राही व सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणीमात्र में प्रेम व सौहार्द भरने वाले थे जिसकी वजह से इस्लाम के आने के बावजूद इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और भारत बीसवीं सदी में भी वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करता रहा।

यह आश्चर्य नहीं था कि 1947 में धर्म के आधार पर भारत के दो टुकड़े हो जाने के बावजूद देश के तत्कालीन कर्णधारों ने आजाद भारत को धर्म या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने का साहस दिखाया। इसका असली कारण यह था कि भारत के बहुसंख्य लोग हिन्दू थे और जो मानते थे कि इस देश की संस्कृति में वह तासीर है जिसके असर से गैर हिन्दू भी नहीं बच सकते। वास्तविकता भी यही है कि भारत में माने जाने वाले सभी धर्मों के अनुयाइयों पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका जिनमें इस्लाम धर्म भी अपवाद नहीं था। भारत चुंकि तीज-त्यौहारों व उत्सवों वाला देश था अत: प्रत्येक धर्म के अनुयाइयों पर इसका गहरे तक असर पड़ा। यही वजह है कि पंजाब व बंगाल के मुसलमानों पर इन दोनों क्षेत्रीय संस्कृतियों की गहरी छाप हमें आज भी दिखाई पड़ती है। असल में श्री भागवत का यह कहना कि भारत में रहने वाला प्रत्येक हिन्दू है, अतिरंजित नहीं है क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने ही भारत के निवासियों को यह नाम दिया था। उनकी नजर में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू था। इसकी छाप हम आज भी तब देखते हैं जब भारतीय मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इन भारतीय मुसलमानों को वहां 'हिन्दी' कहा जाता है।

> **श्री भागवत ने इसके साथ ही हिन्दू समाज में व्याप्त जातिवाद पर भी चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि समाज में जो लोग इस आधार पर पीछे रह गये हैं उन्हें झुक कर ऊपर उठाना होगा। इसमें स्पष्ट सन्देश है कि हिन्दू समाज को अगली सदियों में मानववादी दृष्टि अपनाते हुए सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना होगा और इसके लिए अपने ही बीच से सुधार शुरू करने होंगे। अक्सर संघ पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि वह मनुस्मृति का हिमायती है। इसमें देखने वाली बात केवल इतनी है कि हिन्दू समाज में जिन जातियों का निर्माण हुआ है उनमें लोगों के व्यवसाय या पेशे की भी प्रमुख भूमिका रही है मगर अब 21वीं सदी चल रही है और शिक्षा से लेकर विभिन्न ज्ञान के क्षेत्र समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए खुल रहे हैं अत: व्यवसाय मूलक जातियों का भी खात्मा होना निश्चित है।**

श्री भागवत ने इसके साथ ही हिन्दू समाज में व्याप्त जातिवाद पर भी चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि समाज में जो लोग इस आधार पर पीछे रह गये हैं उन्हें झुक कर ऊपर उठाना होगा। इसमें स्पष्ट सन्देश है कि हिन्दू समाज को अगली सदियों में मानववादी दृष्टि अपनाते हुए सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना होगा और इसके लिए अपने ही बीच से सुधार शुरू करने होंगे। अक्सर संघ पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि वह मनुस्मृति का हिमायती है। इसमें देखने वाली बात केवल इतनी है कि हिन्दू समाज में जिन जातियों का निर्माण हुआ है उनमें लोगों के व्यवसाय या पेशे की भी प्रमुख भूमिका रही है मगर अब 21वीं सदी चल रही है और शिक्षा से लेकर विभिन्न ज्ञान के क्षेत्र समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए खुल रहे हैं अत: व्यवसाय मूलक जातियों का भी खात्मा होना निश्चित है। यह भी हिन्दू समाज की विशेषता रही है कि चारों वर्णों में से किसी एक में जन्म लेना वाला व्यक्ति कर्म के आधार पर अपनी जाति बदलता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि विश्वमित्र रहे हैं जो जन्म से क्षत्रिय या राजा थे मगर कर्म से ऋषि हो गये लेकिन इसके समानान्तर यह भी वास्तविकता है कि इसी भारत में जन्मगत जाति के आधार पर सदियों तक दलित या कथित शूद्र वर्ग के लोगों के साथ पशुवत व्यवहार होता रहा है अत: 21 वीं सदी में इसका जड़मूल से सफाया बहुत जरूरी है क्योंकि यह विज्ञान से भी बढ़ कर अब क्रत्रिम बुद्धिमत्ता का युग होता जा रहा है।

भारत वासियों की दृष्टि शुरू से ही वैज्ञानिक रही है जिसके प्रमाण भी हमें इसकी संस्कृति में समाहित मिलते हैं। प्रकृति को देवतुल्य मान कर इसकी पूजा करने का विधान केवल हिन्दू संस्कृति में ही है जो यह बताता है कि हमारे पुरखे पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे परन्तु 1947 में जब देश का बंटवारा भारत व पाकिस्तान में हुआ तो यह लकीर खिंच गई कि हिन्दू व मुसलमान दो राष्ट्र हैं। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भाषा से लेकर सांस्कृतिक चेतना व ऐतिहासिक मान्यताओं के दम पर अंग्रेजों के सामने यह साबित किया कि हिन्दू व मुस्लिम दो अलग- अलग कौमें हैं। हालांकि उस समय भी भारत में ऐसे मुसलमानों की कमी नहीं थी जो हिन्दू व मुसलमानों की मुत्तैहदा कौमियत के हिमायती थे और भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे। संघ प्रमुख ने इसी बात को आज थोड़ा घुमा कर कहा है और विचार व्यक्त किया है कि भारत में हर रहने वाला हिन्दू ही है, बेशक उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है क्योंकि ये सभी एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं। इसका प्रमाण यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बाद भारी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ और यहीं के निवासियों को इस्लाम धर्म की रवायतों में ढाला गया। वर्ना मुस्लिम आक्रान्ताओं के साथ अरब या अन्य देशों से बहुत थोड़ी संख्या में ही लोग आये थे।

इस बात पर जरूर मतभेद हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा धर्मान्तरण किस मुस्लिम सुल्तान या बादशाह के कार्यकाल में हुआ मगर धर्म परिवर्तन से इंकार नहीं किया जा सकता। यह विचारणीय है कि हमने स्वतन्त्र भारत में प्रत्येक धर्मानुयायी को अपने-अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने का खुला संवैधानिक अधिकार दिया जिसका गलत लाभ कुछ कट्टरपंथियों ने उठाया और लालच या अन्य प्रलोभनों के जरिये लोगों का धर्म परिवर्तन कराते रहे जिसकी वजह से ऐसे धर्मों के मानने वालों की जनसंख्या में वृद्धि इस वजह से भी हुई जबकि हिन्दू मतावलम्बी ऐसे रास्तों से अलग रहे। जब भारत का अस्तित्व ही हिन्दू संस्कृति व इसकी मान्यताओं पर टिका हुआ है तो इस धर्म के मानने वालों का भी यह दायित्व बनता है कि वह भारत की राष्ट्रीयता को सर्वदा जीवन्त रखें। क्योंकि हिन्दू राष्ट्रीयता व भारतीयता में कोई खास अन्तर नहीं है। अत: संघ के प्रमुख के वक्तव्य को संकीर्णता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

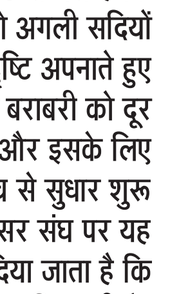

फैसला

गीता पाढा

"उच्चतम न्यायालय का एक फैसला फिर सुर्खियों में आया है,
बलात्कार की विस्तृत परिभाषा और
यौन शोषण पर कड़ा रुख अपनाया है,
कितनी महिलाओं ने छेड़खानी के उन हादसों के
बाद जिंदा लाशों सा जीवन बिताया है,
न्यायशास्त्र के सिद्धांत को पुनर्जीवित करवाया है,
अब संवेदना के साथ कानून ने अपना धर्म निभाया है,
दोषियों के लिए कठोर दंड का स्पष्ट संदेश दिखाया है...।"

एक नई सुबह

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री-निर्वाचित तारीक रहमान के शपथ-ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का पहला कदम बांग्लादेश की ओर से उठाया गया तो यह संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का स्पष्ट संकेत और इरादा था। यह उस रिश्ते के लिए मानो एक नए सवेरा जैसा था जो अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था। रिकॉर्ड के लिए रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने हालिया चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की। यह वह पहला चुनाव था जिसका सामना देश ने शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद किया।

रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। खालिदा जिया का पिछले वर्ष दिसंबर में निधन हो गया था। शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं खालिदा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं। बीएनपी की निर्णायक जीत के पीछे क्या कारण रहा, यह कहना कठिन है: क्या यह सहानुभूति लहर थी, या हसीना-विरोधी भावना, या फिर रहमान की उम्मीदवारी परंतु तथ्य यही है कि अब सत्ता की बागडोर रहमान के हाथ में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिछले 30 वर्षों में यह पहली बार था जब आवामी लीग का चुनाव-चिह्न 'नाव' मतपत्र पर दिखाई नहीं दिया। अतीत के विपरीत जब आवामी लीग ने दो बार संसदीय चुनावों का बहिष्कार किया था, इस बार पार्टी भाग ही नहीं ले सकी क्योंकि उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने 77 सीटें जीतीं। जमात को पाकिस्तान के क़रीब माना जाता है। आवामी लीग के शासनकाल तक जमात और बीएनपी दोनों ही शेख हसीना के शासन का विरोध करने में साथ-साथ थे।

साझा विरोधी अर्थात शेख हसीना के हटते ही दरारें उभरने लगीं और दोनों के रास्ते अलग हो गए। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जिसमें बीएनपी के एक वर्ग ने अपने पूर्व सहयोगी पर धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त जमात अब परछाइयों से बाहर आकर स्वयं को नए रूप में परिभाषित कर रही है, सिर्फ़ सहायक भूमिका निभाने या कनिष्ठ साझेदार बने रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र पहचान और प्रभाव स्थापित करने की कोशिश में।

इस दूरी का असर बीएनपी की छवि पर भी पड़ा है, जिसने स्वयं को आक्रामक के बजाय मध्यमार्गी, उदार और धर्मनिरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया है। वर्तमान परिदृश्य में चारों ओर उत्साह का माहौल है। अलग-अलग दलों के आंकड़ों से इतर, जनता के एकजुट होकर अपनी आवाज़ वापस हासिल करने की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने इस जनादेश को भय की समाप्ति और "धमकी के माहौल से आगे बढ़ने" का संदेश बताया तो अंतरिम सरकार के प्रमुख और बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने कहा कि देश ने "दु:स्वप्न का अंत कर एक नए स्वप्न की शुरुआत" कर दी है।

चुनाव के साथ-साथ यूनुस द्वारा समर्थित संवैधानिक सुधारों के एक पैकेज पर जनमत-संग्रह भी कराया गया, जिसे 'जुलाई चार्टर' कहा जाता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना और प्रधानमंत्री के लिए दो कार्यकाल की सीमा निर्धारित कर भविष्य में किसी भी निरंकुश शासन के उभरने की संभावना को रोकना है। बहुमत मतदाताओं ने इस चार्टर के पक्ष में मतदान किया। चुनावी प्रक्रिया के दौरान शेख हसीना भारत में निर्वासन में

रहीं, क्योंकि एक युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने उनके शासनकाल के दौरान कथित रूप से किए गए मानवता-विरोधी अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जनविद्रोह ने हसीना के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया था। यह आंदोलन व्यापक भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघनों और आर्थिक मंदी को लेकर बढ़ते जनाक्रोश का परिणाम था। इस विद्रोह और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हसीना सरकार की कठोर कार्रवाई में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। इसी अगस्त 2024 में सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। आंदोलन ने शीघ्र ही उग्र रूप ले लिया और हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। तब से वे भारत में रह रही हैं, जबकि बांग्लादेश की यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की ओर से इस पर लगातार आलोचना होती रही है।

चुनाव से कुछ सप्ताह पहले शेख हसीना ने देश के मतदाताओं से चुनाव बहिष्कार की अपील की थी। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने इसे "सुनियोजित प्रहसन" बताते हुए नतीजों को रद्द करने की मांग की। भारत उन पहले देशों में शामिल था जिसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को बधाई दी। हसीना के पतन और भारत द्वारा उन्हें शरण दिए जाने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में गिरावट आई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश और उसके बाद बीएनपी द्वारा तारीक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मोदी को आमंत्रित किया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। मोदी ने एक्स पर लिखा, "मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों वाले दो निकट पड़ोसी देशों के रूप में, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट के जवाब में पार्टी ने लिखा, "हम परस्पर सम्मान, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि के साझा संकल्प के मार्गदर्शन में भारत के साथ अपने बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक संवाद की आशा करते हैं।" मोदी ने कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा," और जोड़ा कि वे रहमान के साथ काम करने के इच्छुक हैं और यहीं पेच भी छिपा है। बांग्लादेश, जिसने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के मामले में हसीना को मृत्युदंड सुनाया है, उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

भारत ने न केवल इस अनुरोध को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, बल्कि हसीना को भारतीय भूमि से चुनावी प्रचार करने की अनुमति भी दी है। चुनाव से ठीक पहले जब उन्होंने अपने देश के मतदाताओं से बहिष्कार की अपील करने के लिए संपर्क साधा तो ढाका ने भारत से यह सवाल उठाया कि हसीना को प्रेस संबोधित करने की अनुमति क्यों दी गई अर्थात उन्हें राजनीतिक एजेंडा चलाने की छूट कैसे मिली। एक बयान में कहा गया, "हम आश्चर्यचकित और स्तब्ध हैं कि भारत ने एक फरार पूर्व प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में सार्वजनिक संबोधन करने दिया और एक सामूहिक हत्यारे को खुलेआम घृणा भाषण देने की अनुमति दी।"

इसके साथ ही तारीक रहमान की "बांग्लादेश फर्स्ट" वाली टिप्पणी जो उन्होंने भारत के साथ संबंधों पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कही, संदेश को और स्पष्ट कर दिया है: भारत दोहरी नीति नहीं अपना सकता, एक ओर शेख हसीना को शरण दे और दूसरी ओर रहमान के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था से हाथ मिलाए।

इस प्रकार औपचारिक संकेतों, जैसे भारत का बधाई संदेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण से इतर वास्तविक परीक्षा तब होगी जब हसीना के प्रत्यर्पण जैसे विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने की बारी आएगी।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

भारत कैसे बनेगा ईवी हब?

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : भारत को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हब बनाने का सपना कैसे होगा पूरा, इस मसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत को ईवी उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाने के नवोन्मेषकों को समर्थन करना ही चाहिए। तभी भारत एक सच्चा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। पर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार के बीच ऑटो सेक्टर की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर अब डीप-टेक स्टार्टअप्स ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र की कंपनियों का कहना है कि घोषित पीएलआई स्कीम का बड़ा हिस्सा अब तक ज़मीन पर उतरना बाकी है। बजट में हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद, वास्तविक वितरण बेहद सीमित रहा है, जिससे नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा।

उद्योग का दावा है कि यदि आवंटित फंड का प्रभावी और संतुलित उपयोग किया जाए तो भारत का ईवी इकोसिस्टम तेज़ी से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति बना सकता है। 2026 की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ईवी स्टार्टअप के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत धन का उपयोग काफी कम रहा। अनुमान के मुताबिक लगभग आवंटित राशि का लगभग10 प्रतिशत ही वितरित हो सका, उसमें भी एडवांस्ड

केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी के क्षेत्र में तो आवंटन लक्ष्य का केवल 2.8 प्रतिशत ही प्रोत्साहन राशि का वितरण हो सका। बजट बढ़ोतरी के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पीएलआई योजना राशि का केवल 12 प्रतिशत ही उपयोग हो पाएगा।

ईवी स्टार्टअप का कहना है कि केवल आवंटन बढ़ाने से इस इंडस्ट्री में तेजी नहीं आएगी। जब तक फंड का एक बड़ा हिस्सा ईवी स्टार्टअप के पास नहीं पहुंचता तब तक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां टिक नहीं पायेंगी। इस समय तो कुछ स्थापित खिलाड़ियों को ही केवल फायदा हो रहा है। मैन्युफैक्चररों का कहना है कि कमर्शियल ईवी सबसे अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं, फिर भी पीएलआई के तहत इस सेकटर को प्रयप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को गति देने के लिए पीएलआई के ढांचे में बदलाव करना जरूरी है। टर्नओवर-आधारित मानकों से हटाकर वास्तविक ईवी बिक्री के आकड़े को आधार बनाया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चररों कहना है कि भारत के ईवी उद्योग का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर स्थायी क्षमता निर्माण है। भारत को ईवी उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाने के नवोन्मेषकों को समर्थन करना ही चाहिए। तभी भारत एक सच्चा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा।

पहाड़ों की गूंज से उगते सूरज तक : मिजोरम और अरुणाचल को कैसे मिला राज्य का दर्जा?

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आज जब हम हिमाचल के सेब खाते हैं, मिजोरम के बांस के जंगलों की तस्वीरें देखते हैं, या अरुणाचल के तवांग मठ में शांति तलाशते हैं, तो हमें उन संघर्षों और समझौतों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने इन राज्यों को जन्म दिया। इन राज्यों का गठन हमें बताता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता को एक सूत्र में पिरोने में ही है। आज कई बार लोग 1971 और 1987 की तारीखों में उलझ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस साल (1987) को अक्सर हिमाचल के साथ जोड़ा जाता है, वह असल में भारत के सुदूर पूर्व (मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश) के उदय का साल था?साल 1987 भारतीय संघवाद के इतिहास में 'स्वर्णिम वर्ष' माना जाता है। यह वह साल था, जब भारत के नक्शे पर दो नए राज्य, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जुड़े। मिजोरम की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 1966 में एक अकाल के बाद वहां विद्रोह की आग भड़क उठी थी। लालडेंगा के नेतृत्व में 'मिजो नेशनल फ्रंट' (एमएनएफ) ने भारत से अलग होने के लिए हथियार उठा लिए थे। दो दशकों तक वहां बारूद की गंध और डर का माहौल रहा। लेकिन, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। 1986 में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। विद्रोही नेता लालडेंगा, जो कभी जंगल में छिपे रहते थे, वे मुख्यधारा में लौटे। समझौते के तहत, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया। यह दुनिया के उन विरले उदाहरणों में से है, जहां एक विद्रोही आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदल गया। लालडेंगा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।

मिजोरम के साथ ही, उसी दिन यानी 20 फरवरी 1987 को एक और इतिहास रचा जा रहा था। वह क्षेत्र जिसे कभी 'नेफा' (उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी) कहा जाता था और जो चीन की सीमा पर भारत का प्रहरी बनकर खड़ा था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश, यानी 'उगते सूरज की भूमि'। सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील इस क्षेत्र को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल का राज्य बनना एक संदेश था कि तवांग की घाटियों से लेकर लोहित नदी के तट तक बसने वाले लोग भारत के अटूट अंग हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी यात्रा भी दिलचस्प और जिक्र करने के लायक है। आजादी के तुरंत बाद, 1948 में 30 छोटी-बड़ी रियासतों को जोड़कर हिमाचल बना तो दिया गया, लेकिन इसे 'केंद्र-शासित प्रदेश' का दर्जा मिला। दिल्ली में बैठे नौकरशाहों को लगता था कि पहाड़ के लोग अपना शासन खुद चलाने में सक्षम नहीं हैं।

-आईएएनएस

एआई : चुनौतियां भी कम नहीं

आकाश चोपड़ा

नई दिल्ली में दुनियाभर के दिग्गज एआई के ढांचे को सुरक्षित बनाने के लिए विचार मंथन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं भी गहरी हो रही हैं। आज के दौर में डीपफेक के खतरे सामने आ रहे हैं। एआई से फर्जी तस्वीरें, फर्जी वीडियो दिखाई दे रहे हैं। अब तो वकील भी एआई से तैयार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि याचिकाएं ऐसे तैयार नहीं होती। दायर की गई याचिकाओं में कुछ ऐसे संदर्भ थे जो कभी हुए ही नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आर्टिफिशियल मॉडल जैसे की चैट जीपीटी की मदद से नकली आधार और पैन कार्ड भी बनाये जा सकते हैं। तकनीक के दोहरे दौर से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उभर रहा है। कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो ऐसी प्रवृत्ति को उजागर करती हैं जहां दुश्मन देश और आपराधिक आतंकवादी संगठन दोनों ही एआई के दोहरे उपयोग की क्षमताओं को फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि क्या एआई के दौर में हर चीज अपनी मौलिकता को खो देगी। चारों ओर नकली चीजों को बोलबाला तो नहीं हो जाएगा। चाहे वे दस्तावेज हो, कला हो, साहित्य हो। एआई से तो व्यक्तियों की भी प्रभावी नकल की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखे अगर कक्षाओं में एआई की उपस्थिति है तो फिर परीक्षा केन्द्रों का क्या होगा। क्या भविष्य में छात्रों को परीक्षा केन्द्र में कैलकुलेटर या अन्य एआई उपकरण ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सच तो यह है कि बच्चों के बुद्धि कौशल का क्या होगा, उनके मानसिक विकास को क्या होगा। क्या उनकी बौद्धिक क्षमता मंद तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे सवाल समाज के सामने हैं।

आधुनिक तकनीक के रूप में मोबाइल या स्मार्टफोन जितना उपयोगी साबित हुआ है, उसके समांतर अब उसके ऐसे खमियाजे भी सामने आ रहे हैं जो कई बार व्यक्ति को बहुस्तरीय मानसिक परेशानियों के संजाल में फंसा लेते हैं, तो कभी वह उस चक्र में फंस कर अपनी जान भी गंवा बैठता है। स्मार्टफोन में कोई गेम खेलते हुए बच्चों के आत्महत्या कर लेने की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं।

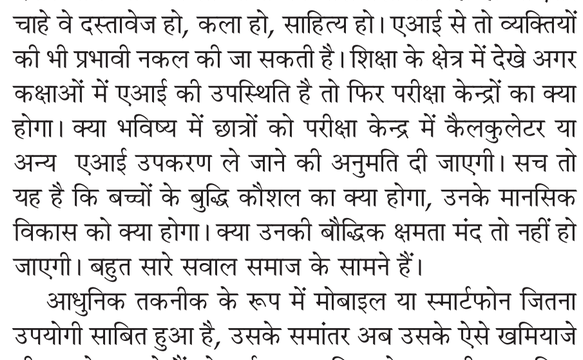

हाल के दिनों में जब से एआई के बढ़ते दायरे और इसके असर की बात होने लगी है, तब से इसे भविष्य में नौकरियों का सृजन करने का औजार भी बताया गया है। दूसरी ओर, एआई के फैलते पांव के समांतर रोजगार पर इसके व्यापक प्रभाव और खतरों को लेकर आशंकाएं भी जताई गई हैं। दिल्ली के सम्मेलन में एक

उद्देश्य एआई से रोजगार, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर और उसके खतरों को कम करने के लिए ठोस उपायों तथा प्रयासों पर भी चर्चा करना रहा। रक्षा और कारोबार के विभिन्न क्षेत्र में नए स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। जाहिर है, विकास के नए मानक रचने और आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एआई के मामले में हर वक्त अद्यतन रहने की जरूरत होगी। मगर रोजगार के अवसरों के सिकुड़ने से लेकर कई स्तर पर लोगों की जिंदगी से जुड़े बहुस्तरीय जोखिम के जैसे मामले तेजी से सामने आने लगे हैं, उसका हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह जगजाहिर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा कितने बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। हाथ में मौजूद स्मार्टफोन अब केवल तस्वीरें संपादित करके सोशल मीडिया के मंचों पर सुर्खियां हासिल करने का जरिया भर नहीं है। चिकित्सा जगत में एआई का उपयोग बीमारी की पहचान से लेकर इलाज में भी होने लगा है। अपराध पर लगाम लगाने के मामले में एआई की उपयोगिता साबित हो चुकी है।

शिक्षा जगत से लेकर तकनीक के मामले में जितनी तेज रफ्तार से नवाचार का प्रयोग हुआ है, सभी जरूरी क्षेत्रों में एआई का दायरा फैला है, उसमें इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि इसकी संभावनाओं और उम्मीदों के साथ-साथ इससे जुड़ी आशंकाओं पर भी विचार हो। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विकास के किसी स्वरूप से अंतिम तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं और कोई भी तकनीक इसी कसौटी पर देखी जाएगी कि उससे मनुष्य का कितना समग्र हित सुनिश्चित हो सका और दुनिया की ज्यादातर आबादी के लिए वह कितनी उपयोगी साबित हुई।

मगर इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर संक्षिप्त वीडियो या रील बना कर प्रसारित करने की प्रवृत्ति जिस तेजी से बढ़ती देखी जा रही है उसने एक नई चिंता पैदा की है। हालत यह है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात या किसी मनोरंजक गतिविधि को पहुंचाने के लिए लोग अजीबोगरीब तरीके भी अपनाने लगे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित छवियों को अब प्रमुखता से लेबल किया जाना अनिवार्य है। अक्तूबर में मसौदा नियमों के जारी होने के बाद से इस आदेश में कुछ सुधार हुए हैं: अब इस तरह के खुलासे के लिए कोई निश्चित आकार निर्धारित नहीं किया गया है और न ही यह किसी भी एआई-जनित छवि पर लागू होता है जो वास्तविक होने का दावा नहीं करती है। एआई-जनित छवियों ने उपयोगकर्ताओं के फीड को भर दिया है और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ये छवियां वास्तविक नहीं हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री को घोषित करने की आवश्यकता स्वागत योग्य है। कृत्रिम छवियों को बनाने की तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए सरकार को नियमों के उन हिस्सों पर फिर से विचार करना होगा जो प्लेटफार्मों द्वारा कृत्रिम सामग्री का सक्रिय रूप से पता लगाने को अनिवार्य बनाते हैं। आखिरकार, हालांकि तकनीकी प्लेटफार्म आमतौर पर कृत्रिम मीडिया का स्वचालित रूप से पता लगाने में सक्षम होते हैं लेकिन इन पहचान तंत्रों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है जिससे यह क्षमता लगातार चुनौती का सामना कर रही है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में दुनियाभर में अभी सबसे ज्यादा जोर आधुनिक तकनीकों के विकास और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नवाचार के प्रयोग पर दिया जा रहा है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रेरणा

आशावादी बने रहिए...क्योंकि यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। - **हेलन केलर**

संपादकीय

अपनी क्षमताओं से चौंकाया है हमारे 'सर्वम्' एआई ने

भारत सरकार द्वारा वित्त, तकनीकी और डेटा के स्तर पर पोषित निजी उपक्रम द्वारा बनाया गया सर्वम् एआई चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड से कई मायनों में बेहतर साबित हुआ है। इस एआई को सरकार ने न केवल अपनी टेक्निकल क्षमता के प्रदर्शन के लिए एआई समिट में रखा बल्कि इसे गवर्नेंस की रीढ़ भी बनाने जा रही है। हिंग्लिश, स्थानीय भाषाओं और निम्न वर्ग की बोलचाल, देशज जरूरतों, 22 भारतीय भाषाओं और हिंदी-अंग्रेजी बोलने की क्षेत्र-विशेष की शैली पर बुलबुल-वी-3 (टेक्स्ट-टु-स्पीच) मॉडल पर प्रशिक्षित सर्वम् सभी वर्गों के लिए उपयोगी होगा। गांव की महिलाएं भी इसे उसी सहजता से इस्तेमाल कर सकेंगी, जैसे कोई अंग्रेजी बोलने वाला। भारत सरकार ने इस एप को विकसित करने के लिए इस उपक्रम को अपने हजारों जीपीयू का नेटवर्क उपलब्ध कराया और ओडिशा और तमिल सरकार ने ट्रेनिंग के लिए डेटा और रेस्पॉन्स के जरिये आगे बढ़ाया। चूंकि भारत में हिंदी-अंग्रेजी शब्दों का सम्मिलित प्रयोग होता है और उसमें स्थानीय और देशज शब्द भी शामिल होते हैं, लिहाजा विदेशी एआई मॉडल्स के मुकाबले इसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है। जबकि कई बार चैटजीपीटी या जेमिनी उन शब्दों को न समझ कर अर्थ का अनर्थ कर देता है। सॉवरेन एआई होने के कारण सरकार मानती है सर्वम् के प्रयोग से देश का डेटा भी लीक नहीं होगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

हम अपने बच्चों को तभी बचा पाएंगे जब खुद सावधान होंगे

दुनियाभर के बाजार आज एआई में जमकर निवेश कर रहे हैं। दीवानों ने दर्द को ही दवा बना लिया है। हर बात का निदान एआई में ढूंढा जा रहा है। हमारे यहां दो स्तरों पर एआई से जुड़कर काम होना चाहिए- एक देश के स्तर पर, दूसरा परिवार के लिए। एआई से विकास तो हो, लेकिन ये तकनीक देश से काम को कम ना कर दे, वरना काम करने वाले और बेरोजगार हो जाएंगे। एआई को लेकर अमेरिका और चीन में जमकर मुकाबला चल रहा है। इन दोनों ही देशों में परिवार का ढांचा बिखरा हुआ है। तो हमें एआई से बाजार में फायदा हो, ऐसा तो सोचना है, लेकिन परिवार की सुरक्षा पर भी चिंतन करना है। पूरी दुनिया के देश शायद परिवार संस्था को लेकर इतने गम्भीर ना हों, पर हम भारतीयों को चाहिए कि एआई की चपेट में हमारी गृहस्थी ना आ जाए, दाम्पत्य जीवन बिखर ना जाए। क्योंकि हम एआई से बच्चों को तब बचा पाएंगे, जब माता-पिता खुद सावधान हों। आज तो बारूद के ढेर की हिफाजत चिंगारी के हाथ में दे दी गई, ऐसा दृश्य देखने में आ रहा है। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • एनसीपी में विलय की प्रक्रिया थम गई है

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी मंथन से किसे फायदा होगा?

राजनीति

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों को ऐसे बदल दिया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। फिलहाल तो इसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों धड़ों की विलय की प्रक्रिया को रोक दिया है। इस पर काम चल रहा था और 12 फरवरी को इसकी घोषणा होने वाली थी। हालांकि किसी ने भी यह सार्वजनिक नहीं किया था कि इसकी शर्तें क्या होतीं।

क्या अविभाजित एनसीपी एनडीए के साथ रहती? शरद पवार ने बार-बार कहा है कि वे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और यह मुश्किल ही था कि अजित पवार या उनकी पार्टी के वे लोग जो मुम्बई में सरकार में हैं, या जिनके सिर पर ईडी/सीबीआई की तलवार लटक रही थी, वे महायुति से अलग होना चाहते। यह सम्भव था कि अविभाजित एनसीपी एनडीए के साथ बनी रहती, जिसमें सुप्रिया सुले को बड़ी भूमिका दी जाती और सीनियर पवार रिटायर हो जाते। लेकिन अजित पवार के धड़े वाली एनसीपी के सीनियर नेताओं- प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे- जो सभी गैर-मराठा हैं- ने मीटिंग को पहले ही टाल दिया।

अजित पवार के धड़े वाली एनसीपी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सम्पर्क में थे और वे सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमत्री के तौर पर तुरंत शपथ दिलाने के लिए मान गए थे। सच यह है कि न तो अजित पवार का करीबी परिवार और न ही उनके सीनियर साथी पार्टी को शरद पवार को सौंपना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शरद पवार पार्टी का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। अजित दादा की मौजूदगी और पार्टी पर उनकी पकड़ के बिना वे कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन एनसीपी को अजित पवार की मृत्यु के बाद मिली हमदर्दी का फायदा मिला। क्योंकि इसके बाद हुए जिला परिषद् चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का प्रदर्शन खराब रहा। 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में भी अजित दादा की एनसीपी शरद पवार की एनसीपी से ज्यादा ताकतवर साबित हुई थी।

इधर एक और महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि भाजपा ने रितु तावड़े को बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के रूप में नियुक्त कर दिया। शिवसेना के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर बने। एकनाथ शिंदे मेयर पद के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहां भी नंबर दो की पोजिशन से ही संतोष करना पड़ा।

महाराष्ट्र की राजनीति में आज चल रहे इस मंथन से किसे फायदा होगा? एनसीपी के टूटने, अजित पवार की असामयिक मृत्यु, शरद पवार के कमजोर पड़ने और कांग्रेस की लगातार गिरावट के साथ मराठा खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। मराठा वोटों (35%) पर कब्जा करने की होड़ लगी है। एनसीपी के दोनों गुटों के अलावा एकनाथ शिंदे- जो खुद मराठा हैं और जिन्हें ठाणे जैसे शहरी इलाकों से बड़ा समर्थन मिलता है- अजित दादा की मृत्यु के बाद मराठों के साथ नए तरीके से खड़े हो सकते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस फिर से खुद को मजबूत कर पाएगी? अभी तक तो हालात देवेंद्र फडणवीस के हित में रहे हैं और संघ फडणवीस के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

फडणवीस ने बिना समय गंवाए सुनेत्रा पवार को अपनी सरकार में शामिल कर लिया और जाहिर है कि उन्हें इसके लिए दिल्ली से भी मंजूरी मिल गई थी। इससे उन्हें एकनाथ शिंदे के दबाव को कम करने में

क्या 6 बार के डिप्टी सीएम अजित दादा की मृत्यु और 85 साल के शरद पवार की घटती ताकत महाराष्ट्र की राजनीति के उस पवार साम्राज्य के कमजोर होने का संकेत है, जिसने आधी सदी तक उसकी सियासत पर असर डाला?

मदद मिली। फडणवीस ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा है, जो पहले अजित दादा के पास था। इसे किसी भी ऐसे कद्दावर नेता के लिए रिजर्व में रखा जा सकता है, जो शरद पवार की एनसीपी से एनडीए में आने का फैसला कर सकता है।

जिस सूझबूझ से फडणवीस ने हाल के घटनाक्रमों को संभाला, उसने उन्हें मोदी के बाद के दौर के लिए तैयार हो रहे नेताओं की सूची में एक पायदान ऊपर पहुंचा दिया है। क्या 6 बार के डिप्टी सीएम अजित दादा की मौत और 85 साल के शरद पवार की घटती ताकत महाराष्ट्र की राजनीति के उस पवार साम्राज्य के कमजोर होने का संकेत है, जिसने आधी सदी तक राज्य पर राज किया या उस पर असर डाला? पवार युग 1977 में शरद पवार के उदय के साथ शुरू हुआ, जो तीन बार मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के पदों तक पहुंचे। वे चाहे सत्ता में हों या बाहर, उन्हें दरकिनार नहीं जा सकता था। उन्हें अब भी एक ऐसे निष्णात राजनेता के तौर पर देखा जाता है, जो राज्य को बखूबी जानते हैं और स्टेट की मशीनरी कैसे काम करती है, इसकी बारीकियों से भलीभांति परिचित हैं। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

दूरदृष्टि • तकनीक का व्यावहारिक उपयोग जरूरी

एआई की मदद से मुकदमों का बोझ क्यों नहीं घटाते हम?

न्यायिक

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
viraggupta@hotmail.com

देश में एआई की आंधी चल रही है। यह एक समस्या साबित होगी या विकसित भारत का शंखनाद, इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। फिलहाल 4 बिंदुओं के जरिए न्यायिक व्यवस्था में एआई से जुड़ी चुनौतियों व विरोधाभासों का मूल्यांकन किया जा सकता है :

1. ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में एआई और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 53.57 करोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शोध और अनुवाद के लिए कई एआई टूल बनाए गए हैं। लेकिन 99 फीसदी से ज्यादा मुकदमे हाईकोर्ट और जिला अदालतों में लंबित हैं। वहां एआई के माध्यम से पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन और वादकारों को जोड़कर जमानत से जुड़े लाखों मामलों में जल्द फैसला हो सकता है। एआई के इस्तेमाल से चेक बाउंसिंग और ट्रैफिक चालान जैसे करोड़ों मुकदमों के त्वरित निस्तारण से अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ कम हो सकता है। अदालतों में एआई टूल के इस्तेमाल से मुकदमों की कार्रवाई की ट्रांसस्क्रिप्ट बने तो तारीख पे तारीख का गोरखधंधा कम हो सकता है। लेकिन आम जनता के लिए जल्द और सही न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने में एआई का व्यावहारिक इस्तेमाल नहीं होना चिंताजनक है।

2. विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया में मदद और केस मैनेजमेंट के माध्यम से एआई न्याय की रफ्तार बढ़ा सकता है। लेकिन यह जजों के विवेक और मानवीय भावनाओं की जगह नहीं ले सकता। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की जिला अदालत के जज ने एआई के माध्यम से लिखे माफीनामा को अस्वीकार करते हुए कहा कि उसमें संवेदना और मानवीय भावों का अभाव है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस गवई ने कहा था कि चैटजीपीटी के इस्तेमाल से संवैधानिक व्यवस्था के सामने बड़े संकट आ रहे हैं। पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एआई से बनाए गए काल्पनिक मुकदमे के उल्लेख पर 50 हजार का जुर्माना लगाया था। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने नए सिरे से इस मर्ज पर चिंता जाहिर की है। वकीलों की ड्राफ्टिंग और जजों के फैसलों में एआई के गलत इस्तेमाल से मुकदमेबाजी को जटिल बनाया जा रहा है।

3. लोकसभा में कानून मंत्री ने दिसंबर 2025 में कहा था कि न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल से एल्गोरिदम बायस, अनुवाद की समस्या और डेटा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ई-कमेटी विचार कर रही है। उसके पहले मार्च 2025 में मंत्री ने संसद में कहा था कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से फैसलों का 18 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। पिछले दिसंबर में जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि एआई के गलत इस्तेमाल से न्यायिक प्रशासन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के लिए सबूत के तौर पर सरकार ने तीन मिनट के भाषण का आठ मिनट में अनुवाद पेश किया है। जस्टिस अरविंद कुमार और वराले की पीठ ने कहा कि एआई के दौर में अनुवाद के मामलों में कम से कम 98 फीसदी सटीकता जरूरी है। जजों के अनुसार सरकार किसी ऐसी चीज पर भरोसा कर रही है, जो वास्तविक नहीं है।

4. सुनवाई और प्रसारण में वॉट्सएप और जूम जैसे एप्स का इस्तेमाल होना गैरकानूनी होने के साथ न्यायिक व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप भी है। गृह मंत्रालय के नवीनतम आदेश के अनुसार वर्गीकृत जानकारी को मीडिया से साझा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गोपनीयता कानून के तहत सख्त आपराधिक कार्रवाई होगी। लेकिन डिजिटल और एआई कंपनियों के साथ जनता और सरकार के डेटा को गैरकानूनी और संगठित तरीके से साझा करने के खिलाफ कारवाई नहीं हो रही। निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के नौ साल पुराने फैसले को लागू करवाने के बजाय ठंडे बस्ते में कैद डेटा सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालतों में सुनवाई होना एक अलग ही प्रहसन है।

अदालतों में एआई टूल के इस्तेमाल से मुकदमों की कार्रवाई की ट्रांसस्क्रिप्ट बने तो तारीख पे तारीख का गोरखधंधा कम हो सकता है। लेकिन आम जनता के हित में एआई का व्यावहारिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चिंताजनक है।

एआई के माध्यम से 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' का लक्ष्य सधे तो अच्छा है। लेकिन एआई क्रांति की आड़ में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य हो गया तो संविधान की सार्वभौमिकता और आत्मनिर्भर भारत के सामने खतरों की सुनामी आ सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | भारत की मशहूर कॉफी चेन

7600 करोड़ का कर्ज, मालिक ने आत्महत्या की दिवालिया होने वाली थी, अब मुनाफे में लौटी सीसीडी

सबक क्यों- मालकिन मालविका हेगड़े ने विपरीत परिस्थितियों में हार मानने के बजाय कंपनी का कर्ज घटाया, उसे दोबारा खड़ा किया।

एक समय था जब लोग अक्सर कहते थे- चलो सीसीडी चलते हैं। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे। एक ऐसी जगह जहां लोग मिलने के लिए इकट्ठे होते। छोटे शहर में जब पहला सीसीडी खुलता तो लोगों के लिए यह किसी इवेंट से कम नहीं होता था। सीसीडी की 2019 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार 240 से ज्यादा शहरों में इसके 1,752 स्टोर थे। यह देश की नंबर-1 वन कॉफी चेन थी।

2016 में आईआईटी कानपुर की आंत्रप्रेन्योरशिप समिट के दौरान सीसीडी के मालिक वी.जी. सिद्धार्थ ने मंच को संबोधित करते हुए कहा था 'अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, तो शायद कभी सच्ची कमाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सीमा के बाद, पैसा केवल एक संख्या बनकर रह जाता है। असल में हमें आगे बढ़ाने वाली चीज पैसा नहीं, बल्कि काम के प्रति जुनून और प्रेम है'।, हालांकि रणनीतिक रूप से वे कमजोर पड़ गए। एक समय सीसीडी पर 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। खुद को डूबता देख उन्होंने 2019 में आत्महत्या कर ली। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ये उदाहरण बताते हैं कि बिना योजनाओं के विस्तार और अव्यावहारिक जुनून भी नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बढ़ने के लिए खुद की क्षमताओं को जानना जरूरी है। ऐसे में आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी कैफे कॉफी डे की।

बेंगलुरु स्थित सीसीडी का एक कैफे।

1060 करोड़ रुपए रेवेन्यू था कंपनी का मार्च 2025 तक।

55 हजार से अधिक कॉफी वेंडिंग मशीनें इंस्टॉल्ड हैं होटलों और ऑफिसों में।

435 से अधिक कैफे चल रहे हैं सीसीडी के 141 भारतीय शहरों में।

20 हजार एकड़ जमीन है कंपनी के पास, जिसमें वह कॉफी उगाती है।

ऐसे संकट में फंसी सीसीडी

❶ **बिना सोचे-समझे विस्तार-** सिद्धार्थ हर शहर, में सीसीडी खोलना चाहते थे। कई आउटलेट्स ऐसे थे जो कभी मुनाफे में नहीं आए। इससे कंपनी का कैश खत्म होने लगा और मुनाफ पर से ध्यान हट गया।।

❷ **फोकस खोना :** कॉफी किंग होने के बावजूद सिद्धार्थ ने रियल स्टेट, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया। इन सब में लगा निवेश फंस गया।

❸ **बेहिसाब कर्ज :** विस्तार के लिए कंपनी ने बेहिसाब कर्ज लिया। बैंकों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उठाया गया। जब बिजनेस से पैसा नहीं आया, तो पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया। यह एक तरह का चक्रव्यूह बन गया।

❹ **प्रतिस्पर्धा से भी बढ़ा दबाव :** 2012 के बाद देश में स्टारबक्स आई। 'चायोस' और 'चाय पॉइंट' जैसे स्टार्टअप्स ने भी जगह बनाई। सीसीडी न 'प्रीमियम' रहा और न 'सस्ता'। यह बीच में फंसकर रह गया।

इस तरह हर बार की वापसी

❶ **मालविका हेगड़े की लीडरशिप-** सिद्धार्थ की पत्नी मालविका ने पीछे हटने की बजाय कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने चिट्ठी में कर्मचारियों को लिखा- मैं इस कर्ज को घटाऊंगी, यह मेरा मिशन है।

❷ **घाटे वाले स्टोर बंद करना :** मालविका ने घाटे वाले स्टोर बंद किए। 2019 में 1700 से अधिक स्टोर थे। 2024-25 में 450 के करीब स्टोर बचे।

❸ **नॉन-कोर एसेट की बिक्री-** उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए कड़े कदम उठाए। माइंडट्री स्टेक, ग्लोबल विलेज टेक पार्क और अन्य स्टेक बेचे। ब्लैक स्टोन और श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट से पार्टनरशिप की। इससे करीब 6500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया।

❹ **वेंडिंग मशीन पर फोकस :** कंपनी ने देखा कि ऑफिसों में लगी वेंडिंग मशीनें सबसे ज्यादा मार्जिन देती हैं। इसके बाद उन्होंने इस पर फोकस बढ़ाया। आज करीब 50 हजार लोकेशंस पर उनकी मशीनें हैं।

कॉफी पीने की जगह के रूप में शुरू हुए थे सीसीडी के कैफे

शुरुआत : कॉफी को कल्चर बनाने के लिए शुरू हुआ सीसीडी

कर्नाटक के चिकमंगलूर में जन्मे वी.जी. सिद्धार्थ ने 1993 में पत्नी मालविका हेगड़े के परिवार के कॉफी एस्टेट 'अमरल्योत्तमेन्नु गुंडिया' से प्रेरणा लेकर कॉफी चेन शुरू की। सिद्धार्थ ने सोचा क्यों न भारत में कॉफी को एक कैजुअल कल्चर बनाया जाए। उन्होंने 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर पहला आउटलेट खोला, जहां युवा कॉफी पीने आते। नाम रखा 'कैफे कॉफी डे'।

गंभीर संकट : 2019-21 का दौर रहा सबसे ज्यादा खतरनाक

जुलाई 2019 से मार्च 2021 तक का समय कंपनी के लिए बेहद संकट वाला रहा। जुलाई में सिद्धार्थ की मृत्यु और फिर ठीक उसके बाद कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया। कैफे बंद हो गए। रेवेन्यू करीब शून्य हो गया। इनकम टैक्स केस, बैंकों के नोटिस आने लगे। 2020 में इंडसइंड बैंक ने दिवालिया पिटीशन दायर की। कंपनी करीब-करीब दिवालिया होने की कगार पर थी।

ऐसे पड़ा नाम : आसान लॉजिक था। ऐसी जगह जो कॉफी के लिए हो और जहां लोग दिन बिता सकें। 'A Coffee Day, बाद में यह Cafe Coffee Day बना।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : स्टारबक्स, मैक्कैफे, थर्ड वेव कॉफी, ब्लू टोकिया, बरिस्ता और अब तेजी से बढ़ते टी-कैफे इसके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

141 शहरों में कैफे, 3858 कर्मचारी

सितंबर 2025 तक 141 शहरों में कंपनी के 435 से अधिक कैफे संचालित हो रहे थे। 2024-25 तक कंपनी में करीब 3,858 कर्मचारी थे। वर्तमान में कंपनी की 55 हजार से अधिक कॉफी वेंडिंग मशीनें होटलों, कार्यालयों में इंस्टॉल्ड हैं, जो उसकी कमाई का बड़ा जरिया हैं। इसके अलावा कंपनी के पास करीब 20 हजार एकड़ कॉफी प्रोडक्शन से जुड़ी जमीन है। 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी तिमाही में सीसीडी को करीब 56 करोड़ रु. का लाभ हुआ है।

पीपुल भास्कर | तारिक रहमान | बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री

17 वर्ष तक यूट्यूब-स्काइप से पार्टी चलाई, यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट हैं, 'सबसे छोटे युद्धबंदी' कहे जाते हैं रहमान

चर्चा में क्यों- करीब 17 साल तक परिवार सहित ब्रिटेन में निर्वासित रहने के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं।

2000 का दशक। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए देशभर में सम्मेलन कर रहे थे। तभी उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने करीब 18 हजार एक्टिव कार्यकर्ताओं को चिट्ठियां लिखीं। हर चिट्ठी में कार्यकर्ताओं से जुड़ी समस्या का जिक्र और उसके समाधान की बात लिखी होती थी। उनके इस कदम ने पार्टी में उनकी छवि जमीनी कार्यकर्ताओं से निजी संपर्क रखने वाले एक नेता की बना दी।

तारिक रहमान मानसिक रूप से बड़े मजबूत माने जाते हैं। 2007-08 में जब उन्हें जेल में डाला गया और कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया तो उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मैं 4-5 साल की उम्र में सेना की कैद देख चुका हूं, ये मुझे तोड़ नहीं पाएंगे।

बांग्लादेश छोड़कर 17 साल तक लंदन में निर्वासित रहने के दौरान तारिक ने अपने व्यवहार में काफी बदलाव किया। उनके साथ वक्त बिताने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने 'बोलना कम और सुनना ज्यादा' शुरू कर दिया है। उनकी बिजनेस और अर्थव्यवस्था की समझ अच्छी है। बिजनेस के लिए उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वर्तमान में फिर वे काफी पढ़ने लगे हैं। खासकर लोकतांत्रिक विकास, कूटनीति और राजनीति से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं। इसी विषय पर उन्होंने काफी रिसर्च और लेखन का काम भी किया है। खुद को फिट रखने के लिए मुख्य रूप से वॉक करते हैं।

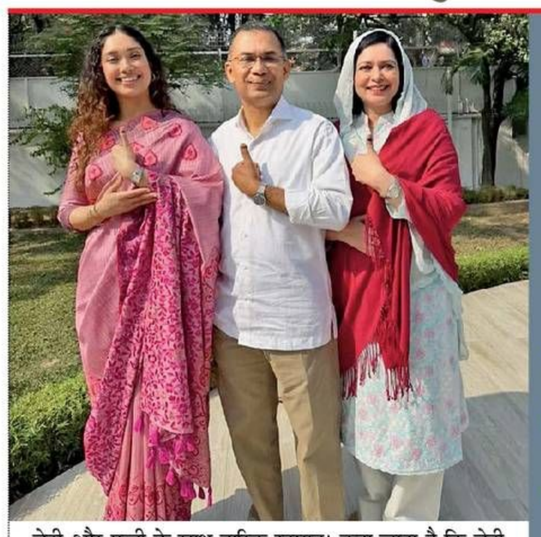

बेटी और पत्नी के साथ तारिक रहमान। कहा जाता है कि बेटी जायमा रहमान की उनकी रणनीतियों में महती भूमिका रहती है।

यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर रहमान ने टेक्सटाइल्स, शिपिंग और कृषि उत्पादों का अपना बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस और अर्थव्यवस्था में उनकी रुचि आज भी उनके काम में झलकती है।

जन्म : 20 नवंबर 1965, ढाका, पूर्वी पाकिस्तान।
शिक्षा : आदमजी कैन्टोनमेंट कॉलेज ढाका से 12वीं।
संपत्ति : करीब 1.48 करोड़ रु. (चुनावी हलफनामे के अनुसार)

परिवार

पिता राष्ट्रपति, मां 3 बार बांग्लादेश की पीएम रहीं

तारिक के पिता जिया उर रहमान पाकिस्तानी सेना में अधिकारी थे, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1971 में पाकिस्तान में हुए मुक्ति युद्ध के दौरान वे परिवार सहित हिरासत में रहे। तब उनकी उम्र करीब 5 साल थी। पार्टी उन्हें 'सबसे छोटा युद्धबंदी' मानती है। 1981 में सैन्य तख्तापलट में पिता की हत्या के बाद मां खालिदा जिया पीएम बनीं। वे 3 बार पीएम रहीं।

विवाह

पत्नी बांग्लादेश नेवी के पूर्व अधिकारी की बेटी

तारिक का विवाह बांग्लादेश नेवी के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल महबूब अली खान की सबसे छोटी बेटी जुबैदा से हुआ है। जुबैदा एक हृदयरोग विशेषज्ञ हैं। शादी के बाद जुबैदा बांग्लादेश सिविल सर्विस में चिकित्सक बनीं, लेकिन 2014 में अवामी लीग सरकार ने अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से हटा दिया था। दोनों की एक बेटी है जायमा रहमान।

करियर

पार्टी के प्राथमिक सदस्य से पीएम तक

1988 में बोरा जिले के गबतली से बीएनपी के प्राथमिक सदस्य बने। 2001 में पार्टी की जीत के बाद सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। 2007 में सैन्य समर्थित सरकार में गिरफ्तार हुए। 18 महीने जेल में रहे। 2008 में उपचार के लिए लंदन गए और वहीं बस गए। 2018 में मां खालिदा जिया को जेल के बाद कार्यकारी अध्यक्ष और अब प्रधानमंत्री बने हैं।

रोचक : लोकतंत्र और कूटनीति पर कई रिसर्च पेपर और विजन डॉक्यूमेंट लिख चुके हैं

खास : बांग्लादेश लौटते ही वहां की मिट्टी को मुट्ठी में भर लिया

- 25 दिसंबर 2025 को लंदन से लौटते ही एयरपोर्ट पर नंगे पैर मिट्टी पर चले। इसके बाद मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर अपने पास रख ली।
- 17 वर्षों तक निर्वासन के दौरान स्काइप और यूट्यूब से पार्टी गतिविधियों को संचालित किया।
- बचपन में परिवार के लोग उन्हें 'पिनु' और छोटे भाई को 'कोको' नाम से बुलाते थे।

उपलब्धि : लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के लिए स्कीम चलाई

- लोकतंत्र और कूटनीति पर कई रिसर्च पेपर और विजन डॉक्यूमेंट लिखे हैं।
- 2001-2006 के दौरान लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के लिए विशेष स्कॉलरशिप स्कीम चलाई।
- 2000 के दशक में बांग्लादेश के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड में पदें के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विवाद : शेख हसीना पर ग्रेनेड से हमले कराने का आरोप

- बांग्लादेशी मीडिया और विपक्ष उन्हें 'मिस्टर 10 पर्सेंट' कहता था। आरोप है कि सरकारी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में वे 10% कमीशन लेते थे।
- 2004 में पूर्व पीएम शेख हसीना पर हुए ग्रेनेड हमले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था।
- बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर भी विवादित बयान दे चुके हैं।

http://t.me/AllNewspapersPdf

एआइ समिट में भारत

भारत में एआइ के ढांचागत विकास और इस क्षेत्र में उसके सिरमौर बनने के सरकार के सपने को पूरा करने की दिशा में इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट-2026 मील का पत्थर साबित हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा भी कि इस समिट का भारत में होना पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसी दिग्गज टेक कंपनियां न सिर्फ एआइ के क्षेत्र में भारत को बड़े केंद्र के रूप में देख रही हैं, बल्कि इन्होंने भारत में निवेश के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. गूगल के सीइओ सुंदर पिचाई ने भारत और अमेरिका के बीच एआइ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नये सब-सी केबल रूट की घोषणा की. साथ ही, उन्होंने दो करोड़ सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और 1.1 करोड़ छात्रों को सहायता देने की भी घोषणा की. वर्ष 2025 के अंत तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एमेजॉन ने भारत में 67.5 अरब डालर का निवेश किया था. भारत का विशाल और विविध बाजार, किफायती इंजीनियरिंग प्रतिभा, अंग्रेजी में कुशल कार्यबल, डाटा संप्रभुता और डिजिटल ढांचा एआइ के लिए आकर्षक स्थान बनाता है. देश की 65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, और यही जनसांख्यिकीय शक्ति देश की डिजिटल और नवाचार रणनीति का आधार बन रही है. करीब 1.2 अरब डॉलर के इंडिया एआइ मिशन के तहत सरकार ने बड़ी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना शुरू की है, जिसमें कंप्यूटर क्षमता बढ़ाने, डाटा और तकनीकी संसाधनों तक सस्ती पहुंच देने पर जोर है, ताकि छात्र, स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ता भी एआइ के विकास में सहभागी बन सकें. बजट में मुंबई स्थित आइआइसीटी के सहयोग से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एआइ आधारित कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गयी, जिससे लाखों युवाओं को भविष्य के कौशल मिल सकेंगे. भारत में एआइ कौशल की पहुंच वैश्विक औसत से अधिक तो है ही, साथ ही अब आधे से अधिक स्टार्टअप महानगरों से बाहर उभर रहे हैं. समिट में युवाओं और स्टार्टअप्स की खास भूमिका दिखी. लाइव प्रदर्शन समाधान के जरिये युवा नवाचार को वैश्विक पहचान मिली, तो युवाओं और महिला उद्यमियों ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में एआइ आधारित समाधान पेश किये. जाहिर है, यह समिट वैश्विक एआइ एजेंडे को आकार देने के एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है.

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट में लाइव प्रदर्शन समाधान के जरिये हमारे युवा नवाचार को वैश्विक पहचान मिली, तो युवाओं और महिला उद्यमियों ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में एआइ आधारित समाधान पेश किये.

संसद में गतिरोध बने रहना चिंता का विषय

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

संसद के कामकाज में आयी गिरावट हमारी सामूहिक चिंता का कारण है. इस बार बजट सत्र के पहले चरण में जो हुआ, वह इससे अलग नहीं था. इसने एक बार फिर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भरोसे की कमी को रेखांकित किया, जिस कारण संसद ही नहीं चल पायी. यही नहीं, इस बार संसद की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं- यानी नेता प्रतिपक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष की छवि भी प्रभावित हुई. संसद को सुचारु तरीके से चलाने की जिम्मेदारी बेशक सत्तापक्ष की है. लेकिन यह विपक्ष के सहयोग के बगैर संभव नहीं है.

वर्षों से संसद के कामकाज में आयी गिरावट हमारी सामूहिक चिंता का कारण बनती जा रही है. कई बार बिना चर्चा के ही संसद में बिल पारित हो जाते हैं. संसद चल रही होती है, और माननीय सदस्यगण अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाते हैं. वे एक-दूसरे पर कागज फेंकते हैं. संसदीय कार्यवाही कई दिनों तक रुक जाती है और पीठासीन अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप लगाये जाते हैं. ये सब अब संसदीय आचरण का हिस्सा बन चुके हैं. इसके बावजूद बजट सत्र के पहले चरण में जो हुआ, वह बेहद चिंताजनक है. विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. भले ही अध्यक्ष को हटाने के लिए जरूरी संख्याबल विपक्ष के पास न हो, लेकिन इससे लोकसभा अध्यक्ष की छवि प्रभावित होती है. वर्षों के संसदीय इतिहास में विपक्ष ने यह कदम उठाने के बारे में सोचा न था. उतना ही अभूतपूर्व वह कदम था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से रोका. उनके पास ठोस सूचना थी कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, वहां कांग्रेस की महिला सांसद बाधा पहुंचाने का काम कर सकती हैं. दूसरे शब्दों में, लोकसभा अध्यक्ष चिंतित थे कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए लोकसभा में उनका आना सुरक्षित नहीं. लोकसभा अध्यक्ष की यह सूचना सुरक्षा के लिहाज से बेहद चौंकाने वाली थी. गौरतलब है कि 2024 के मध्य से वॉच एंड वार्ड स्टाफ नहीं, बल्कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) पर संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह यह संदेश जाये कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं, तो यह बेहद गंभीर मामला है.

दूसरी तरफ, सरकार पर सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशिक पुस्तक, 'फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी' का जिक्र करते हुए 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की आक्रामकता के बरक्स केंद्र सरकार की कथित रक्षात्मकता का मुद्दा उठाने की कोशिश की. लेकिन चूंकि प्रकाशक ने इस पुस्तक के प्रकाशित न होने की जानकारी दी, तथा नरवणे ने भी प्रकाशक के रुख से सहमति जतायी, ऐसे में, स्थिति विस्फोटक हो गयी. स्थिति तब और जटिल हो गयी, जब एक एफआइआर दर्ज हो गयी और सदन में बहस किताब में दर्ज मुद्दे के बजाय इस पर केंद्रित हो गयी कि राहुल गांधी के पास यह किताब आयी कहां से. सदन में राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास कराया. उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करने के साथ उन पर जीवनभर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की भी मांग की.

इन घटनाक्रमों के कारण संसद की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं- यानी नेता प्रतिपक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष की छवि प्रभावित हुई. इसने एक बार फिर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भरोसे की कमी की रेखांकित किया, जिस कारण संसद ही नहीं चल पायी. इस कारण सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद भी कठिन हो गया. बेशक संसद को सुचारु तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है. लेकिन यह विपक्ष के सहयोग या आपसी संवाद में शालीनता के बगैर संभव नहीं है. संसद में गतिरोध पैदा होना कोई नया नहीं है. मुझे 1996 का एक दृश्य याद आता है, जब सदन में भारी शोरगुल से परेशान तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त संसद के सेंट्रल हॉल के दरवाजे के पास हाथों में अपना सिर टिकाये परेशान और निरुपाय बैठे थे. गठबंधन सरकारों के दौर में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की असहमति से संसद के कामकाज में बार-बार गतिरोध पैदा होते थे. उस दौर में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गयी थीं, और उनके सांसद जब-तब संसद ठप कर अपने प्रमुखों को यह संदेश देते थे कि वे दिल्ली में अपने राज्य के हितों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. मुझे याद है कि दिसंबर, 2011 में लोकपाल बिल का विरोध करते हुए राजद के एक सांसद ने बिल की प्रति फाड़ दी थी. राजद प्रमुख लालू प्रसाद उस दिन विजिटर्स गैलरी में बैठे अपने सांसदों को देख रहे थे. वर्ष 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुस्से में प्रदर्शन करते सांसदों को फटकारते हुए कहा था, 'ईश्वर के लिए, अपना काम कीजिए'. अतीत में जब भी कभी संसद में गतिरोध पैदा होता था, तब पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही स्थगित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर संयम बरतने और सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए रास्ता निकालने की बात कहते थे. वैसे प्रयास अक्सर सफल होते थे, क्योंकि पीठासीन अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे.

इसके अलावा, तब दोनों ही ओर ऐसे कई नेता थे, जो संसद की गरिमा में विश्वास करते थे और चाहते थे कि संसद चले. तब हमारे संसदीय लोकतंत्र की क्या छवि थी? इसके उत्तर भी संसद से ही मिलते हैं. उस दौर के अनेक सांसदों के यादगार भाषण सुरक्षित हैं. सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच स्वस्थ रिश्तों की स्मृतियों की एक झलक स्वर्गीय सुषमा स्वराज के 2014 के एक भाषण से मिलती है, जब वह नेता प्रतिपक्ष थीं. सुषमा स्वराज ने 15वीं लोकसभा के विघटित होने से ठीक पहले जो कुछ कहा था, वह आज के संदर्भ में ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा था, 'भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी (सुशील कुमार शिंदे) अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे'. उसके बाद सुषमा स्वराज ने संकट के समय मध्यस्थता के लिए सोनिया गांधी की प्रशंसा की. जबकि अतीत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में इन्हीं सुषमा स्वराज ने अपना सिर मुड़वा लेने की धमकी दी थी. फिर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी विनम्रता, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उनकी सहिष्णुता और लालकृष्ण आडवाणी को उनकी न्यायप्रियता के लिए धन्यवाद दिया. जाहिर है, संसदीय गतिरोध के समय इन सबकी भूमिका उल्लेखनीय थी. सुषमा स्वराज ने कहा था कि 'भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख भावना यह है कि विपक्ष में होते हुए भी हम शत्रु नहीं हैं'. इसीलिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद संबंध बनाये रखना संभव हो सका. सुषमा स्वराज के ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि वे बारह साल पहले थे.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक होती है मातृभाषा

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
uchaturvedi@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

तकनीकी दौर में मातृभाषाएं सर्वाधिक संकट में हैं. जैसे-जैसे अधिकाधिक भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, भाषायी विविधता खतरे में पड़ती जा रही है. दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है. इसी कारण दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषायी विविधता का संरक्षण जरूरी है.

तकनीकी दौर में मातृभाषाएं सर्वाधिक संकट में हैं. क्योंकि मातृभाषाओं में बात करना भी तकनीक से प्रभावित हो रहा है और लेखन तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है. तकनीक की विशेषता कहें या कमी, वह बाजार के लिहाज से खुद को विकसित करती है और अपने उत्पादों के लिए इसी नजरिये से शोध करती है. चूंकि मातृभाषाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें बोलने या जिनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनसे कमाई की संभावना कम है, इसी कारण तकनीक उनके सहज इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाती. इसलिए मातृभाषाएं बड़ी संख्या में लुप्त होने के कगार पर हैं. भारत को ही देखिए. वर्ष 1961 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से भारत में 1,652 भाषाएं थीं, पर 1971 में यह संख्या घटकर 808 रह गयी. ऐसा परिवर्तन तब हुआ, जब तकनीक का बोलबाला नहीं था. पर अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है. वर्ष 2013 के भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, विगत 50 वर्षों में जहां 220 भाषाएं लुप्त हो गयी हैं, वहीं 197 भाषाएं समाप्ति के कगार पर हैं.

मातृभाषाओं के लुप्त होने के कई अन्य कारण भी हैं. भाषा शास्त्रियों के अनुसार, व्यक्तिवादी दर्शन, उपभोक्तावाद, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में आ रहे परिवर्तन, और शहरीकरण के साथ ही पारंपरिक मूल्यों के प्रति घटती निष्ठा और रोजगार के साधनों के रूप में भाषाओं की घटती संख्या भी मातृभाषाओं की समाप्ति के कारण बने हैं. हालांकि, कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो मातृभाषाओं को लेकर कुछ क्षेत्रों में सम्मोहन अभी भी बरकरार है. संभवतः यही कारण है कि इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को ने जो थीम रखी है, वह बेहद अहम जान पड़ती है. यह थीम है, 'भाषाओं का महत्व : रजत जयंती और सतत विकास.' इस थीम का ध्येय वाक्य 'अनेक भाषाएं, एक भविष्य' है. पूर्वी बंगाल में 1952 में शहीद हुए भाषा आंदोलनकारियों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की शुरुआत की 2025 में रजत जयंती थी. तब यूनेस्को ने इस दिवस को भाषाई विविधता, डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर जोर देने पर केंद्रित किया था. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हर वर्ष यूनेस्को किसी न किसी अहम विषय को ध्येय बनाता है और उस दृष्टिकोण से पूरे वर्ष भाषाई विविधता को विकसित करने और उन्हें लागू करने पर जोर देता है. इस बार के ध्येय वाक्य से साफ है कि यूनेस्को चाहता है कि विश्व के सतत विकास में मातृभाषाओं की महत्ता रेखांकित की जाये.

मातृभाषाएं एक तरह से भाषायी लोकतंत्र को रचती हैं. इस लोकतंत्र को बचाये बिना विविधरंगी संसार को नहीं बचाया जा सकता. सोचिए, यदि उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी वर्चस्व के चलते एकरस और एक भाषायी संसार तैयार हो जाये, तो दुनिया कितनी नीरस होगी, ज्ञान के तमाम स्रोत तब या तो सूख चुके होंगे या फिर भुला दिये गये होंगे. इसलिए मातृभाषाओं को बचाना और उन्हें सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जिंदा रखना जरूरी हो जाता है. यूनेस्को की ओर से घोषित 'भाषाओं का महत्व : रजत जयंती और सतत विकास' विषय, एक तरह से भाषाई विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास के बीच गहरे संबंधों को ही रेखांकित करता है. चूंकि यूनेस्को मातृभाषाओं को संरक्षित करने, भाषाई विविधता को जिंदा रखने और उन पर रश्क करने के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वह लगातार भाषाओं को बचाने का संदेश दे रहा है. चूंकि भाषाएं सिर्फ संवाद का साधन ही नहीं होतीं, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का महत्वपूर्ण औजार भी हैं, लिहाजा प्राथमिक शिक्षा में उन पर जोर दिया जा रहा है. दुनियाभर के शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा समावेशी होती है और बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में मददगार होती है. इसी कारण सतत विकास के लक्ष्यों को अब मातृभाषा के जरिये मिलने वाली शिक्षा में गंभीरता से खोजा जा रहा है.

जैसे-जैसे अधिकाधिक भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, भाषाई विविधता खतरे में पड़ती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं. मातृभाषाओं का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि स्थानीय समाज उनके माध्यम से शिक्षा हासिल कर सकें. मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक नींव की आधारशिला है. यह सोचने, समझने और संवाद करने का सबसे सहज माध्यम है, जो बच्चे को उसकी विरासत से जोड़ती है. मातृभाषा में शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है और संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं. शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, जिन बच्चों की नींव मातृभाषा में मजबूत होती है, मातृभाषाओं से इतर भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है. दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है. इसी कारण दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषाई विविधता का संरक्षण जरूरी है. स्थानीय भाषाएं ज्ञान का खजाना हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

अमेरिका यूरोप को श्वेत वर्चस्ववाद के युग में वापस घसीट रहा है

पच्चीस वर्ष पहले, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूरोपीय नेताओं को अपने आतंकवाद विरोधी युद्ध का समर्थन करने के लिए राजी किया था. उसमें लाखों लोगों की जान गयी और मध्य-पूर्व के कई हिस्सों से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए. उसने अमेरिका और यूरोप में मुसलमानों, शरणार्थियों और नस्लीय अल्पसंख्यकों के प्रति नस्लवाद और घृणा को सामान्य बना दिया. मुझे डर है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मार्को रुबियो का भाषण, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर नस्लीय प्रवासियों से श्वेत, पश्चिमी, ईसाई सभ्यता की रक्षा करने का आह्वान किया, एक भयावह सिलसिला शुरू कर सकता है. एक साझा और श्रेष्ठ अमेरिकी और यूरोपीय सभ्यता को लेकर रुबियो की भाषा डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस से अलग है. रुबियो आतंकवाद और कठोर सुरक्षा खतरों की बात करने के बजाय प्रवासन, पहचान और सभ्यतागत चिंताओं की बात करते हैं, जैसा कि कभी बुश ने किया था. अपने म्यूनिख भाषण में रुबियो ने विदेशियों के प्रति नफरत या घृणा का संदेश फैलाने से इनकार किया, इसकी बजाय राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने के अपने आह्वान को कर्तव्य और संप्रभुता की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया. पर आप्रवासियों के ऊपर मूलनिवासी के हितों को प्राथमिकता देने का संदेश जस का तस रहा. नौ ग्यारह हमलों के बाद के हालात को झेलने और उन पर रिपोर्टिंग करने के बाद मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि श्वेत वर्चस्व से प्रेरित ऐसे विमर्श के पीछे नस्लवादी भावनाएं और इस्लाम विरोधी संकेत छिपे होते हैं. कई वर्ष पहले, यूरोप में इस्लाम के स्थान, निष्ठा व अपनेपन के भाव, और मुसलमानों को दूसरा मानने के मुद्दे पर जो चिंताजनक बहसें छिड़ी थीं, वे आज भी यूरोपीय मुसलमानों को परेशान कर रही हैं. भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में, यूरोपीय नेता चिंतित हैं कि कहीं उनका सहयोगी अमेरिका नाराज न हो जाये, सो वे उसका साथ दे रहे हैं. पर नस्लवाद को चाहे कितना भी स्वाभाविक तथा सद्गुण के रूप में प्रस्तुत किया जाये, उसकी आलोचना होनी ही चाहिए.

The Guardian

-शदा इस्लाम

बोधि वृक्ष

धर्म के लिए कामना

किसान सोचता है कि जिस जमीन पर वह बीज फेंक रहा है, उस पर बीज अंकुरित होंगे या नहीं? ऐसे ही मुझे भी लगता है कि जिनसे कह रहा हूं, वे सुन भी सकेंगे या नहीं? उनके भीतर कोई बीज अंकुरित हो सकेगा या नहीं? जब इस तरह सोचता हूं, तो बहुत निराशा होती है. निराशा इसलिए कि विचार केवल उनके हृदय में बीज बन पाते हैं, जिनमें प्यास हो. केवल उनके हृदय सुनने में समर्थ हो पाते हैं, जिनके भीतर गहरी कामना हो. अन्यथा हम सुनते हुए मालूम पड़ते हैं, परंतु सुन नहीं पाते. हमारे हृदय में विचार जाते हुए मालूम पड़ते हैं, परंतु उनमें कभी अंकुरण नहीं होता है. प्यास के बिना किसी के लिए सुनना संभव नहीं है. इसलिए आवश्यक नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं, वे सभी सुनेंगे. यह भी जरूरी नहीं है कि उन तक मेरी बात पहुंचेगी. परंतु इस आशा में कि शायद किसी के पास पहुंच जायेगी, तो भी ठीक है. यदि एक के पास भी बात पहुंच जाए, तो परिणाम निश्चित होगा. मगर दुनिया में सत्य और परमात्मा के लिए प्यास कम होती जा रही है. सत्य और धर्म के लिए हमारी कामना कम होती जा रही है. यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी धर्म के सदस्य नहीं भी हो सकते हैं, पर आपके अंदर धर्म के लिए प्यास हो सकती है. जिसके भीतर प्यास होगी, वह खोज करेगा, साहस करेगा, साधना करेगा और सत्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेगा. हम दूसरों के उधार विचार स्वीकार कर लेते हैं, और परंपरा से सहमत हो जाते हैं. जन्म का आकस्मिक संयोग हमें जिस घर में पैदा कर देता है, हम उस धर्म को अंगीकार कर लेते हैं. ये हमारे भीतर बुझी हुई प्यास के लक्षण हैं. जिनके भीतर परंपरा के प्रति संदेह नहीं उठता, जिनके प्रति प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं के प्रति जिज्ञासा और प्रश्न खड़े नहीं होते हैं, उनके भीतर कोई प्यास नहीं है. यदि उनके भीतर प्यास हो, तो प्यास की अग्नि उन्हें विद्रोह में ले जायेगी. धर्म और सत्य की खोज एक विद्रोह है. हम अनुभूति करेंगे, तो स्वीकार करेंगे. अनुभूति के पहले जो स्वीकार करने को तैयार है, उसकी प्यास झूठी है. यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और पानी शब्द से ही वह तृप्त हो जाये, तो हम क्या कहेंगे.

-ओशो

कुछ अलग

परदेस में विसंगतियों की तलाश

राकेश सोहम्
व्यंग्यकार
sohamsahitya@gmail.com

विकसित देश साफ-सफाई वाले होते हैं. ऐसे देश में रहने का अवसर मिले, तो कौन नहीं जाना चाहेगा. मुझे बुलावा आया. फिर भी मैं अनमना-सा घूमता रहा. दरअसल, मैं एक कलमकार हूं. इसलिए तैयारी करते हुए एक कलम मैंने अपनी कमीज की जेब में खोंस ली. फिर भी एक दिक्कत है. व्यंग्य की कलम में विसंगति की स्याही लगती है. अड़चन विसंगतियों को लेकर आ रही है. विकसित देश में विसंगतियों का भारी टोटा है. बिना विसंगतियों के तो मेरा प्रवास गुड़-गोबर हो जायेगा. मैं विसंगतियों को लादकर ले जाना चाहता हूं. पर डरा हुआ हूं. यदि मेरे चेकइन बैग में विसंगतियां पकड़ ली गयीं, तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा. यह भी संभव है कि मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर 'डिपोर्ट' कर दिया जाये.

मैं अपने देश को सुधरता हुआ देखना चाहता हूं. इसलिए स्वदेशी विसंगतियों पर नजर रहती है. यहां विसंगतियां भरपूर हैं. विसंगतियों का समुद्र है. जितनी चाहे उलीच लो. जिस दिन लगता है कि आज लिखने के लिए कोई विसंगति उपलब्ध नहीं है, पान के ठेले पर जा खड़ा होता हूं. कोई न कोई पान का शौकीन, वहां पान की जुगाली करते हुए विसंगति बयां करने लगता है. पीकें उछालते हुए विसंगतियों से समझौता करके शांत हो लेता है. कार्यालयीन समय में चाय-समोसे के साथ भी विसंगतियां फ्री में उपलब्ध हो जातीं हैं. परदेस में ऐसे पान-ठेले कहां? वहां चाय-समोसे की गुमटियां भी नहीं होतीं. विसंगतियों को बांधकर ले जाना असंभव है. वर्ना जर्दे की पुड़िया की तरह विसंगतियों को डिबिया में भरकर चेक इन वाले बैग में छुपाकर ले जाता. जब मन होता जुगाली कर लेता, लेकिन विसंगतियों को तो भोगना पड़ता है. वर्ना वे बासी हो जाती हैं. वैसे महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी विसंगतियां सदाबहार होती हैं. भोगने के बाद भी समाप्त नहीं होतीं. पर एक ही विसंगति की स्याही से कलम भोथरी हो जाती है. व्यंग्य की कलम के लिए अलग-अलग स्याही लगती है.

बहरहाल, परदेस पहुंचकर मुझे कुछ विसंगतियां दिखाई पड़ने लगी हैं. यहां की कारों में ड्राइविंग सीट उल्टी तरफ है. सड़क पर कारें रॉन्ग साइड से दौड़ती हैं. इसलिए यहां पर कार चलाते हुए तात्कालिक सुख का अनुभव होने लगा है. यहां इस बात की चिंता नहीं सताती कि अचानक कोई सामने से आकर घुस पड़ेगा और दुर्घटना हो जायेगी. चौपहिया वाहन के चालन में अपने देश की विसंगतियों को ताजा करते हुए अच्छा लग रहा है. हाल ही में देश में रुपये के लुढ़कने से खासी विसंगति खड़ी हो गयी है. उफ! एक तो वैसे ही परदेस में विसंगतियों का टोटा है, ऊपर से कार्ड में भरकर लाया गया रुपया भी छोटा पड़ गया है!

आपके पत्र

जाम से मुक्ति के लिए बाइपास जरूरी

अभी बिहार बोर्ड व सीबीएसइ की मैट्रिक परीक्षा चल रही है. जाम की वजह से कई छात्र-छात्राओं की परीक्षा छूटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. सड़कों पर भारी भीड़ में रेंगती गाड़ियों के कारण वे अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाते. समस्तीपुर के रोसड़ा जैसे शहर, जहां भारी मालवाहक गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया है. ऐसे शहरों में अविलंब बाइपास का निर्माण होना चाहिए. जाम की समस्या को निबटने में प्रशासन व पुलिस भी लाचार दिखती है. इसलिए सरकार को रोसड़ा में बाइपास का निर्माण कराना चाहिए.

सचिन झा, समस्तीपुर

अगली औद्योगिक क्रांति है एआइ

एआइ अगली औद्योगिक क्रांति है और पूरी दुनिया इसके कारनामों से अभिभूत है. भारत ने इसकी दूरदृष्टि महत्ता को समझते हुए नयी दिल्ली में एआइ महाकुंभ आयोजित कर अमेरिका और चीन की बराबरी का संदेश दिया. अमेरिका और चीन पहले ही अपने एआइ मॉडल प्रस्तुत कर चुके हैं, जिन्हें अन्य देश अपना रहे हैं. भारत का यह सम्मेलन दिखाता है कि वह केवल एआइ का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने की दौड़ में अमेरिका और चीन को कड़ी चुनौती दे रहा है. एआइ मशीनों को सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देता है.

युगल किशोर राही, छपरा

https://t.me/NewsPapersPaidU

नई दिल्ली

कल्पमेधा

धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जिसमें निश्चित असफलता जान पड़ती है।

– डेल कानेर्गी

न्याय की संवेदना

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई और फैसले की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायालय में पीड़िता के पक्ष पर कितनी संजीदगी के साथ गौर किया गया। खासतौर पर हमारे देश में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में न केवल इस अपराध की प्रकृति, बल्कि उसका पीड़िता के मन-मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बेहद संवेदनशील रुख अपनाने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार इन तकाजों को प्राथमिक नहीं माना जाता। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक जरूरी मानक सामने रखा है कि निचली अदालतों में बलात्कार के मामलों पर सुनवाई करते हुए कितना संवेदनशील होने की जरूरत है! गौरतलब है कि पिछले वर्ष मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक नाबालिग लड़की पर यौन इरादे से शारीरिक बलप्रयोग को बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं माना और आरोपों को हल्का करार दिया। उस समय भी अदालत के रुख और उसकी टिप्पणियों पर तीखे सवाल उठे थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, उससे एक बार फिर महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संबंधित मामले में बलात्कार से संबंधित कानून के प्रावधानों की विचित्र व्याख्या करके आरोपियों के प्रति जिस तरह नरम रुख अख्तियार किया था, वह अपने आप में न्याय की प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल था। खासतौर पर एक नाबालिग लड़की पर तीन युवकों के शारीरिक बलप्रयोग, बदतमीजी और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने की जिस स्तर पर अनदेखी की गई और आरोप की गंभीरता को कम किया गया, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। बीते वर्ष 25 मार्च को शीर्ष अदालत की पीठ ने साफ शब्दों में कहा था कि यह फैसला पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है, इसलिए इस पर रोक जरूरी है। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई और उसके विवादित फैसले को पलटते हुए नाबालिग लड़की से की गई हरकत को 'बलात्कार का प्रयास' करार दिया। अब यह मुकदमा गंभीर अपराध और पाक्सो अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत चलेगा।

निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह रुख महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की रोकथाम और खासतौर पर अदालतों में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की सुनवाई के क्रम में कभी-कभार बरती जाने वाली असंवेदनशीलता के मद्देनजर बेहद अहम है। सवाल है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अपराध की प्रकृति, पीड़िता की स्थिति और सामाजिक हकीकतों को ध्यान में रखना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता! जब भी अदालतों की ओर से ऐसे मामलों में जरूरी संवेदनशीलता के तकाजों की अनदेखी की जाती है, तब यौन अपराधों के विरुद्ध महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रयास कमजोर होते हैं। शायद इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने अब यौन अपराधों और अन्य संवेदनशील मामलों के संदर्भ में न्यायाधीशों के दृष्टिकोण और न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता तथा करुणा पैदा करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को एक समिति गठित करने को कहा है। यह इसलिए भी जरूरी पहल है कि न्याय की उम्मीद तभी पूरी हो सकती है, जब न्यायाधीशों के भीतर पीड़ित की वास्तविक स्थितियों के प्रति जरूरी संवेदनशीलता, करुणा और समझ की भावना हो।

साख पर सवाल

आमतौर पर झूठे दावों की हकीकत किसी न किसी रूप में सामने आ जाती है, लेकिन कई बार उसके नतीजे गंभीर होते हैं। दिल्ली में आयोजित 'एआइ इम्पैक्ट सम्मेलन' में हिस्सा लेने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक झूठ से न केवल उसकी फजीहत हुई, बल्कि इस आयोजन में बरती जाने वाली कोताही पर भी सवाल उठे। यह बात समझ से बाहर है कि इस संस्थान को चीन के बनाए 'रोबोटिक डाग' को अपना नवाचारी उत्पाद बता कर पेश करने की क्या जरूरत थी? सम्मेलन में उपस्थित उसके प्रतिनिधि ने क्या सोच कर इस संबंध में अतिरेक से भरे और झूठे दावे किए? अव्वल तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के फर्जी और अनैतिक दावे करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। दूसरे, ऐसा करते हुए एक बार भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि जिस तरह की तकनीक के बारे में झूठा दावा किया गया, आज इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में उस झूठ को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है।

आखिर विवाद बढ़ने के बाद संस्थान को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन इससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ा है। इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उचित ही सम्मेलन से वह स्थल खाली करने को कहा गया, जहां इस निजी विश्वविद्यालय ने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। इस बात की पूरी संभावना है कि एआइ सम्मेलन में प्रदर्शित करने के लिए आए तमाम उत्पादों को मंजूरी पहले ही दी गई होगी। सवाल उठता है कि इस सम्मेलन में संस्थानों को जब अपने मौलिक एआइ उपकरणों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया होगा, तब गलगोटिया की ओर से लाए गए 'रोबोटिक डाग' और उसके बारे में बढ़-चढ़ किए गए दावों को लेकर आयोजकों की ओर से शुरू में ही जरूरी सवाल क्यों नहीं किए गए? आज जब देश कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने की जमीन तैयार करने में लगा है, तो ऐसे में इस विवाद ने सम्मेलन में एक असहज स्थिति पैदा की। सवाल केवल किसी संस्थान की साख का नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का है।

लक्ष्य से दूर कार्बन उत्सर्जन पर लगाम

महज वादे करने और इरादे जताने भर से कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाना संभव नहीं है। छोटे-बड़े कई देशों ने संकल्प तो जताया, लेकिन उत्सर्जन रोकने के ठोस उपाय नहीं किए। नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है।

सुशील कुमार सिंह

धरती का तापमान न बढ़े, इसके लिए कवायद तो हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों की वर्तमान नीतियां ऐसी हैं जो तापमान को 2.3 से 2.5 डिग्री तक ले जा सकती हैं। हालांकि कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया है। फिर भी 29 देशों में कार्बन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर, भारत कम उत्सर्जन के साथ मध्यम प्रदर्शन कर रहा है। 'कार्बन मार्केट वाच' की रपट बताती है कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े देश जलवायु परिवर्तन रोकने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसद कमी लाने की जरूरत है। मगर इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। कई बड़े उद्योगों का कामकाज जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। सच यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से रोकने के प्रयास अपर्याप्त हैं।

पिछले जी-20 सम्मेलन में शामिल देशों में वर्ष 2050 तक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मगर यह भी सच है कि भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जलवायु अनुकूलन का तालमेल स्थापित करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत ने कई महीनों तक गर्म हवाओं, बाढ़ और चक्रवात जैसी विषम मौसमी घटनाओं का सामना किया था, जिससे जन-जीवन से लेकर लोगों की आजीविका तक प्रभावित हुई। साथ ही विकास कार्यों के लिए यह स्थिति बाधा बनी रही।

'नेट जीरो' का मतलब ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना भर नहीं है, बल्कि इन गैसों को दूसरे कामों से संतुलित करना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी तैयार करना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल न के बराबर हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उसी के अनुपात में उसे अवशोषित करने का भी इंतजाम हो। यह पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। यदि कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में होता है और उत्सर्जन करने वाली इकाई उसी अनुपात में पेड़ों को महत्त्व देती है, तो कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण की समानता के कारण उत्सर्जन को शून्य स्तर पर ले जाना आसान हो जाएगा। मगर मौजूदा दौर में जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे अब शून्य उत्सर्जन के बारे में सोचना सपना ही लगता है। फिलहाल दुनिया में केवल दो देश भूटान और सूरीनाम ही हैं, जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य है। इसकी वजह वहां कम आबादी और चारों तरफ हरियाली है।

महज वादे करने और इरादे जताने भर से इस उत्सर्जन को शून्य पर लाना संभव नहीं है। छोटे-बड़े कई देशों ने संकल्प तो जताया, लेकिन उत्सर्जन रोकने के के ठोस उपाय नहीं किए। नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह होता रहा, तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का तापमान दो डिग्री बढ़ जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। लोगों को भीषण सूखा से लेकर विनाशकारी बाढ़ का सामना

करना पड़ेगा। हिमखंड और अधिक पिघलेंगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होगा।

दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इनमें 137 देश शून्य उत्सर्जन का समर्थन करते हैं। देखा जाए, तो कुल ग्रीनहाउस उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी 80 फीसद है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले चीन और अमेरिका भी इसी में शामिल हैं। चीन ने वर्ष 2026 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस मामले में वह कितना खरा उतरेगा, कहना मुश्किल है। दूसरी ओर, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश 2045 तक, जबकि आस्ट्रिया, फिनलैंड और उरुग्वे ने अलग-अलग समय में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अमेरिका के अलावा ऐसे कई देश हैं जो इस मामले में कहीं आगे जाकर वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हैं। इस बीच सुखद यह है कि जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के बीच भारत के वन क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान तीन फीसद से अधिक बढ़ोतरी हुई। वैसे भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर दूसरे देशों के मुकाबले कहीं अधिक चिंतित है। इस समय वह नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (काप-26) में भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को किसी भी तरह कम किया जाए। दूसरा यह कि अपनी 50 फीसद ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से कैसे पूरा किया जाए। वहीं कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते जाना है। इसके अलावा, वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तो है ही। हालांकि समय की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, यह अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाना और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी बड़ी राशि आबंटित की गई है और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रानिक वाहनों तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

इस वर्ष के बजट में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की पहल दिखती है। हरित ऊर्जा गलियारा, परमाणु ऊर्जा पर जोर और हरित बुनियादी ढांचा- ये सब ऐसे संदर्भ हैं, जिस पर भारत 'पृथ्वी प्रथम' की नीति को महत्त्व देता है। जबकि कुछ ताकतवर देश अपनी नीतियों में 'देश प्रथम' को महत्त्व दे रहे हैं। नतीजा यह कि इसकी कीमत शेष देश चुका रहे हैं।

दुनिया भर के देश अगर किसी भी तरह जल्दी अथवा धीरे-धीरे ही सही कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प करें, तो न केवल पृथ्वी, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। यह निराशाजनक ही है कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाम के मुद्दे पर दुनिया के देशों में कागजी एकजुटता तो देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सार्थक पहल करते नहीं दिखते। वहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच नाहक ही इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है। सभी को सोचना होगा कि भौगोलिक सीमाओं में बेशक सभी देश बंटे हुए हैं, लेकिन धरती तो एक ही है और सभी को मिल कर उसे बचाना है। दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि 'राष्ट्र प्रथम' की नीति लेकर नहीं, बल्कि वैश्विक सुशासन के साथ काम करना होगा।

फिलहाल भारत की अपनी चिंताएं और चुनौतियां हैं। अगर यह कार्बन उत्सर्जन पर सख्ती से कदम उठाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। सच भी है कि अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में संयमित देश है और यह अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है।

> **दुनिया भर के देश अगर किसी तरह जल्दी या फिर धीरे-धीरे ही सही, कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प करें, तो न केवल पृथ्वी, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। यह निराशाजनक ही है कि कार्बन उत्सर्जन पर दुनिया के देशों में कागजी एकजुटता तो देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सार्थक पहल करते नहीं दिखते। वहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच नाहक ही इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है। सभी को सोचना होगा कि भौगोलिक सीमाओं में बेशक सभी देश बंटे हुए हैं, लेकिन धरती तो एक ही है और सभी को मिल कर उसे बचाना है।**

https://t.me/AllNewsPapersPdf

रिश्तों का परिवेश

पवन शर्मा

रिश्ते कभी वसंत की तरह खिलखिलाते हैं, कभी बरसात की तरह गीला-गीला होते हैं, कभी ग्रीष्म की तरह तपते हैं और कभी पतझड़ की तरह सूने-सूने लगते हैं। मगर बीते कुछ दशकों में इनका बदलना सिर्फ स्वाभाविक चक्र नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के गहरे बदलावों का आईना भी बन गया है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि रिश्तों का रूप, उनकी परिभाषा और उनका निभाया जाना- सब कुछ बदल रहा है। यह स्थिति हमें कभी सुकून देती है, तो कभी बेचैनी से भर देती है।

कभी भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान संयुक्त परिवार हुआ करती थी। एक ही छत के नीचे तीन-चार पीढ़ियां साथ रहती थीं। बच्चों का पालन-पोषण सिर्फ मां-बाप तक सीमित नहीं था, उसमें दादी-नानी का दुलार, बड़ों की डांट और छोटे-बड़े भाई-बहनों की शरारतें शामिल थीं। त्योहार धार्मिक अवसर मात्र नहीं होते थे, बल्कि वे पारिवारिक एकजुटता और रिश्तों की मजबूती का उत्सव होते थे। अब वही संयुक्त परिवार टूटकर छोटे-छोटे फ्लैटों में सिमट गए हैं। महानगरों की नौकरी और पढ़ाई ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया है, जहां न तो आंगन है, न चौपाल। चार पीढ़ियों का साथ अब दुर्लभ हो गया है। रिश्तों की नजदीकी धीरे-धीरे दूरी में बदल गई है।

डिजिटल क्रांति ने इस दूरी को और भी गहराई दी है। दोस्त अब मोहल्ले की गली या गांव की चौपाल पर नहीं मिलते, वे सोशल मीडिया और आभासी खेलों की दुनिया में मिलते हैं। भाई-बहन एक ही घर में रहकर भी अपने-अपने डिजिटल कमरों में कैद हैं। किसी के कानों में हेडफोन है, किसी की आंखों पर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। माता-पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं और बच्चों के पास माता-पिता को सुनने का धैर्य नहीं। संवाद जो कभी रिश्तों की जान हुआ करता था, अब सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर 'स्टेटस अपडेट' की दुनिया में बिखर गया है। शिकायतें सीधे कहे जाने के बजाय इशारों और 'इमोजी' में बदल गई हैं।

यह भी सच है कि डिजिटल दुनिया ने कुछ नए रास्ते खोले हैं। परदेस गया बेटा अब अपनी मां से रोज वीडियो काल के जरिए बात कर सकता है। बहन-भाई रक्षाबंधन पर आनलाइन तोहफे भेज सकते हैं। विदेश में बैठा छात्र अपने गांव की शादी का सीधा प्रसारण देख सकता है। यह सब तकनीक की देन है और रिश्तों को नई तरह की निकटता भी देती है। मगर सवाल यही है कि क्या यह निकटता असली अपनापन बन पाती है? दिल का 'इमोजी' क्या सचमुच धड़कते दिल की गर्माहट पहुंचा सकता है? एक वीडियो काल क्या मां की गोद का विकल्प हो सकता है?

नई पीढ़ी रिश्तों को बराबरी की नजर से देखती है। बेटियां अपने फैसले खुद ले रही हैं, बेटे घर के कामों में हाथ बंटा रहे हैं। विवाह और दोस्ती, दोनों में बराबरी का भाव बढ़ा है। जाति और धर्म के बंधनों को भी धीरे-धीरे चुनौती दी जा रही है। यह बदलाव सकारात्मक है, क्योंकि यह रिश्तों को न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बना रहा है। मगर साथ ही यह पीढ़ी धैर्य और प्रतीक्षा से भी दूर जा रही है। हर चीज उन्हें तुरंत चाहिए- खाना, प्यार और रिश्ते भी। यही कारण है कि अब टूटते रिश्ते किसी को ज्यादा विचलित नहीं करते। सोशल मीडिया पर 'ब्लाक' और 'अनफ्रेंड' रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता बन गए हैं। जहां पहले रिश्ते निभाने के लिए समझौते और त्याग की जरूरत होती थी, वहां अब एक क्लिक से रिश्ता खत्म करना आम हो गया है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी रिश्तों की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले रिश्ते अपनापन और जिम्मेदारी के आधार पर चलते थे। अब वे लाभ-हानि के तराजू में तौले जाने लगे हैं। दोस्ती तब तक है, जब तक काम आ रही है। विवाह तब तक है, जब तक सुख और सुविधा मिल रही है। पड़ोस तब तक है, जब तक उससे कोई फायदा जुड़ा हुआ है। यह मानसिकता रिश्तों को खोखला कर रही है। रिश्ते अब जिम्मेदारी कम और सौदेबाजी ज्यादा लगने लगे हैं।

त्योहारों की दुनिया में भी यही बदलाव दिखता है। पहले दीपावली पर घर-घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थीं, अब आनलाइन तोहफे का 'वाउचर' भेजना काफी समझा जाता है। होली पर गले मिलने की जगह 'हैप्पी होली' का संदेश भेज देना सामान्य हो गया है। ईद की सेवई और क्रिसमस का केक अब 'वाट्सएप स्टिकर' तक सिमट गया है। त्योहारों की आत्मा रिश्तों की गहराई थी, जो अब बाजार और तकनीक की चमक में कहीं खोती जा रही है।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। बदलते रिश्तों के इस मौसम ने नई संभावनाएं भी खोली हैं। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों की स्वीकृति बढ़ रही है। दूरदराज के रिश्तेदार मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जुड़े रह सकते हैं। मगर मूल सवाल वही है कि क्या यह सब रिश्तों को जीवित रखने के लिए काफी है? क्या आभासी अपनापन वास्तविक संवेदना की जगह ले सकता है? सच तो यही है कि रिश्ते निभाने के लिए तकनीक से अधिक संवेदना चाहिए। उन्हें जीवित रखने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर वह मानवीय स्पर्श चाहिए, जिसे कोई मशीन नहीं दे सकती।

रिश्तों का मौसम चाहे जैसे भी बदले, उनकी आत्मा वही पुरानी है- विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी। अगर आत्मा बची रही तो रिश्ते बदलते मौसमों में भी हरे-भरे रहेंगे। अगर यह आत्मा खो गई, तो रिश्ते सिर्फ नामों और नंबरों की सूची बनकर रह जाएंगे। आज हमें यही तय करना है कि हम किस मौसम में जीना चाहते हैं- वसंत की गुनगुनाती गरमाहट में या पतझड़ की सूनी उदासी में।

दुनिया मेरे आगे

> **रिश्तों का मौसम चाहे जैसे भी बदले, उनकी आत्मा वही पुरानी है- विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी। अगर आत्मा बची रही, तो रिश्ते बदलते मौसमों में भी हरे-भरे रहेंगे। आज हमें यही तय करना है कि हम किस मौसम में जीना चाहते हैं- वसंत की गुनगुनाती गरमाहट में या पतझड़ की सूनी उदासी में।**

दायित्व का दायरा

पिछले दिनों गायिका जैस्मीन सैंडलस महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर प्रस्तुति से इनकार बेहद अहम घटना है। इस संदर्भ में 'स्त्री की गरिमा' (संपादकीय, 13 फरवरी पढ़ा)। जिस तरह से गायिका ने महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाया, इस पर समाज और प्रशासन दोनों को सोचना होगा। आज भी सार्वजनिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। बड़े आयोजनों में अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंध, भीड़ नियंत्रण की कमी और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई का अभाव अक्सर भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। ऐसे कार्यक्रम में कलाकार यदि महिलाओं को असुरक्षित देख कर असहज महसूस करे, तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोजन स्थल पर क्या व्यवस्था रही होगी। ऐसे में जरूरी है कि आयोजक और प्रशासन मिल कर सुरक्षा मानकों को कठोर बनाएं। सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य हों। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना जरूरी है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

घोर लापरवाही

हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है, क्योंकि इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि आतंकवाद से कई गुना ज्यादा लोग अव्यवस्था और लापरवाही से मारे जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं। इसकी वजह है लापरवाही। कहीं खुले सीवर या पानी भरे गड्ढे में गिर कर लोगों की मौत हो जाती है, तो कहीं बिजली के खुले तारों में उलझ कर। खाद्य पदार्थों में मिलावट भी जानलेवा बन रही है। प्रदूषण की स्थिति तो गंभीर है ही। दिल्ली और मुंबई की बदहाली की वजह हम बेतहाशा बढ़ती आबादी बता देते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि छोटे शहरों से लेकर कस्बों तक में गंदगी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदार वे एजंसियां हैं, जिन पर शहर की गंदगी और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। मगर सच्चाई यही है कि हर तरफ लापरवाही दिखती है।

– मोहन सूर्यवंशी, नई दिल्ली

जोखिम और उम्मीदें

भारत ने एआइ पर शिखर सम्मेलन कर दुनिया को संदेश दिया है कि वह कृत्रिम मेधा में किसी से पीछे नहीं है। यह सम्मेलन भारत की तकनीकी दक्षता और महत्त्वाकांक्षा को दर्शाता है। यह भी स्पष्ट करता है कि वह केवल एआइ का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने की दौड़ में बड़े देशों को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। एआइ कंप्यूटर विज्ञान का ही हिस्सा है, जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह तकनीक डेटा का विश्लेषण करती है और उसके आधार पर कार्य करती है। यह जटिल डेटा पर काम कर सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, जो कई तरह के व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह नई दवाएं खोजने और जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता कर रही है। यह सही है कि एआइ के कारण रोजगार बाजार में उथल-पुथल मचेगी, कई क्षेत्रों में खासकर नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन नई तरह की नौकरियां भी पैदा होंगी।

– युगल किशोर राही, छपरा

समाज की आवाज

आधुनिक संचार माध्यमों के बीच रेडियो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और विश्वसनीय जानकारी का भी स्रोत है। एक दौर में रेडियो ही ताजा समाचार और महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का प्रमुख माध्यम था। स्वतंत्रता की घोषणा से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक, रेडियो ने हर अवसर पर जनता को सही सूचना पहुंचाई। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सर्वसुलभता है। इसे घर, वाहन, खेत या कार्यस्थल कहीं भी सुना जा सकता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई और 'आकाशवाणी' ने इसे जन-जन तक पहुंचाया। रेडियो ने लोक-संगीत, साहित्य, कृषि जानकारी और मौसम का पूर्वानुमान को लोगों तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो आज भी समाज की आवाज बन कर अपनी भूमिका निभा रहा है।

– बलदेव सिंह बेदी, जलंधर

अमर उजाला

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 20 फरवरी 2026

लोकतंत्र, सुशासन और आधुनिकता को किसी दूसरे देश से खरीदा नहीं जा सकता। - एमिल लाहौद

क्षमता पर भरोसा

दिग्गज डिजिटल कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में अगर एआई के क्षेत्र में भारत की मौजूदा स्थिति को अद्वितीय बताया, तो उसकी मुख्य वजह है-उपयोगकर्ताओं की बड़ी आबादी, नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभाओं का विशाल पुल और नियम आधारित वैश्विक एआई शासन में भारत का दमदार हस्तक्षेप। बृहस्पतिवार को इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से डरता नहीं है, बल्कि उसने इसमें अपना भविष्य देखा है। एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और सहयोगात्मक उपयोग के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सम्मेलन में पिचाई ने विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर की लागत से एआई हब बनाने की गूगल की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो देश में गीगावाट क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधा और अंतरराष्ट्रीय सब-सी केबल गेटवे के विकास में महत्वपूर्ण है। भारत-अमेरिका कनेक्ट के तहत घोषित सब-सी केबल गेटवे के विकास से दो महाद्वीपों के बीच संचार संपर्क को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इंटरनेट ट्रैफिक सुचारु होगा। इसके अलावा, गूगल द्वारा छात्रों एवं युवा पेशेवरों के लिए एआई से संबंधित पेशेवर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने से कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। पिचाई का यह कहना समझा जा सकता है कि भारत में एआई सदियों पुरानी कमियों को दूर करने और नए अवसर पैदा करने का मौका देता है, क्योंकि यहां उद्यमिता का परिवेश तेजी से विकसित हो रहा है और कई स्वदेशी कंपनियां तेजी से विकास कर रही हैं। भारतीय उद्यमिता परिवेश के बारे में सुंदर पिचाई की सकारात्मक टिप्पणी दिग्गज तकनीकी कंपनियों की भावनाओं को दर्शाती है, जो भारत की क्षमता पर भरोसा करती हैं और यहां निवेश की खातिर उत्साहित भी हैं। वास्तव में, कंपनियों के इस उत्साह के पीछे सरकार की नीतिगत पहल का भी हाथ है, जिसके चलते न केवल भारत में व्यापार सुगमता बढ़ी है, बल्कि नियामक स्थिरता ने भी निवेशकों को आश्वस्त किया है। पर जैसा कि कई

तकनीकी दिग्गजों ने रेखांकित किया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रमुख दावेदारी करने के लिए भारत को अपने मौजूदा 1.2 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाना होगा। अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने से आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने के अवसर तो मिलेंगे ही, रोजगार की नई संभावनाएं भी पैदा होंगी।

कैसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं रहमान

तारिक रहमान किधर जाएंगे, यह फैसला उन्हें करना है। यह देखने वाली बात होगी कि वह पुराने ढर्रे के राजनेताओं के रास्ते पर चलेंगे या एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के साथ पिछले कुछ समय से जारी तनावपूर्ण संबंधों का अंत हो और पहले जैसे रिश्ते बनें। यह बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा।

तस्लीमा नसरीन

चर्चित लेखिका

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहती है, जहां मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक या संशयवादी-सभी सुरक्षित रहेंगे। यह बात तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कही थी। ऐसी बात आज तक बांग्लादेश के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने नहीं कही। सत्रह साल तक एक विकसित देश में रहने के कारण ही तारिक रहमान अपने शिक्षित और सभ्य होने का ऐसा उदाहरण दे पाए हैं। अन्यथा वह ऐसी बात नहीं कह पाते।

आज तक बांग्लादेश में नास्तिकों और संशयवादियों को सुरक्षा देने का वादा किसी भी सरकार ने नहीं किया था। इसके उलट संशयवादियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले किए गए, उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, यहां तक कि निर्वासन तक में भेज दिया गया। ऐसे लोगों की या तो सिर की कीमत लगाई गई या फिर ऐसे लोगों के हत्यारों के खिलाफ सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेश में नास्तिकों एवं संशयवादियों के नागरिक अधिकारों का वर्षों से उल्लंघन होता आया है। सिर्फ इस्लाम ही ऐसा एक धर्म है, जिसमें नास्तिकों और संशयवादियों को परेशानी होती है। दूसरे किसी भी धर्म में ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती। पर इस्लाम में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हत्यारे अपने छूरे की धार तेज किए रखते हैं। अगर ऐसे जिहादियों से लोगों को सुरक्षा दी जाए, तो हम लोग बांग्लादेश में रह सकती हैं और वहां के लोगों को सभ्य, शिक्षित एवं वैज्ञानिक सोच का बनाने में मदद कर सकती हैं।

बहुत-से लोग कह रहे हैं कि कट्टरवादियों के दबाव में तारिक रहमान शायद नास्तिकों व उदार चिंतकों को सुरक्षा न दे पाएं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान में अल्लाह पर पूरी आस्था और भरोसा रखेंगे। इसका मतलब तो यही निकलता है कि बांग्लादेश पहले की तरह गर्त में रहेगा। ऐसे में, जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी में कोई फर्क भी नहीं रहेगा।

तारिक रहमान के पिता जिया उर रहमान ने धर्मनिरपेक्ष संविधान की हत्या की थी। उम्मीद करनी चाहिए कि तारिक अपने पिता की गलती सुधारेंगे। तारिक रहमान की मां खालिदा जिया ने 31 साल पहले मुझे बांग्लादेश से बाहर किया था। उसका कारण यह था कि जिहादी मेरी हत्या करने की

साजिशें बुन रहे थे। खालिदा जिया ने जिहादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस निरीह लेखिका के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। मानवता के पक्ष में लिखी मेरी चार किताबों को भी उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। उम्मीद करनी चाहिए कि तारिक रहमान मेरी किताबों पर से प्रतिबंध हटाएंगे और बांग्लादेश में मेरी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए, तो यह माना जाएगा कि उनका वादा दिखावटी है। अगर ऐसा हुआ, तो उनमें और दूसरे सुविधावादियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऐसे में, बांग्लादेश के प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और उदारचिंतक, वैज्ञानिक सोच वाले लोगों की हताशा बढ़ेगी ही। तब मूर्ख, अशिक्षित और धर्मांध जिहादी खुश होंगे। तारिक रहमान किधर जाएंगे, यह फैसला उन्हें करना है। यह देखना है कि वह पुराने ढर्रे के राजनेताओं के रास्ते पर चलेंगे या एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। हमारे जैसे असंख्य लोगों की उम्मीद है कि वह धर्मांधता, घृणा, हिंसा और विद्वेष से बांग्लादेश को बचाएंगे।

बांग्लादेश का चुनावी नतीजा देखकर मैं खुश हूं। बीएनपी को जीत हासिल हुई है और रजाकार-जिहादी तथा आतंकी तत्वों से भरपूर जमात-ए-इस्लामी को हार का सामना करना पड़ा है। इन जिहादी तत्वों ने पिछले करीब डेढ़ साल तक बांग्लादेश में विकट तांडव फैलाया, अपने लाखों समर्थकों के साथ सभा की, इच्छानुसार संत्रास फैलाया, जिसे चाहा, उसे मारा, उन पर अत्याचार किया। इन विघटनकारी तत्वों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई, पीट-पीटकर उनकी हत्या की। इन लोगों ने एक भी महिला को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनने दिया। चरम नारी विद्वेषी इन नकारात्मक तत्वों ने कामकाजी महिलाओं को वेश्या कहा, महिला नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई तथा औरतों को बुर्का और नकाब के अंधेरे में ले जाकर पटक दिया। स्त्रियों को जरखरीद गुलाम और यौनदासी समझने वाले जमात के लोग सत्ता में आने पर शरिया कानून लागू करने का सपना देख रहे थे। इसी कारण मतदाताओं ने उन्हें सत्ता में नहीं आने दिया। फिलहाल यही अच्छी खबर है। मेरा मानना है कि बांग्लादेश की सत्ता में आई बीएनपी को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

सबसे पहले, उसे जुलाई चार्टर को रद्द करना चाहिए। उसे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को लाना होगा और इस्लामी राष्ट्रवाद को विदा करना होगा। नई सरकार को इसी तरह मजहब आधारित पारिवारिक कानून रद्द कर स्त्रियों के बराबरी के अधिकार की रक्षा के लिए समान अधिकार पर आधारित अभिन्न दीवानी विधि लागू करना होगा। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी) की सुरक्षा और स्त्री सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नई सरकार को मदरसे की शिक्षा बंद कर वैज्ञानिक सोच पर आधारित धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उसे देश के हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देनी होगी। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हुए नई सरकार को अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध न केवल हटाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि देश से बाहर भाग गए अवामी लीग के तमाम नेता निर्वासन से लौटकर देश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकें। जमात-ए-इस्लामी जैसी एक पार्टी को विरोधी पार्टी का दर्जा मिलना बांग्लादेश के लिए सुखद नहीं है।

आर्थिक उन्नति के साथ-साथ बांग्लादेश में धनी और गरीबों का फर्क मिटाना होगा। राजनीतिक दलों को परिवार व धर्म केंद्रित राजनीति से बाहर निकलना होगा। शेख हसीना के दौर में ब्लॉगर्स की लगातार हत्याओं के कारण अनेक उदारवादी चिंतकों को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। ऐसे लोग वापस बांग्लादेश लौट सकें और सुरक्षित ढंग से अपना कामकाज कर सकें, इस बारे में नई सरकार को आश्वस्त करना होगा। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर नई सरकार को जोर देना होगा। सरकार को कोशिश करनी होगी कि अवामी लीग के जिन किताबों और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन पर से प्रतिबंध हटाए जाएं। मुक्तियुद्ध से जुड़े जिन स्थापत्यों को यूनुस के दौर में मिटा दिया गया था, उनके पुनर्निर्माण की दिशा में भी कदम उठाने जरूरी हैं। इसका भी ध्यान रखना होगा कि देश में कहीं भी महिलाओं के लिए हिजाब व बुर्के की अनिवार्यता न हो। यूनुस के दौर में जिन जिहादियों को जेल से रिहा किया गया था, उन्हें फिर से जेल भेजने का काम होना चाहिए। चिन्मयकृष्ण दास को रिहा किया जाना चाहिए। साथ ही, अवामी लीग के जिन सदस्यों, समर्थकों, कलाकारों, लेखकों व पत्रकारों को गैरकानूनी तरीके से कैद किया गया है, उन्हें भी रिहा किया जाना जरूरी है।

और अंत में, भारत के साथ पिछले कुछ समय से जारी तनावपूर्ण संबंधों का अंत हो और पहले जैसे रिश्ते बनें। यह बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा।

edit@amarujala.com

https://t.me/AUNewsPaper

पर्यावरण

विकास व विनाश की लक्ष्मण रेखा

आर्थिक विकास का विरोध नहीं है, न ही आपत्ति। पर यदि हम अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को साथ लेकर चलें, तो एक बेहतर, सुरक्षित और संतुलित समाज का निर्माण संभव है।

जलवायु परिवर्तन कोई कल्पना नहीं है और न इसे अब प्रमाण जुटाने की जरूरत रह गई है। जिस तरह से पिछले एक दशक में घटनाएं घटी हैं, और इस वर्ष में भी जो कुछ हमने देखा तथा झेला है, वे सभी स्पष्ट संकेत करती हैं कि कुछ तो बदल रहा है और वह बदलाव गहरा तथा खतरनाक है। प्रकृति के इस बदलते व्यवहार के सबसे बड़े दोषी हम स्वयं हैं। यह एक बड़ी वैश्विक घटना बन चुकी है। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि वह सुरक्षित है-यहां तक कि वे देश भी नहीं, जो अपने पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे हैं।

भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में वर्ष 2024 में भीषण गर्मी ने तबाही मचाई। 50 डिग्री सेल्सियस तक की जानलेवा गर्मी हमने झेली, और 2025 में यह स्थिति इतनी सामान्य हो गई कि किसी को आश्चर्य भी नहीं हुआ। इसके बाद दुनिया भर में आई बाढ़ों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। यही नहीं, सऊदी अरब जैसे देश (जहां बर्फ की कल्पना भी नहीं की जा सकती) के कुछ क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ। यह किसी के लिए भी आश्चर्यजनक था, किंतु कथित 'रोमांटिक एन्वॉयरनमेंटलिज्म' ने इसे 'विंटर वंडरलैंड' कहकर प्रस्तुत किया। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह कुदरत की मार है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना आज अत्यंत आवश्यक है। यदि हम पिछले दस वर्षों के आंकड़े देखें, तो चाहे पर्वतीय क्षेत्र हों या मैदानी इलाके (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरल) हर जगह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हुआ है, जो बताता है कि मौसम अब हमारे नियंत्रण में नहीं रहा। यह प्रकृति का अंतिम संदेश है कि अब भी समझने व संभलने का वक्त है। प्रकृति किसी देश के अच्छे या बुरे व्यवहार में भेद नहीं करती। चाहे विकसित देश हों या अविकसित, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। अब सवाल प्रकृति को नहीं, स्वयं को बचाने का है। आज दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ आर्थिक विकास की होड़ है। यह सब बेहतर जीवन की कल्पना के लिए किया जा रहा है, सुख-सुविधाओं से भरे संसार के लिए। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? जिस तरह से हमने प्रकृति के साथ व्यवहार किया है, ये ही सुख आगे चलकर बड़े दुख में बदलने वाले हैं और शायद हम उन्हें झेल भी न सकें। इतिहास गवाह है कि लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले और फिर 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्रकृति में ऐसे बड़े परिवर्तन आए, जिनसे समूचा जीवन समाप्त हो गया। मानव सभ्यता के इतिहास में भी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, प्राचीन मिस्र का पुराना साम्राज्य हो या माया सभ्यता, सभी के पतन में प्रकृति की भूमिका निर्णायक रही है। पिछले 40 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं अमेरिका में, फिर चीन में और तीसरे स्थान पर भारत में हुई हैं, जबकि ये तीनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं।

अनिल प्रकाश जोशी

आर्थिक विकास का विरोध नहीं है, न ही आपत्ति। पर यदि हम अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को साथ लेकर चलें, तो एक बेहतर, सुरक्षित व संतुलित समाज का निर्माण संभव है। अपने देश में भी कई तरह के विरोध-बहस जारी हैं। इसके बजाय, एक राष्ट्रीय बहस क्यों संभव नहीं है, जो यह तय करे कि प्रकृति व पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहिए और अगर चाहिए, तो उसकी सीमा क्या हो। एक तरफ प्रकृति संवेदनाएं जता रही है, तो दूसरी तरफ सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, मिलकर विकास रेखा तय कर ली जाए, जिसे सब मान्यता दें। विकास और विनाश के बीच यह लक्ष्मण रेखा ही होगी, जिसे पार करना किसी के हित में नहीं होगा।

हमारी संस्कृति में जो सर्वाधिक प्रचलित स्व-प्रमाणित मान्यताएं हैं, उनमें से सबसे खतरनाक यह है कि वृद्धावस्था का मतलब गिरावट और खराब सेहत है। *-मर्लिन फर्ग्यूसन*

जीवन का सबसे सार्थक अध्याय

वृद्धावस्था को बोझ मानने के बजाय एक गौरवमयी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि आपकी परिपक्वता ही वह अंतिम उपहार है, जो आप इस संसार को दे सकते हैं। जीवन का अंतिम अध्याय वास्तव में सबसे अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो सकता है।

अक्सर समाज हमें यह महसूस कराता है कि वृद्धावस्था जीवन की वह शाम है, जहां ऊर्जा और उपयोगिता समाप्त होने लगती है। लेकिन जिंदगी का यह पड़ाव केवल शरीर के कमजोर होने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चरित्र के निखार की अवस्था है। जैसे एक पुराने पेड़ की छाल जितनी खुरदरी होती है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी और उसकी छाया उतनी ही शीतल होती है, वैसे ही उम्र का बढ़ना वास्तव में आपके चरित्र के पूर्णता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है।

जेम्स हिलमैन

जिस प्रकार एक पुरानी इमारत के पत्थर अपनी रगड़ और दरारों के बावजूद मजबूती और इतिहास का परिचय देते हैं, ठीक उसी तरह वृद्धावस्था में चेहरे की झुर्रियां जीवन के उन अनुभवों का प्रमाण हैं, जिन्होंने हमें गढ़ा है। यह वह अवस्था है, जहां हम अंततः उस सांचे में ढल जाते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने हमें बनाया था। वृद्धावस्था ही वह समय होता है, जब 'आप क्या करते हैं' से ज्यादा महत्वपूर्ण 'आप कौन हैं' हो जाता है।

दरअसल वृद्धावस्था में ही प्रकृति हमें वह समय और एकाग्रता प्रदान करती है, जिससे हम अपने भीतर झांक सकें और अपनी यादों को एक नए अर्थ के साथ संजो सकें। यादों का यह खजाना अतीत में भटकना नहीं है, बल्कि यह जीवन की पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोकर उसके सार को समझने की एक आध्यात्मिक साधना है।

मुड़-मुड़ के देख

मेरा मानना है कि उम्र बढ़ने का उद्देश्य केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने 'अस्तित्व के सार' को पूरी तरह से प्रकट करना है, जो जवानी की भागदौड़ में कहीं ओझल हो गया था। इस उम्र में आपकी उपस्थिति, स्थिरता और शांति नई पीढ़ी के लिए एक ठंडी छांव की तरह काम करती है।

अतः उम्र के इस पड़ाव को बोझ मानने के बजाय एक गौरवमयी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि आपकी परिपक्वता ही वह अंतिम उपहार है, जो आप इस संसार को दे सकते हैं। आपकी चेतना व अनुभव का विस्तार असीम है, जो सिद्ध करता है कि जीवन का अंतिम अध्याय वास्तव में सबसे अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो सकता है।

उपहार से ज्यादा भावनाओं का है महत्व

आर्थिक संकट से जूझ रही 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने उपहार के संबंध में कुछ यों सलाह दी-

मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूं। पति की मौत के बाद, मेरी कोई आमदनी नहीं है, ऐसे में खास मौकों पर परिवारजनों को उपहार देने के लिए मैं क्या कर सकती हूं?

संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का अपने बच्चों, नाती-पोतों और नातिन-पोतियों को आशीर्वाद के तौर पर नकद या तोहफे देना एक पुरानी परंपरा है। इसकी जड़ें पुरुष-प्रधान व्यवस्था में हैं, जहां पैसे पर परिवार के सबसे बड़े आदमी का नियंत्रण होता था। पारंपरिक रूप से, खास मौकों पर बच्चों का अपने बड़ों के पैर छूना और बड़े-बुजुर्गों का उन्हें नकद या सोने-चांदी के गहने के रूप में आशीर्वाद देना आम बात हो गई है। पर, आज की बढ़ती महंगाई के दौर में सभी बुजुर्ग, विशेषकर महिलाएं इसका भार नहीं उठा पाती हैं। सोने-चांदी के भाव आज इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन सब रीति-रिवाजों को निभाना एक बड़ा बोझ बन गया है। यह सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, बल्कि कई बुजुर्गों ने अपनी बातचीत में मुझसे यह समस्या साझा की है।

जैसा कि मैंने अन्य लोगों को सलाह दी है, आपको भी सुझाव देना चाहता हूं कि अपने परिवार के लोगों, खासकर बेटों से खुलकर बात करें। सबसे पहले, उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछें। आपके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप उनसे कहें कि वे आपकी तरफ से शगुन के तौर पर उपहार का एक लिफाफा तैयार कर लें।

दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप सक्षम हों, तो सोने के गहनों के बदले चांदी का सिक्का देना शुरू करें-यह शगुन की निशानी होगी और अपेक्षाकृत सस्ती भी। निराश होने या अपराध-बोध से ग्रसित होने के

बजाय अपनी कोई आमदनी न होने पर भी आप प्यार और भावनाओं से भरे हस्तनिर्मित उपहार देकर परिवार के लोगों को खुश कर सकती हैं। समय, मेहनत और रचनात्मकता से बनाए गए उपहार महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। आप हस्तनिर्मित कार्ड, पुरानी यादों का कोलाज फोटो फ्रेम देकर भी उन्हें खास महसूस करा सकती हैं। हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड, पेंटिंग्स, या किसी पुरानी तस्वीर को इस तरह से सजाएं, जो देखने में अनूठी लगे और प्रेम दर्शाती हो। यदि घर में कोई पुरानी वस्तु हो, तो उसे सजाकर या पेंट करके उपहार के तौर पर दे सकती हैं।

उपहार देने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए आप अपनी आर्थिक हैसियत देखकर ही उपहार दें। चूंकि, आप संयुक्त परिवार में रहती हैं, तो उपहार देना लाजिमी है। इसलिए ऐसा उपहार दें, जिससे किसी को भेदभाव का आरोप लगाने का अवसर न मिले और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता पर भी आंच न आए। असल में, उपहार में कीमती वस्तु से ज्यादा भावनाओं का महत्व होता है, इसलिए खुलकर अपने प्यार का इजहार करें। आखिरकार, इन खास पलों में खुश रहने का हक आपको भी है। समाज व सामाजिक परिपाटी को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें!

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

94 की उम्र में जज्बे की नई मिसाल 'गोल्डन ग्रैंडमा'

94 साल की उम्र में जहां लोग अक्सर शारीरिक शिथिलता को स्वीकार कर लेते हैं, वहीं राजस्थान की पानी देवी, जिन्हें प्यार से 'गोल्डन ग्रैंडमा' कहा जाता है, ने उम्र के बंधनों को तोड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। झुंझुनू जिले की रहने वाली पानी देवी गोदारा ने हाल ही में एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप और राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में अपनी उम्र के वर्ग (90 वर्ष से अधिक) में अलग-अलग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह गोला फेंक (शॉट पुट), चक्का फेंक (डिस्कस थ्रो) और भाला फेंक (जेवलीन थ्रो) जैसे कठिन खेलों में भाग लेती हैं। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी इस साधारण महिला ने कभी खेल प्रशिक्षण नहीं लिया, पर सक्रिय जीवनशैली और मेहनत ने उन्हें अद्भुत शारीरिक क्षमता दी। वह आज भी अपने घरेलू कामों को खुद ही करना पसंद करती हैं तथा शुद्ध देसी खान-पान (दूध, दही और बाजरा) को अपनी ऊर्जा का स्रोत बताती हैं। उनकी जीत यह संदेश देती है कि यदि मन में उत्साह हो, तो शरीर भी साथ देने लगता है।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट* बुजुर्गों को परिवार जैसा खुशनुमा माहौल प्रदान करता है, जहां उनके सम्मान, बेहतर देखभाल व भावनात्मक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां 24/7 चिकित्सा सहायता और पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध है। संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर कर उन्हें एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना है। यहां बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए समय-समय पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, उन्हें वाई-फाई और इंटरनेट से जोड़कर देश-दुनिया से भी अपडेट रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट sheetalchaya.org या 7982195899 पर संपर्क कर सकते हैं।
- *सेवाधाम वृद्ध आश्रम* बेसहारा बुजुर्गों या जिनकी कोई संतान नहीं है, की पूरी देखभाल करता है। यह बुजुर्गों की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई पर ध्यान देता है, और जरूरतमंद वरिष्ठजनों के लिए एक मददगार और सम्मानजनक माहौल देता है। अधिक जानकारी के लिए 7011084730 पर संपर्क किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

मुफ्त योजना पर चोट

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही मुफ्त योजनाओं की जो कड़ी आलोचना की है, वह स्वागतयोग्य है। न्यायालय ने साफ कहा है- ऐसी योजनाओं से विकास में बाधा आती है, अतः ऐसी नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। न्यायालय की यह टिप्पणी तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में सामने आई है। कुल मामला यह है कि तमिलनाडु की सरकार वहां सभी को मुफ्त बिजली देना चाहती है। फिलहाल वहां प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली मुफ्त है और नई योजना अगर लागू हुई, तो यह राज्य पूरी तरह मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ा देगा। गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात समझ में आती है, मगर सक्षम लोगों को भी मुफ्त बिजली देने का क्या मतलब है? न्यायालय ने इसी दलील के साथ मुफ्त योजनाओं का विरोध करते हुए बिल्कुल सही कहा है कि ऐसी योजनाओं के जरिये संसाधन बांटने के बजाय, सरकारों को ऐसी सुनियोजित नीतियां लागू करनी चाहिए, जो लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के उपाय करें, बेरोजगारी दूर हो। न्यायालय की फटकार वाजिब है, अगर हर चीज मुफ्त मिलने लगेगी, तो काम करना कौन चाहेगा? क्या कार्य संस्कृति खराब नहीं हो जाएगी?

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली का विश्लेषण प्रशंसनीय है कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में है और फिर भी वे विकास की अनदेखी करते हुए ऐसी मुफ्त योजनाएं पेश करते रहते हैं। सवाल यह भी है कि सरकारें चुनाव से ठीक पहले क्यों मुफ्त योजनाएं लाती हैं? मुफ्त योजनाओं के बजाय सरकारों को विकास पर अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। अगर समाज में मुफ्तखोरी बढ़ेगी, तो कमाएगा कौन? अगर नहीं कमाएगा, तो टैक्स कौन चुकाएगा? टैक्स नहीं चुकाएगा, तो सरकारों के पास राजस्व कैसे आएगा? अगर सरकारों के पास राजस्व नहीं आएगा, तो गरीबों की मदद कैसे होगी या देश का विकास कैसे होगा? हालांकि, यह आज की राजनीति का एक स्थापित पहलू है कि हर पार्टी मुफ्त योजनाओं से सियासी फायदा उठाना चाहती है। एक दुखद राजनीतिक धारणा यह भी है कि विकास से वोट नहीं मिलते हैं और असंख्य मतदाता अपना तात्कालिक लाभ देखते हैं। ऐसे में, सियासी दलों की मदद भी तात्कालिक होने लगी है। बहरहाल, एक समस्या और है। अब तमिलनाडु में यह सियासत होगी कि तमिलों के हित में आ रही योजना को रोका जा रहा है, जबकि बिहार में जब मुफ्त रेवड़ियां बंट रही थीं, तब नहीं रोका गया। क्या ऐसी सियासत या उसकी मुफ्त योजनाओं पर कोई लगाम लगा सकता है?

क्या सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा नीति-निर्देश जारी कर सकता है, जिससे मुफ्त योजनाओं की हदें तय हो जाएं? मुफ्त योजनाओं से विकास प्रभावित न हो सके।

वैसे, भारत में कोई पहली बार नहीं है, जब मुफ्त योजनाओं पर आपत्ति जताई गई है। अनेक नेता ऐसी मुफ्त योजनाओं पर आपत्ति जता चुके हैं। हालांकि, ऐसे नेता भी हैं, जो इन योजनाओं का बचाव करते हैं। द्रमुक के नेता दयानिधि मारन ने ही कहा है कि ये योजनाएं खैरात नहीं, सशक्तीकरण का प्रयास हैं। न्यायालय भी एक हद तक यही मानता है। उसे आपत्ति केवल इस बात पर है कि मुफ्त का लाभ सक्षम लोगों को क्यों मिले? न्यायालय का तर्क ठीक है, पर आगे की राह कैसी है? क्या न्यायालय ऐसा कोई दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जिससे मुफ्त योजनाओं की हदें तय हो जाएं? क्या न्यायालय चुनाव से पहले किसी राजनीतिक पार्टी को मुफ्त योजनाओं की घोषणा या क्रियान्वयन से रोक सकता है? फिलहाल, यह सिर्फ एक उम्मीद भर है- एक दिन आएगा, जब मुफ्त योजनाओं का दुरुपयोग रुक जाएगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 फरवरी, 1951

नेपाल में नया अध्याय

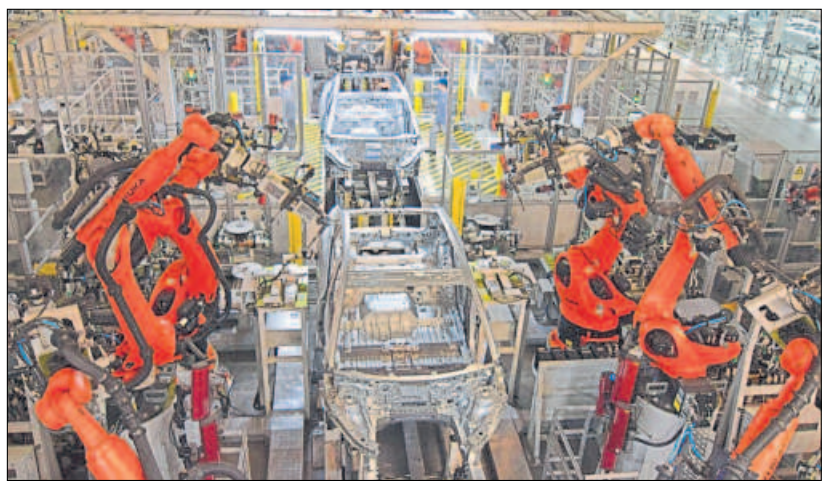

महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम की ताजा घोषणा के साथ नेपाल राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। उनकी यह घोषणा उस समझौते के अनुरूप है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा मोहन शमशेर और नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच भारत सरकार की मध्यस्थता में सम्पन्न हुआ था। घोषणा में महाराजाधिराज ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि भविष्य में नेपाल का शासन लोकतंत्री संविधान के अनुसार चलाया जाये, जिसका निर्माण जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा करेगी। जब तक यह संविधान नहीं बन जाता, तब तक नेपाल का शासन चलाने के लिए उन्होंने एक मिले-जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, जिसमें पांच मंत्री प्रधानमंत्री मोहन शमशेर की ओर के और पांच नेपाली कांग्रेस के लिये गये हैं। नयी सरकार के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर होंगे और वह संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करेगी और महाराजाधिराज के प्रति उत्तरदायी होगी और उस समय तक अधिकारारूढ़ रहेगी, जब तक महाराजाधिराज की विश्वास भाजन रहेगी।... नेपाल के नये मंत्रियों ने अपने पदों की शपथ ग्रहण कर ली है और यह शपथ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम ने स्वयं दिलाई है।

गत वर्ष 7 नवम्बर को महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम ने अपने परिवार सहित भारतीय दूतावास में शरण ली थी। उसके बाद वह नयी दिल्ली चले आये। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर ने महाराजाधिराज को पदच्युत करके उनके स्थान पर तीन वर्षीय शिशु को नेपाल की गद्दी पर बिठा दिया। इधर तो नेपाल के महाराजाधिराज ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, उधर नेपाली कांग्रेस ने नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध बगावत कर दी। नेपाल की इन घटनाओं पर भारत के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक है। हिमालय के उस पार तिब्बत की उथल-पुथल ने उसकी चिन्ता को और बढ़ा दिया था।... भारत ने दृढ़तापूर्वक नेपाल के शिशु नरेश को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। ब्रिटेन और अमरीका ने भी इस मामले में भारत की विशेष स्थिति को मानते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे स्थिति पेचीदा होती। जहां तक ज्ञात हुआ है, इन देशों ने नेपाल के प्रधानमंत्री को यही परामर्श दिया कि वह भारत की सहायता से नेपाल की समस्या को हल करने की कोशिश करें।

देशों की आर्थिक दशा बदलती एआई

दुनिया में इससे पहले जो भी तकनीकी बदलाव हुए, उनसे हमारे भौतिक कामकाज प्रभावित हुए थे, लेकिन एआई तमाम अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रभावित करने लगी है।

यहां स्कैन करें

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

नई दिल्ली में चल रहा 'एआई इम्पैक्ट समिट' अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था पर एआई के बढ़ते प्रभाव पर हुई चर्चाएं अहम हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब इस नई तकनीक से प्रभावित होने लगी हैं। यह कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि एआई एक क्रांतिकारी तकनीक है।

इससे पहले जो भी तकनीकी बदलाव हुए हैं, उन्होंने कमोबेश शारीरिक श्रम पर असर डाला था। उनसे हमारे भौतिक कामकाज प्रभावित हुए थे, पर एआई कुशल कामगारों को प्रभावित कर रही है। एआई समिट में यह भी चर्चा हुई कि इससे लोगों की उत्पादकता कितनी बढ़ रही है और उनके काम करने के तरीके कितने बदल रहे हैं। यह बदलाव काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि एआई में निवेश काफी ज्यादा हो रहा है। मसलन, पिछले साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के बुनियादी ढांचे को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए लगभग 500 अरब डॉलर तक के निवेश की घोषणा की। वहां 'मेटा' जैसी बड़ी कंपनियां भी अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। चीन भी इस तरह के कामों में पीछे नहीं है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो देश एआई में सर्वोच्चता हासिल कर लेगा, वह विश्व-व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बना लेगा।

यही वजह है कि एआई को 'पब्लिक गुड्स' के रूप में विकसित करने की वकालत की जाती है, ताकि यह सबको सुलभ हो और सभी इसका इस्तेमाल कर सकें। यह मांग इसलिए भी हो रही है, क्योंकि एआई से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। यह किसी उद्योग के लिए जरूरी शोध कर सकती है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तत्काल बता सकती है कि कहां उसके लिए बेहतर कच्चा माल उपलब्ध है और कहां से उसे लाना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। इसी तरह, मार्केटिंग की रिपोर्ट तैयार करने में भी एआई से काफी मदद मिलती है। कहां और किस क्षेत्र में कैसी मांग है, इससे यह पता करना आसान हो जाता है। यानी, सूचनाएं उपलब्ध रहने से तमाम उद्यमों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इस तरह उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है।

इसी तरह, नए-नए शोध में एआई से फायदा मिल सकता है। मिसाल के लिए, अब प्रोटीन की संरचना समझने के लिए 'अल्फाफोल्ड' सॉफ्टवेयर की मदद ली जाने लगी है। यह प्रोटीन की थ्रीडी संरचना बना देती है, वह भी थोक के भाव से। पहले प्रोटीन की एक संरचना के विश्लेषण के लिए एक शोध-कार्य होते थे, लेकिन 'अल्फाफोल्ड' हजार शोध के बराबर काम करने में सक्षम है। इससे दवाओं के निर्माण में फायदा होता है। इस जैसे तमाम पेशेवर कामों में अब एआई की भागीदारी संभव होगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम किसी डॉक्टर या सीए के इंटर्न के रूप में किसी एआई मॉडल को सेवा देते देखें।

एआई भाषायी बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को मदद कर सकती है। अभी सुदूर देशों के साथ संपर्क साधना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्यमी भाषायी तौर पर कुशल नहीं होते, लेकिन एआई द्वारा आसानी से मूल भाषा में अनुवाद करके सामग्री उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिल सकती है। इससे नई-नई चीजों के ईजाद में काफी सहायता मिलेगी और कामकाज में तेजी आ सकेगी।

जीवन-स्तर की गुणवत्ता में एआई द्वारा सुधार लाना आर्थिक नजरिये से सुखद माना जाता है। एआई पेशेवर लोगों की क्षमता बढ़ाने में मददगार होगी। इससे उनके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सूचनाएं न सिर्फ काफी तेजी से आ सकेंगी, बल्कि उनका गहन विश्लेषण भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे कर्मियों की क्षमताओं में इजाफा होगा। वित्तीय बाजार पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और वित्तीय योजनाएं बनाने में एआई पेशेवरों की मदद कर सकेगी।

हालांकि, इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस पर हमें कहीं अधिक संजीदगी से काम करना होगा। जैसे, सन माइक्रोसिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला ने एआई समिट में बताया कि एआई की वजह से पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं और 2030 तक कॉल सेंटर व बीपीओ जैसे कामों में लोगों की जरूरतें खत्म हो सकती हैं। जाहिर है, अब काम करने के तरीके बदल रहे हैं और उसी बदलाव के अनुसार हमें लोगों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत में महत्वाकांक्षी नौजवानों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है।

एआई से कुछ क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन भी होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में मांग घट सकती है, जिसके लिए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा और कौशल जिनके पास होगा, वे आगे बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि एआई में अमेरिका और चीन की तेजी को बाकी दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे देशों के बीच ठीक उसी तरह असमानता बढ़ सकती है, जिस तरह समाज में कुशल और अकुशल लोगों के बीच गैर-बराबरी है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि एआई-सक्षम देश नव-साम्राज्यवादी ताकत बन सकती हैं और वे उन मुल्कों पर दबाव बना सकती हैं, जो एआई अपनाने में कमजोर रहेंगी। इससे दुनिया में आर्थिक विषमता का एक नया चक्र शुरू हो सकता है।

अच्छी बात है कि एआई से अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए भारत जैसे देश लगातार काम कर रहे हैं। हमें कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला है, शोध कार्यों के लिए माहौल सुधारना। इसके लिए उच्च शिक्षण व शोध संस्थानों को पहल करनी चाहिए और शोध-संबंधी माहौल की जो कमियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को भी शोध व विकास पर अपने खर्च बढ़ाने होंगे।

दूसरा काम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। बेशक, नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी नई-नई तकनीक को समझ सकें, लेकिन कक्षा के मुताबिक उनकी मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। 'कैसे हमें सीखना चाहिए' यह सीख हमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बच्चों को सिखानी होगी। अच्छा होगा, भारत यह पहल करे कि 'ग्लोबल साउथ' के देश आपस में मिलकर एआई पर काम करें। इससे एआई का हर मोर्चे पर अधिकतम फायदा उठाया जा सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अपनी बातों पर कितने खरे उतर पाएंगे तारिक रहमान

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

यहां स्कैन करें

संजय कुमार भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर सत्ता की बागडोर संभाल ली है। पिछले 18 महीने के गतिरोध के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक स्थायित्व के लिहाज से इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। नई सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के चार सांसदों में से दो को मंत्री बनाया गया है। राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने जिस तरह अल्पसंख्यकों की दिलजोई की, उससे यही उम्मीद बांधी जा सकती है कि यह सब प्रतीकात्मक भी हो, तब भी बांग्लादेश वापस पटरी पर आ सकता है।

हालांकि, बीएनपी का इतिहास इस्लामी राजनीति में अधिक विश्वास करने का रहा है, मगर बांग्लादेश की जनता ने इसे अवामी लीग के विकल्प के रूप में देखा है। अतः नई सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाली संस्कृति की मुख्य पक्षधर पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। जमात-ए-इस्लामी 68 सीटों के साथ सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जो कट्टर इस्लामी विचारधारा में यकीन रखती है। अतः धर्मनिरपेक्ष व अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए आंतरिक व बाहरी दबाव परस्पर बना रहेगा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि बेगम खालिदा जिया (अब दिवंगत) के नेतृत्व में बांग्लादेश में बीएनपी की जो सरकार बनी थी, उसने भारत से दूरी बनाए रखी और पाकिस्तान-चीन से नजदीकी बढ़ाई थी। खालिदा जिया के पति और तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान बीएनपी के संस्थापक थे और सत्ता में आने पर उन्होंने ही बांग्लादेश को बंगाली राष्ट्रवाद से बांग्लादेशी राष्ट्रवाद में तब्दील किया था, जिसके मूल में इस्लाम रहा। जियाउर रहमान के दौर में इस्लामी देशों से बांग्लादेश के संबंध मधुर हुए। खालिदा जिया ने वही नीति जारी रखी। भारत ने 1991 और 2001 के चुनावों में बीएनपी पर विश्वास दिखाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस पार्टी की हुकूमतों ने भारत विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाया। अतः संबंध अच्छे नहीं रहे।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों को मंत्री बनाना प्रतीकात्मक भी हो, तब भी यह पड़ोसी देश के पटरी पर लौटने के संकेत देता ही है।

हालांकि, बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद ढाका लौटे तारिक रहमान ने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में जो कुछ कहा, उसका अर्थ यह था कि वह बीएनपी की पहले की नीतियों में बदलाव करेंगे तथा इस्लामी राष्ट्रवाद की जगह सहिष्णुता और उदारवाद को तरजीह देंगे, लेकिन बीएनपी के इतिहास को देखते हुए इस पर बहुत भरोसा करना मुश्कल है। वैसे भी, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो यह कि नई सरकार पर जुलाई चार्टर को, जिसे जमात समर्थित यूनुस सरकार ने बनाया था, लागू करने का भीषण दबाव है। जमात बांग्लादेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, एनसीपी के साथ वह शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करके अपना रुख जगजाहिर कर चुका है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में अब भी अवामी लीग के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। देखने वाली बात है कि तारिक सरकार का अवामी लीग के प्रति क्या रुख रहता है? जिस तर्ज पर तारिक रहमान को माफ किया गया, उसी तरह क्या वह अवामी लीग की ज्यादतियां माफ कर सकेंगे? क्या जमात-ए-इस्लामी कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने का काम करती रहेगी? फिर पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। भारत ने भी बांग्लादेश से जुड़ी मदद-राशि कम कर दी है। बांग्लादेश में मुद्रास्फीति बढ़ गई है और पिछले 18 महीनों में निवेश कम हुआ है। वेतन-वृद्धि व रोजगार का सरकार पर दबाव है। अतः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है। इसमें भारत एक अच्छा सहयोगी हो सकता है।

बांग्लादेश में भारत का लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश है, ऐसे में नई दिल्ली की अनदेखी ढाका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। आपसी विवाद और सुरक्षा के मुद्दे दोनों देशों को उलझा सकते हैं। तारिक सरकार को समझना होगा कि भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववाद का किसी किस्म का समर्थन द्विपक्षीय संबंध को गंभीर ठेस पहुंचाने वाला होगा। संतुलित विदेश नीति उसे स्थायित्व प्रदान करेगी। बांग्लादेश को यह भी समझने की जरूरत है कि विश्व परिदृश्य बदल चुका है। कट्टर इस्लामी मुल्क भी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, विकास ही बांग्लादेश के जेन-जी की भी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बंधना नहीं, मुक्त होना

जो भी चीज हमारे जीवन से संबंध रखती है, उसकी जिम्मेदारी हम अपने हाथों में ले लेते हैं और जब किसी चीज को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते, तो ईश्वरीय इच्छा या नियति की बातें करने लगते हैं। इस समय भी आप अपने जीवन में चुनाव अचेतन तरीके से कर रहे हैं। इसे ही कर्म कहते हैं। आप अपनी नियति पूरी लापरवाही, पूरी बेखबरी में रच रहे हैं। आप जो भी अचेतन होकर कर रहे हैं, अगर उसे सचेतन तरीके से करने लगें, तो जमीन-आसमान का फर्क आ जाएगा। यही फर्क अज्ञानता और आत्मज्ञान के बीच होता है।

अपना भाग्य अपने हाथों में लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके मन-मुताबिक होने लगेगा। बाहरी दुनिया कभी सौ फीसदी आपके मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें तमाम दूसरे पहलू शामिल होते हैं। बाहरी दुनिया को अपने मुताबिक चलाने की चाहत का मतलब है- निरंकुश होना। भाग्य बनाने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया की हर परिस्थिति आपके काबू में हो। इसका मतलब बस इतना है कि खुद को इस तरह का बनाएं कि आपके आस-पास चाहे कैसी भी घटना या परिस्थिति क्यों न हो, आप उनके बोझ तले चकनाचूर होने के बजाय उनसे पार पाना सीख जाएं। असल में, इसका मतलब अपनी परम प्रकृति को प्राप्त करने की ओर बढ़ना है।

तो उन सितारों, ग्रहों का क्या, क्या वे हमारी किस्मत तय नहीं करते? अगर आपकी किस्मत उन ग्रहों और सितारों द्वारा तय होती, तो इसका मतलब होता कि आप अपनी इच्छा से न जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं। आप अपने जीवन के बारे में कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से तय नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ अपनी कुंडली के चश्मे से देख रहे होते हैं!

क्या निर्जीव चीजों को इंसान की दिशा और भाग्य तय करना चाहिए या इसका उल्टा होना चाहिए? अगर आप खुद में अच्छी तरह से स्थित हैं, तो चाहे आपके ग्रह आपको किसी भी दिशा में मोड़ना चाहें, आप उसी दिशा में जाएंगे, जहां आप जाना चाहते हैं। अगर लोगों को दूसरे ग्रहों की चिंता कम और धरती माता की ज्यादा होती, तो कम से कम हम थोड़ा बेहतर जीवन जी सकते थे!

इसलिए आप जिसे 'भाग्य' कहते हैं, वह ऐसी चीज है, जिसे आपने खुद के लिए अचेतन तरीके से बनाया है। कर्म एक प्रक्रिया है; भाग्य उसका परिणाम है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। कार्य तमाम तरह के होते हैं- शारीरिक, मानसिक/भावनात्मक और ऊर्जा से किए गए कार्य। अगर इन कार्यों की अभिव्यक्ति बाहर की ओर होती है, तो यह कर्म है। शरीर, मनोभावना और ऊर्जा से परे, अगर कार्य भीतर की ओर किया जाता है, तो उसे 'क्रिया' कहते हैं। याद रखिए, कर्म आपको बांधने की प्रक्रिया है और क्रिया आपको मुक्त करने की प्रक्रिया।

कार्यों की अभिव्यक्ति बाहर की ओर होती है, तो यह 'कर्म' है। अगर कार्य भीतर की ओर किया जाता है, तो उसे 'क्रिया' कहते हैं। कर्म आपको बांधने की प्रक्रिया है और क्रिया मुक्त करने की।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

आध्यात्मिकता की असली उपयोगिता हमारे व्यावहारिक जीवन में है। अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करना ही कर्मयोग है। सेवा भाव से कर्म करना और उनके फल समाज को अर्पित करना, सर्वोच्च कोटि का कर्मयोग है।

इमरान खान के साथ इंसाफ होना चाहिए

दुनिया के 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों द्वारा पाकिस्तान सरकार से इमरान खान को उचित उपचार मुहैया कराने की अपील यह बताती है कि खेल आज भी इंसानियत और भाईचारे की सबसे बड़ी पनाहगाह है। इस खबर ने खेल की दुनिया के संवेदनशील पहलू को रेखांकित किया है। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने दुनिया के 12 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों के साथ मिलकर पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज की सुविधा देने और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की गई है।

बताते हैं, इमरान खान की दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत रोशनी हिरासत में चिकित्सकीय उपेक्षा के कारण चली गई है। वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। लगभग ढाई वर्षों से जारी कैद और उससे जुड़ी परिस्थितियों ने पूर्व क्रिकेट कप्तानों को बेचैन कर दिया है। उन्होंने इमरान खान के साथ हो रहे गलत व्यवहार और उनकी कैद की परिस्थितियों पर गहरी चिंता जताई है।

यह सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए लिखी गई चिट्ठी नहीं है, बल्कि उस भावना का इजहार है, जिसे क्रिकेट की दुनिया 'फेयर प्ले', 'ऑनर' और 'रिस्पेक्ट' के नाम से जानती है। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले तमाम कप्तान कभी मैदान पर इमरान के प्रतिद्वंद्वी रहे, मगर आज एक स्वर में उनके लिए गरिमापूर्ण व्यवहार की मांग कर रहे हैं। क्रिकेट को अक्सर देशों के बीच पुल कहा गया है। जब स्टंप उखाड़े जाते हैं, तो प्रतिद्वंद्विता वहीं समाप्त हो जाती है, बाकी बचता है सम्मान। 1992 के विश्व कप में पाकिस्तान को ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले इमरान खान सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वह उस पीढ़ी के प्रतीक हैं, जिसने खेल को जज्बे, नेतृत्व और आत्मविश्वास से भरा।

राजनीति में वैचारिक-नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, मगर बीमारी और बुनियादी मानवीय गरिमा का सवाल राजनीति से ऊपर उठ जाता है। पूर्व कप्तानों की यह अपील किसी कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि शिष्टता और न्याय के सिद्धांतों को याद दिलाने की कोशिश है। ऐसे दौर में, जब भीड़ का शोर इंसानियत की आवाज को दबा देता है, क्रिकेट के ये बुजुर्ग सितारे हमें याद दिला रहे हैं कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह संस्कार भी है। शायद यही वह रोशनी है, जो किसी के एक आंख की नहीं, पूरी दुनिया की नजर बचा सकती है।

पंकज शुक्ला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

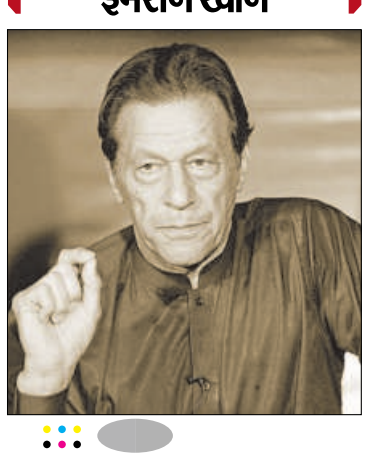

इमरान खान

अपना ही बोया हुआ वह जेल में काट रहे

इमरान खान इतने महान इंसान नहीं हैं कि उन्हें जेल में सुविधाएं दिलाने के लिए पूर्व क्रिकेट कप्तानों को चिट्ठी लिखनी पड़े। खेल भावना की नजर से भले ही यह सही लगे, लेकिन राजनीति विज्ञान का छात्र होने के नाते जब उनका आकलन करता हूं, तो इमरान खान भी पाकिस्तान के उन प्रधानमंत्रियों जैसे जान पड़ते हैं, जिनका रुख भारत-विरोधी रहा है। अपनी फौज की तारीफ में तो उन्होंने यहां तक कहा था कि लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन और इराक जैसे मुल्क ही नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया संघर्ष में उलझी हुई है, जबकि पाकिस्तान सुरक्षित है, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी फौज है। अगर यह फौज नहीं होती, तो पाकिस्तान कई हिस्सों में बंट चुका होता।

इमरान खान पाकिस्तानी फौज के कितने बड़े रबर स्टैंप थे, यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें पाकिस्तानी फौज की बदौलत ही प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी, इसीलिए वह उसके इशारों पर चलते रहे। सरकार के कई बड़े पदों को उन्होंने पाकिस्तानी जनरलों के हवाले कर दिया था। बस, सेना से खटपट शुरू हुई, तो उनकी सत्ता चली गई। ऊपर से उन्होंने फौज से सीधे-सीधे लड़ाई मोल ले ली, इसलिए आज वह इतने बुरे दिन देख रहे हैं। वास्तव में, सत्ता में रहते हुए उन्होंने कमोबेश वही सब किया, जो फौज उनसे कहती रही। ऐसे में, स्वाभाविक ही वह अपनी फौज की तरह भारत के खिलाफ दुराग्रह पाले हुए दिखते थे। इमरान खान भारत के खिलाफ कैसी सोच रखते थे, इसका अंदाजा इस खबर से भी होता है कि पिछले साल मई में जब उनकी बहनों को जेल में उनसे मिलने दिया गया, तो उन्होंने मुलाकात में हुए संवाद में भारत की चर्चा होने की बात भी कही। बहनों के मुताबिक, इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज और हुकूमत को आगाह किया कि वे भारत से चौकन्ना रहें। उन्होंने इमरान खान के चिंतित होने की बात भी कही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से 'नफरत' करने वाला व्यक्ति बताया था।

ऐसे कई उदाहरण हैं, जो इमरान खान की मंशा स्पष्ट करते हैं। वह सत्ता में बने रहना चाहते थे, जिसके लिए उनको भारत से दुश्मनी मोल लेने से भी गुरेज न था, जबकि हमारे यहां के एक नामचीन खिलाड़ी उनके शपथ-ग्रहण में वहां गए थे। कहने का मतलब यही है कि हर बार दोस्ती का हाथ हमारी तरफ से ही बढ़ा, इमरान खान ने तो बस इस्तेमाल करना सीखा। इसलिए, आज अगर वह जेल की कोठरी में बंद हैं, तो अफसोस नहीं होता। वह अपना बोया हुआ ही काट रहे हैं।

साहिल, टिप्पणीकार

प्रत्येक परिवर्तन चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लाता है

बोझ बनी मुफ्त की संस्कृति

यह पहली बार नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां कही जाने वाली लोकलुभावन योजनाओं पर अपनी आपत्ति और चिंता प्रकट की हो। वह कई बार यह कह चुका है कि मुफ्त की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा है। गत दिवस भी उसने सरकारों की ओर से मुफ्त सुविधाएं और वस्तुएं देने के चलन पर यह प्रश्न किया कि यदि वे इसी तरह फ्री अनाज, बिजली, साइकिल आदि देते रहे तो विकास के लिए धन कहां से आएगा? उसने इस पर भी बल दिया कि सरकारें मुफ्त की सुविधाएं और सामग्री के स्थान पर रोजगार दें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल यह मान चुके हैं कि लोकलुभावन योजनाएं चुनाव जीतने की गारंटी बन गई हैं। इसका परिणाम यह है कि चुनाव आते ही सत्तारूढ़ दल और सत्ता की चाह रखने वाले विपक्षी दल मुफ्त की योजनाओं का पिटारा खोलने में जुट जाते हैं। अब तो वे सीधे धन देने की भी घोषणा करने लगे हैं। यह तब है, जब अधिकांश राज्य घाटे में हैं। विडंबना यह है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की कमी का रोना रोते हैं और फिर भी मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। साफ है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी करते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आते ही संबंधित राज्य सरकारों की ओर से मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की जाने लगी है। तमिलनाडु सरकार ने हर किसी को फ्री बिजली देने की पेशकश कर दी है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि यह याचिका तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने दायर की है। इसके पहले भी ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। निःसंदेह कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह निर्धन-वंचित वर्गों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए विशेष उपाय करे और उन्हें कुछ मुफ्त या रियायती सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और उन्हें अपने स्तर पर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। बीते कुछ समय से तो वोट हासिल करने के इरादे से ऐसी सुविधाएं देने की पहल होने लगी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का उपहास और संसाधनों का दुरुपयोग भी है। जब सक्षम लोगों को भी मुफ्त की योजनाओं का लाभ दिया जाता है तो लोग एक तरह से काम न करने के आदी बनते हैं और वे शासन पर बोझ बनते हैं। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, जिससे गरीब एवं अक्षम लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने का काम राज्य के आर्थिक संसाधनों के आधार पर हो, न कि मनमाने तरीके से चुनाव जीतने के लिए।

बढ़ेगा भरोसा

राज्य सरकार किसी भी कीमत पर एथनाल प्लांट को बंद नहीं होने देगी। इस आशय की जानकारी उद्योग मंत्री ने विधानपरिषद में दी। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि विशेष परिस्थिति में बिहार का एथनाल का कोटा बढ़ाया जाएगा। यह आश्वासन बिहार के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दिया है। निश्चित तौर पर संकट का सामना कर रहे एथनाल उत्पादन इकाइयों के लिए यह राहत भरी खबर है, वहीं निवेशकों में यह भरोसा भी बढ़ेगा कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

निवेशकों के हितों का ख्याल रखने से उनका भरोसा तो बढ़ेगा ही, औद्योगिक माहौल भी बेहतर होगा।

दरअसल, बिहार में कोटा सीमित होने के कारण प्रदेश के एथनाल प्लांट के उत्पादन में कमी आई, जिससे उनकी कमर टूट रही थी। इन इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों पर भी छंटनी के बादल मंडराने लगे, वहीं इन यूनिटों ने मक्के की खरीद भी कम कर दी। वैकल्पिक बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण मक्के की खेती करने वाले किसान सरकारी समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिचौलियों के हाथों फसल बेचने को मजबूर हो गए। राज्य में मक्के के उत्पादन का अधिकतर हिस्सा एथनाल कंपनियों को ही बेचा जा रहा था। अब बिहार का कोटा बढ़ने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि एथनाल का उत्पादन बढ़ेगा और इसका फायदा किसानों को भी मिल सकेगा। किसानों के समक्ष समस्या है कि वे लंबे समय तक मक्के का भंडारण नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार को मक्के या ऐसे अन्य फसलों के भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हों।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र है?

आज का सवाल

क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का यह सुझाव सही है कि 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए?

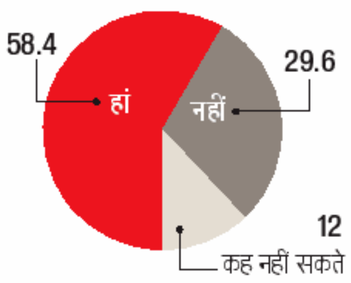

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अपनों को भी अमेरिका से दूर करते ट्रंप

डा. एके वर्मा

ट्रंप की नीतियों के चलते तनाव अन्य देशों के साथ-साथ भारत जैसे अमेरिका के निकट सहयोगियों में भी उसके प्रति संदेह और अविश्वास का माहौल बना है, जो आसानी से दूर नहीं होगा

पूरे विश्व में अमेरिका की प्रतिष्ठा एक आदर्श लोकतंत्र की रही है। उसके उदारवादी मूल्यों को लोकतंत्र का मानदंड माना गया है। हालांकि हाल के समय में उसके प्रति यह धारणा बदलती दिख रही है। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी संस्थानों की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उनका चुनावी नारा मेक-अमेरिका-ग्रेट-अगेन (मागा) यानी 'अमेरिका को पुनः महान बनाना है' रहा। इसमें भी एक आत्मस्वीकृति थी कि अमेरिकी लोकतंत्र अब महान नहीं रहा और ट्रंप उसका पुराना गौरव लौटाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया नहीं कि अमेरिकी महानता के कौन-कौन से स्तंभ धराशायी हो गए हैं, जिनका वे पुनरुत्थान करना चाहते हैं। जब सोवियत संघ के बिखरने के बाद एकध्रुवीय विश्व में अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया, तब ट्रंप की चिंता के क्या कारण हो सकते हैं? संभवतः बदलता भू-राजनीतिक, मौद्रिक और प्रतिरक्षा संबंधी परिदृश्य ट्रंप को चिंतित कर रहे हैं।

भू-राजनीतिक परिदृश्य पर चीन एवं भारत के उभार से 21वीं सदी एशिया की हो चली है। ट्रंप ने आर्थिक-उपनिवेशवादी मानसिकता से तमाम देशों पर टैरिफ लगाया। उससे न केवल भारत, चीन और रूस निकट आए, वरन अमेरिका के सहयोगी देश कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी चीन एवं भारत की ओर रुख कर लिया। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में अमेरिकी विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिस आक्रामकता से ट्रंप ने टैरिफ वार चलाया, जिस बड़बोलेपन का प्रयोग उन्होंने 'वैश्विक-राजनय' में किया, जिस निर्लज्जता से 'नोबेल शांति पुरस्कार' के लिए लालसा दिखाई, जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदी बनाया, जिस नव-साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोका, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि एक 'अंतरराष्ट्रीय दादा' जैसी हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय-कानून और कूटनीतिक-शिष्टाचार को धता बता कर कुछ भी करने पर आमादा हैं। एक ओर वे पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताते नहीं थकते तो दूसरी ओर उन्हें उकसाने के लिए अनर्गल प्रलाप भी करते रहे। उन्होंने आपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता का दावा किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनमी' बताया, जबकि भारत विश्व की चौथी बड़ी आर्थिकी है, जो कुछ ही समय में तीसरे पायदान पर पहुंचने के निकट है।

ट्रंप की नीतियों से न केवल एशिया,

अवधेश राजपूत

अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, वरन अमेरिका के निकट सहयोगियों में भी उसके प्रति संदेह और अविश्वास बढ़ गया। इससे एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेती दिख रही है। ट्रंप इसे समझते हैं और इसीलिए उन्होंने गाजा शांति बोर्ड जैसी पहल कर स्वयं को उसका आजीवन मुखिया भी नामित कर लिया, जिसके पास अंतिम निर्णायक वीटो होगा। ऐसी पहल स्थापित अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बन उसे प्रतिस्थापित करने का कुत्सित प्रयास भी है।

मौद्रिक मोर्चे को लेकर भी ट्रंप तनाव में हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में डालर का बोलबाला है। वैश्विक मुद्रा विनिमय में अमेरिकी बैंकों तथा स्विफ्ट जैसी व्यवस्थाओं का एकाधिकार है। इनका प्रयोग अमेरिका सभी देशों के विरुद्ध हथियार के रूप में करता रहा है। जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने 2022 में रूस के मुद्रा भंडार पर रोक लगा दी। यह एक खतरे की घंटी ही थी। इससे सबक लेते हुए भारत ने अमेरिकी गोल्ड-बांड की बिकवाली की और अपने डालर भंडार को 2023 में 40 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जर्मनी, न्यूजीलैंड, रूस, बांग्लादेश, इजरायल, सिंगापुर, श्रीलंका, इंग्लैंड सहित 22 देशों के बैंकों को भारत में 'स्पेशल वोस्ट्रो रुपया अकाउंट' खोलने की स्वीकृति दी, जिससे इनके साथ डालर की जगह रुपये में व्यापार होगा। इसी बीच यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर भी सहमति बनी। इसके बाद अमेरिका पर दबाव बनना स्वाभाविक ही था, जिसका परिणाम भारत के साथ परस्पर लाभ वाले एक अंतरिम व्यापार समझौते के रूप में निकला। भारत ने अमेरिका के सामने स्पष्ट कर दिया था कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं और उसके पास विकल्पों की कमी नहीं। आखिर 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाला देश किसी के आगे झुके भी क्यों? यह भी न विस्मृत किया जाए कि अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी तो भारत की उतनी ही आवश्यकता है।

ट्रंप की एक चिंता प्रतिरक्षा तंत्र से भी जुड़ी है। भारत रक्षा उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' की डगर पर चल पड़ा है। एक तो भारत बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन की दिशा में बढ़ रहा है तो विदेशी खरीद के मामले में भी बहुत सोच-समझकर कदम बढ़ा रहा है। गत वर्ष भारत ने फ्रांस से 63 हजार करोड़ रुपये के राफेल जेट्स खरीदे, जबकि 50 प्रतिशत ट्रंप टैरिफ के कारण उनके स्ट्राइकर व्हीकल, जेवलिन मिसाइल और बोइंग पी81 एयरक्राफ्ट की खरीद रोक दी। ट्रंप ने यह संकेत भी समझा और अंततः भारत के साथ व्यापार समझौता करने और टैरिफ घटाने को बाध्य हुए। द्विपक्षीय संबंधों में अब स्थितियां भले ही सामान्य होती दिख रही हों, लेकिन ट्रंप की आक्रामकता से भारतीयों के मन में उनके प्रति संदेह और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए कुछ निराशा जरूर बढ़ी है। वैसे ट्रंप और अमेरिका एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अमेरिकी जनता का एक बड़ा वर्ग भी ट्रंप से परेशान है। सौभाग्य से भारत-अमेरिका संबंध गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। संभव है कि आगे अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक छवि और महानता की पुनर्स्थापना करे।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

सिविल सेवा परीक्षा में सही सुधार

प्रेमपाल शर्मा

जब सभी सेवाओं में सुविधाएं बराबर ही हैं तो आयकर वाला रेलवे में काम करने वाले को नीचे क्यों समझता है?

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस संस्था में समय के अनुसार लगातार सुधार और समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहती है। 2026 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के कुछ कदम स्वागतयोग्य हैं। इनके अनुसार परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने पर यदि किसी उम्मीदवार को ग्रुप ए की कोई सेवा मिल जाती है, तो उसके बाद उसे आइएएस, आइएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए केवल एक अवसर और मिलेगा। उसके बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह अपने विभाग से प्रसन्न नहीं है, तो त्यागपत्र देकर फिर से परीक्षा दे सकता है। आइएएस और आइएफएस में एक बार चुने जाने के बाद फिर से परीक्षा में बैठने की इजाजत पहले की तरह अभी भी नहीं होगी। वैसे यहां लोकतांत्रिक ढंग से एक गुंजाइश छोड़ी गई है। लगभग 23 विभागों में पांच विभाग जैसे अगर दिल्ली में दानिक्स या पुडुचेरी पुलिस आदि में ग्रुप बी की सेवा मिलती है तब जरूर उसे एक से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। इस एक सुधार से कई स्तरों पर फायदा होगा। सबसे पहले नए उम्मीदवारों के लिए ज्यादा पद खाली मिलेंगे, वरना पहले से सफल उम्मीदवार बार-बार उन्हीं पदों पर चुने जाते रहे हैं। एक बार चुने जाने वालों के लिए भी एक और अवसर देने से वे लगातार 30-35 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने के लोभ से बच जाएंगे।

सभी सेवाओं के वेतनमान और सुविधाएं लगभग बराबर ही होती हैं। पहले इन विभागों को उम्मीदवार तो आवंटित हो जाते थे, लेकिन उनमें से कितने ज्वाइन करेंगे, कोई पता नहीं होता था। कुछ फिर से परीक्षा में बैठने के लिए लगातार दो-चार वर्षों तक कई बहाने जैसे मेडिकल, मां की बीमारी आदि बताकर कोशिश करते रहते थे। इससे उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण की समस्याएं पैदा होती थीं। नतीजतन प्रशासनिक क्षमता में लगातार गिरावट आ रही थी। अब सभी विभाग बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इससे सभी विभागों की ट्रेनिंग और क्षमता भी बेहतर होगी। इस सुधार के सामाजिक परिणाम भी अच्छे आएंगे। जब जाति विशेष के कारण

समय के अनुरूप सुधार की राह पर यूपीएससी ● एएफपी

किसी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनंत छूट रहती है, तब तक उसके अंदर बार-बार परीक्षा देने की भूख भी कायम रहती है, लेकिन प्रश्न है कि कितने उम्मीदवारों के लिए यह संभव है? क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान पीढ़ी की क्षमता और ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? क्या यह सामाजिक-जातीय विभाजन की तरह सेवाओं में भी कमतर और बेहतर की भावना पैदा नहीं करता? उनके अभिभावक भी लगातार चिंता में डूबे रहते हैं कि उनकी परीक्षा के चक्र कब खत्म होंगे? देश को इन सबसे मुक्ति चाहिए। मौजूदा सुधार का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है और वह है राज्यवार कैडर में उम्मीदवारों का वितरण।

नौकरशाही के स्टील फ्रेम में आइएएस सबसे मजबूत आधार होता है। जिस राज्य के लिए उनका आवंटन होता है, वे उस राज्य में ही रहते हैं या फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, लेकिन उस राज्य में बने रहने के कुछ दुष्परिणाम अतीत में अनुभव किए गए। जैसे जब पंजाब में आतंकियों ने कहर बरपा रखा था, तब अहसास हुआ कि वहां नियुक्त कुछ अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच मिलीभगत हो गई थी। इसलिए बाद में यह फैसला किया गया कि किसी भी राज्य में वहां के रहने वाले उम्मीदवारों के एक तिहाई से ज्यादा नहीं तैनात होंगे और दो तिहाई उम्मीदवार दूसरे राज्यों के होंगे। देश की एकता में इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य राज्य में तैनात होते हैं, तो भाई-भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहती है। अब इसी में एक कदम और बढ़ाकर इसे और पारदर्शी ढंग से किया गया है। इससे उम्मीदवारों में यह अहसास और पुख्ता होगा कि पूरा देश आपका है और आपको कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है।

हालांकि सरकार नए नियमों को कितनी दृढ़ता से लागू करती है, यह एक सवाल है। पुराने अनुभवों पर नजर डालें तो 1986 में भी इससे कुछ मिलते-जुलते कदम उठाए गए थे। तब परीक्षा देने के प्रयासों पर ऐसी ही रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके खिलाफ दशकों तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई। झूठ-सच के आधार पर उम्मीदवारों ने छुट्टी ली और फिर से वर्षों तक परीक्षाएं दीं। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचा और उसकी कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ा। अफसरों के बीच जो परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसके बदले उनमें ईर्ष्या पनपने लगी। जब सभी सेवाओं की लगभग 99 प्रतिशत सुविधाएं बराबर हैं तो इनकम टैक्स में काम करने वाला रेलवे में काम करने वाले को कमतर क्यों समझता है?

अपने देश में आइएएस या आइपीएस का नशा तो सातवें आसमान पर रहता है। यह भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि वह जन्म से ही बराबरी नहीं सिखाता। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा भी है कि संविधान में तो हमने बराबरी ला दी, लेकिन समाज अभी उससे बहुत दूर है। इससे देश को नुकसान पहुंच रहा है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। यूपीएससी में अभी और सुधारों का इंतजार है। हमने ब्रिटिश शासन से स्टील फ्रेम तो ले लिया, लेकिन उसके आत्मा को आत्मसात नहीं किया। यानी कार्यक्षमता, कम उम्र में भर्ती, पाठ्यक्रम, व्यवस्थित प्रशिक्षण, काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी।

(लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संकल्प की शक्ति

संकल्प मनुष्य की वह आंतरिक ज्वाला है, जो साधारण जीवन को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा देती है। विचार जब दृढ़ निश्चय में बदल जाता है, तब वह संकल्प बनता है और संकल्प ही वह शक्ति है, जो असंभव को संभव बनाने का साहस देती है। इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों ने अपने लक्ष्य को केवल इच्छा नहीं, बल्कि संकल्प बनाया, उन्होंने युग बदल दिए।

महात्मा गांधी का संकल्प केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा के आधार पर समाज को परिवर्तित करने का था। अनेक असफलताओं, जेल यात्राओं और आलोचनाओं के बावजूद उनका निश्चय डिगा नहीं। परिणामस्वरूप, उनका व्यक्तिगत संकल्प जन-जन का विश्वास बन गया। इसी प्रकार, स्वामी विवेकानंद ने निर्धनता, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच यह संकल्प लिया कि वे भारत की आध्यात्मिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करेंगे। शिकागो धर्म संसद में उनका ओजस्वी उद्बोधन केवल वक्तृत्व का चमत्कार नहीं, अपितु उनके अटूट संकल्प का प्रतिफल था। आधुनिक भारत में डा. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी संकल्प की शक्ति का प्रेरक उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे देश को वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उनका जीवन सिखाता है कि संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि संकल्प की कमी मनुष्य को रोकती है।

वास्तव में संकल्प वह दीप है, जो लक्ष्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रतिभा मार्ग दिखा सकती है, परंतु उसे गंतव्य तक पहुंचाने की शक्ति संकल्प ही देता है। जिस व्यक्ति के भीतर दृढ़ निश्चय जाग उठता है, उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं, बल्कि साधन बन जाती हैं। इसलिए जीवन में सफलता का प्रथम सूत्र यही है-सपना देखो, उसे संकल्प में बदलो और फिर अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसे जियो।

प्रो. आनंदप्रकाश त्रिपाठी 'रत्नेश'

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

जनहित में हो एआइ का उपयोग

संपादकीय 'एआइ क्रांति की चुनौतियां' पढ़ा। एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आज विश्व स्तर पर परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। भारत भी इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में उभर रहा है। एआइ से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ी है, पर इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। यदि एआइ के विकास में हम विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर रहे, तो यह दीर्घकाल में आर्थिक-रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, रोजगार पर प्रभाव और तकनीक के दुरुपयोग जैसी समस्याएं भी सामने हैं। एआइ का उपयोग पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सरकार और शिक्षण संस्थानों को शोध, नवाचार और कौशल विकास पर विशेष बल देना होगा, ताकि युवा इसमें दक्ष बनें। एआइ क्रांति केवल अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सही नीतियों के साथ ही भारत इस तकनीक को जनहित और राष्ट्रहित में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

तकनीकी दबदबे को चुनौती

श्रीराम चौलिया ने 'असीमित संभावनाओं वाली मैत्री' अग्रलेख में सही कहा है कि फ्रांस ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार चुना है, जिससे रक्षा से लेकर भविष्य की एआइ तकनीकों तक दोनों देश मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के बाद भारत और फ्रांस के बीच संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भर भारत के लिए क्रांतिकारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा है कि वे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक के लिए केवल अमेरिका-चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते। भारत और फ्रांस ने मिलकर एआइ, डिजिटल विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में भरोसेमंद एआइ के लिए स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया है, जो अमेरिका के तकनीकी दबदबे को चुनौती देता है। अमेरिका की ओर से यूरोप की उपेक्षा (जैसे व्यापार और रक्षा मामलों में) के बीच भारत और फ्रांस एक-दूसरे को रणनीतिक संतुलन के रूप में देखते हैं। फ्रांस भारत के लिए पश्चिमी देशों में एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार (विशेषकर राफेल और पनडुब्बियों के क्षेत्र में) के रूप में उभरा है। वहीं, हिंद-प्रशांत में फ्रांस की उपस्थिति से भारत को रणनीतिक मजबूती मिल रही है, जो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सहायक है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस में 2026 जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और अफ्रीका के साथ साझेदारी को मजबूत करने हेतु मई 2026 में नैरोबी में होने वाले अफ्रीका फारवर्ड समिट में भी आमंत्रित किया।

युगल किशोर राही, छपरा।

एआइ क्रांति जिम्मेदारी भी

संपादकीय 'एआइ क्रांति की चुनौतियां' पढ़ा। एआइ (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) आज विश्व स्तर पर परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। भारत भी इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में उभर रहा है। एआइ से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। यदि एआइ के विकास में हम विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर रहे तो यह दीर्घकाल में आर्थिक और रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, रोजगार पर प्रभाव और तकनीक के दुरुपयोग जैसी समस्याएं भी सामने हैं। एआइ का उपयोग पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को शोध, नवाचार और कौशल विकास पर विशेष बल देना होगा, ताकि युवा वर्ग इस क्षेत्र में दक्ष बन सके। एआइ क्रांति केवल अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सही नीतियों और सतर्कता के साथ ही भारत इस तकनीक का जनहित और राष्ट्रहित में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है। तकनीक के बल पर ही आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन उसका सकारात्मक और समाज के विकास में योगदान हो, इस दिशा में जरूर विचार हो।

इं. हिमांशु शेखर, गयाजी।

पोस्ट

पहली बार रणजी ट्राफी के फाइनल में पहुंचकर जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रच दिया है। युवा खिलाड़ियों की मेहनत, कप्तान पारस डोगरा का नेतृत्व और कोच अजय शर्मा के मार्गदर्शन में यह संघर्षपूर्ण सफर पूरा हुआ है। यह उपलब्धि कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब फाइनल में खिताब की उम्मीद है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारतीय मूल के सीईओ विश्व की बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, यह गर्व की बात जरूर है, लेकिन असली गर्व तब होगा जब हमारी कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होंगी। यही हमें विकसित भारत बनाएगा और आधुनिक तकनीक के मामले में अग्रणी बनाएगा।

हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट में एआइ के बारे में सुनने और सीखने के लिए उत्सुक युवाओं से सभागार भरा हुआ था। इस उत्साह और उत्सुकता ने मुझे भरोसा दिया कि भारत एआइ में शीघ्र ही सुपरपावर बनने जा रहा है, लेकिन हमें एआइ को भारतीय नजरिये से देखने की आवश्यकता है।

शेखर कपूर@shekharkapur

जनपथ

'चीनी कुत्ता' घूमता दिल्ली के बाजार,
बांध लिया गलगोटिया मचती चीख-पुकार।
मचती चीख-पुकार गले में जिसका पट्टा,
सौ की सीधी बात उसी का समझो कुत्ता!
गली-गली में घूम रहे हैं कुत्ते छुट्टा,
अब उनमें इक और बढ़ गया 'चीनी कुत्ता'!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष :0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 307

चिंतन

सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिले सरकारी मदद

देश में बढ़ते "फ्रीबीज कल्चर" पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीब और वंचित तबकों तक ही सीमित होना चाहिए। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भले नई न हो, लेकिन इसके निहितार्थ बेहद गंभीर हैं। जब कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औजार बन जाएं और आर्थिक विवेक पीछे छूट जाए, तब राज्य के विकास पर दीर्घकालिक असर पड़ना तय है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रश्न यह नहीं है कि गरीबों की मदद की जाए या नहीं, निस्संदेह की जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या बिना किसी भेद के, भुगतान करने में सक्षम लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं देना न्यायसंगत और आर्थिक रूप से टिकाऊ है? कल्याण और तुष्टीकरण के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और उसे पहचानना सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत जैसे विकासशील देश में संसाधन सीमित हैं। अधिकांश राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि सरकारों का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और मुफ्त राशन/बिजली जैसी योजनाओं पर ही खर्च हो जाए, तो बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। अदालत की यह चिंता वाजिब है कि विकास परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जबकि चुनावी मौसम में नई-नई घोषणाएं हो जाती हैं। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को दांव पर लगाना दूरदर्शिता नहीं कहा जा सकता। लोकलुभावन वादों का आकर्षण हर लोकतंत्र में रहता है। चुनाव के आसपास मुफ्त योजनाओं की बाढ़ आना भी कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन क्या यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है? यदि नागरिकों को यह संदेश जाए कि राज्य हर जरूरत खाना, बिजली, गैस बिना शर्त उपलब्ध कराएगा तो काम और उद्यमिता के प्रति प्रेरणा पर भी असर पड़ सकता है। आत्मसम्मान और स्वावलंबन किसी भी समाज की बुनियाद होते हैं। सरकार का दायित्व अवसर पैदा करना है। रोजगार, कौशल विकास, उद्यम के लिए अनुकूल माहौल बनाना, न कि स्थायी निर्भरता की संस्कृति विकसित करना। यह भी सच है कि भारत में अभी भी बड़ी आबादी ऐसी है जो बिजली का बिल, रसोई गैस या जरूरी राशन का खर्च वहन करने में असमर्थ है। उनके लिए लक्षित और पारदर्शी सहायता अनिवार्य है। तकनीक और डेटा के इस युग में आय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जरूरत के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करना संभव है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार-लिंक्ड प्रणालियों ने यह क्षमता बढ़ाई है कि सहायता सही हाथों तक पहुंचे। ऐसे में सभी को मुफ्त की नीति प्रशासनिक सुविधा का बहाना तो हो सकती है, आर्थिक विवेक का नहीं। समस्या यह है कि एक बार मुफ्त योजना शुरू हो जाए तो उसे वापस लेना राजनीतिक रूप से बेहद कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप राजकोषीय बोझ बढ़ता जाता है और भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का दबाव बढ़ता है। संतुलन ही समाधान है, न कठोर कटौती, न असीमित उदारता। सरकारों को लोकप्रियता से अधिक प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास को देनी होगी। तभी सरकारी मदद वास्तव में उन तक पहुंचेगी, जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

कूटनीति
अरविंद जयतिलक

सामरिक संबंधों को धार देते भारत-फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्ते को मिठास से भर दिया है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति रेखांकित करता है कि दोनों देश संबंधों की ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप-स्वरूप को जड़ से मिटाने की वकालत के साथ यूक्रेन, मध्य-पूर्व, और इंडो-पैसेफिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में कंधा जोड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोनों देशों ने 21 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें रिमोटली एच-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में एच-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन शुरू की गई है।

एच-125 इतिहास का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतर चुका है। ध्यान देना होगा कि 'मेड इन इंडिया' एच-125 हेलीकॉप्टर मात्र सिविल हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेनाओं की जरूरतें भी पूरी करेगा। इससे भारत की सामरिक रक्षा पंक्ति मजबूत होगी। इसके अलावा फ्रांस की साफरान और भारत की 'भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड' मिलकर भारत में ही हैमर मिसाइल बनाएंगे। गौर करें तो दोनों देशों के बीच राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक रक्षा सहयोग का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी गत वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा हुई थी, तब दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी और टेक्नोलॉजी को नई धार देने के निमित्त एआई (आटिफिशियल इंटेलिजेंस) पर अलग से बयान जारी करते हुए वर्ष 2026 को 'इंडो-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन' घोषित किया। तब दोनों देशों ने स्कॉर्पीन सबमरीन निर्माण, मिसाइल हेलिकॉप्टर, जेट इंजन, एडवांस मॉड्यूल रिएक्टर, परमाणु उर्जा एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के अलावा एकदूसरे को सहयोग करने का भरोसा दिया। मैक्रो की भारत यात्रा ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए एक-दूसरे का स्वर बनने को तैयार हैं। विगत कुछ वर्षों के दरम्यान दोनों देशों की सामरिक-आर्थिक क्षेत्र को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। इस समय दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गत वर्ष पहले ही दोनों देशों के बीच डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप, सैटेलाइट लांच के लिए नए स्पेस इंडियन लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच एमओयू हुए। टाटा और एयरबस स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर 125 हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति बनी। गौर करें तो रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार है। याद होगा कि गत वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण साझीदार बताते हुए सुनिश्चित किया था कि दोनों देश पनडुब्बी हो या नौसैनिक विमान, सभी क्षेत्र में मिलकर काम करने को तैयार हैं। तब दोनों देश 'भारत-फ्रांस हिंद-प्रशांत रोडमैप' जारी करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाने पर सहमति जाहिर की थी। गौरतलब है

कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रीयूनियन द्वीप, न्यूकैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति है। इस पहल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर रोक लगेगी। दोनों देशों के बीच कितने मधुर संबंध हैं इसी से समझा जा सकता है कि फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित कर चुका है। याद होगा जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब उससे नाराज होकर दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध थोपा था। तब फ्रांस ने भारत के साथ कंधा जोड़ते हुए रणनीतिक समझौते को व्यापक आयाम दिया। फ्रांस लगातार भारतीय सेना को लड़ाकू जेट व पनडुब्बियों समेत साजो-सामान की आपूर्ति कर रहा है। 2018 के बाद से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल रक्षा आयात का तकरीबन 29 फीसदी फ्रांस से करता है।

दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता ने कारोबारी, रणनीतिक और सामरिक कुटनीति को नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। दोनों देश एक-दूसरे के सैनिक अड्डे का इस्तेमाल और वहां अपने युद्धपोत रखने के अलावा ऊर्जा, तस्करी, आव्रजन, शिक्षा, रेलवे, पर्यावरण, परमाणु, आतंकवाद और अंतरिक्ष मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच यूपीआई को लेकर भी सहमति बन चुकी है। विगत 25 वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच साझेदारी और समझदारी का ही परिणाम है कि आज भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका है। भारत में 1000 से अधिक फ्रांस की कंपनियां काम कर रही हैं और सभी कंपनियों का संयुक्त टर्नओवर तकरीबन 30 अरब डॉलर से अधिक है। विगत ढाई दशकों में भारत-फ्रांस संबंध को एक नया आयाम मिला है और दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों में बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।

फ्रांस के नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ कुछ द्विपक्षीय बाध्यताओं ने भी दोनों देशों को एक-दूसरे के निकट लाया है। यह तथ्य है कि चीन युद्ध के बाद भारत न केवल महाशक्तियों अपितु अफ्रीका व एशियाई देशों से भी अलग-थलग पड़ गया था। भारत को एक ऐसे देश के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक था जिससे उसका कोई क्षेत्रीय विवाद न रहा हो। इसके अलावा 1962 में भारत व फ्रांस के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण संबंधी संधि के अनुमोदन ने दोनों देशों के संबंधों में मिठास घोली। तथ्य यह भी कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारतीय प्रयास का समर्थन करने वाले प्रथम देशों में से एक था। वह आज भी अपने पुराने रुख पर कायम है। दरअसल, दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व में कई द्विपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों के संबंध में समान सोच है। हालांकि विदेश नीति के विरोधी अभिमुखन के कारण दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर कई बार विरोधी रुख भी अपनाए हैं। 1973 में फ्रांस के तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं वित्तमंत्री वेलेरी जिसकार्ड जो बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति भी बने, की पहल पर 'भारत-फ्रांस अध्ययन समूह' की स्थापना हुई।

इस समूह की पहली बैठक फरवरी 1974 में फ्रांस में हुई तथा दूसरी बैठक मार्च 1975 में नई दिल्ली में हुई। इस समूह की सलाह पर दोनों देशों के मध्य समुद्री तेल उत्खनन, शक्ति उत्पादन व वितरण, कोयला उत्खनन व प्रयोग तथा तीसरे देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने संबंधित कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों देशों के व्यापार में अहम है वह यह कि 1994 के बाद व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में बना हुआ है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

> फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्ते को मिठास से भर दिया है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति रेखांकित करता है कि दोनों देश संबंधों की ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप-स्वरूप को जड़ से मिटाने की वकालत के साथ यूक्रेन, मध्य-पूर्व, और इंडो-पैसेफिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में कंधा जोड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोनों देशों ने 21 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें रिमोटली एच-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण है।

जीवन का मार्गदर्शन करती है अंतःकरण की आवाज

संकलित
दर्शन

हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है, लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज थी। इसी कारण गांधीजी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है। भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती है। जब हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करते हैं तो अंतरात्मा से हमारा संपर्क कमजोर हो जाता है।

ऐसे काम न करें, जिनसे समाज में गलत संदेश जाएं

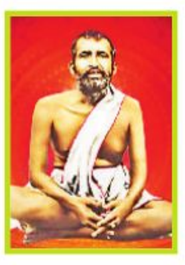

संकलित
प्रेरणा

परमहंस जी अपने शिष्यों को नियमित रूप से उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वे उपदेश दे रहे थे, उस समय एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आम लोग तो सभी सुख-सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु-संतों के लिए इतने कठोर नियम क्यों हैं? परमहंस जी ने शिष्य से कहा कि हमें ऐसे काम करना चाहिए, जिनसे समाज को अच्छा संदेश मिलता है। ये बात साधु-संतों को खासतौर पर ध्यान रखनी चाहिए। आम लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम कर सकते हैं, लेकिन साधु-संत को हर हाल में गलत कामों से दूर ही रहना चाहिए। साधु-संतों को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सुख-सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संत को क्रोध से भी बचना चाहिए। तभी वे समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं। शिष्य ने फिर पूछा कि साधु-संतों के लिए ही इतने कठिन नियम क्यों हैं? जबकि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। परमहंस जी ने शिष्य को समझाया कि त्याग का संदेश साधु-संत नहीं देंगे तो और कौन दे सकता है। साधु-संत अपने ज्ञान और कर्म से समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने की सीख देते हैं। साधु-संत हमें बताते हैं कि हमें किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए, त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। परमहंस जी ने साधु-संतों के माध्यम से संदेश दिया है कि अगर हम घर-परिवार और समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए।

विचार
सोनमणि बोरा

माटीपुत्र पं. श्यामलाल चतुर्वेदी

पद्मश्री पं. श्यामलाल चतुर्वेदी पर कुछ कहना या लिखना अपनी माटी के प्रति एक ऋण के उतारने जैसा है। माटीपुत्र का अलंकरण ऐसे संत पुरुषों को शोभा देता है। उन्हें जब भी देखा, मन, वचन और कर्म से छत्तीसगढ़ की सेवा करते हुए पाया। एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक समाजसेवी चिंतक के रूप में पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी का नाम अविस्मरणीय है। बात तब की है, जब मैं बिलासपुर में प्रशासन की जिम्मेदारी संभाले हुए था। जाहिर तौर पर जब कलेक्टर था, जब जिले को आगे ले जाने वाली नीतियों को लागू कराने के लिए रोज़ाना सैकड़ों लोगों से मिलना होता था। पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी भी आते थे। एक साधारण से कदकाठी के व्यक्ति, हाथ में झोला लिए हुए, खादी और धोती कुर्ता पहने हुए चलते-फिरते ज्ञान और दूरदृष्टि का भंडार थे। उनसे जब भेंट होती, कुछ न कुछ कहानियां, कुछ न कुछ रोचक बातें होतीं। वे सुनाया करते। एक पत्रकार के तौर पर उनके पास सुनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सृजन की कई कहानियां थीं। कई बार वे बताते कि अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बिलासपुर आते, तो कैसे उन्हें वे और उनके साथी पत्रकार घेर लिया करते। बिलासपुर की जायज मांगों को कैसे पूरा करवाते। उनकी इस चर्चा में, उनके इस चिंतन में, उनके इन प्रश्नों में बिलासपुर के विकास का प्रश्न हमेशा रहता और फिर वे हमें सुझाव देते कि आपको नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन के लिए क्या करना चाहिए।

साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री पं. श्यामलाल चतुर्वेदी राष्ट्रपति भवन हुए समारोह में जब पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था, तो मुझे उनके साथ बिताए पल याद आ रहे थे। जब उन्हें राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तब एक मुलाकात हुई थी। वे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भेंट बिलासपुर में ही हुई थी, मैं किसी काम से गया हुआ था बिलासपुर। उन्होंने कहा- "बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत कुछ करना है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप सबका साथ अविरल मिलता रहे, यही कामना है।" हम लोगों ने कहा कि हम तो हमेशा साथ हैं। उनके पुत्र चंद्रकांत और सूर्यकांत दोनों ने उनकी जो सेवा की है, वो अनुकरणीय है। ये उनके पारिवारिक संस्कारों का परिणाम है कि पुत्रधर्म के लिए कई-कई दिनों तक अपनी दिनचर्या का दोनों पुत्रों ने त्याग किया।

पं. श्यामलाल चतुर्वेदी का जन्म 1926 में बिलासपुर जिले के कोटमी गांव में हुआ था। मैंने सुना था कि उनकी कहानी संग्रह भोलवा भोलाराम काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय थी। एक बार उसे सुनने का अवसर मिला था। वे छत्तीसगढ़ी के गीतकार भी रहे। उनकी रचनाओं में 'बेटी के बिदा' प्रसिद्ध है। उन्हें 'बेटी के बिदा' के कवि के रूप में लोग पहचानते हैं। बताया जाता है बचपन में मां के कारण उनका रुझान लेखन में हुआ। उनकी मां ने उन्हें सुन्दरलाल शर्मा की 'दानलीला' रटा दी थी।

उन्होंने पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी मूल्यवान सेवाएं दी। वे मूलरूप से तत्कालीन अविभाजित बिलासपुर जिले के ग्राम कोटमी सोनार (वर्तमान में जिला जांजगीर-चांपा) के निवासी रहे, लेकिन साहित्यकार और पत्रकार के रूप में बिलासपुर उनकी कर्मभूमि रही। 1940-41 से पं. श्यामलाल चतुर्वेदी ने लेखन आरंभ किया। शुरूआत हिन्दी में की लेकिन 'विप्र' जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ी में लेखन शुरू किया। चतुर्वेदी शिक्षक भी थे। श्यामलाल चतुर्वेदी करीब 75 वर्षों तक साहित्य साधना के जरिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्ध बनाने की कोशिश करते रहे।

पं. श्यामलाल चतुर्वेदी का जीवन दर्शन सहजता और सरलता सिखाता है। उनका जीवन दर्शन बताता है कि जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है, वो कितना सहज और सरल होता है। उनके लेखन, चिंतन और समग्र दर्शन पर जो कुछ भी समेटने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्रशंसनीय है। ये समाज को आने वाले समय में दिशा देगा, ऐसा मेरा मानना है।

-लेखक आदिम जाति-अनुसूचित जाति विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

शिव जयंती

इंदौर में गुरुवार को शिवाजी महाराज की 'शिव जयंती' पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में एक बालक।

आज की पाती

मोटापा सेहत का दुश्मन

हमारे देश के लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। इससे जानलेवा बीमारियों के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। आज हमने अपनी जीवनशैली और खानपान की आदतों को बिगाड़ कर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। मोटापा भी कुदरत के विरुद्ध खानपान और जीवनशैली अपनाने से बढ़ता है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश की सरकारें, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बहुत से अभियान चलाते हैं। योग गुरु भी इसके लिए काम करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फिर गलत खानपान और जीवनशैली अपना कर अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने खानपान और जीवनशैली की आदत को बिगाड़ कर अपने स्वास्थ्य को खराब करने का काम किया है। *- ललित वाधवानी, भाटापारा*

ट्रेंड

एआई -सक्षम शासन

नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में राजस्थान के हमारे स्टार्टअप्स और डेटा-संचालित गवर्नेंस मॉडल को वैश्विक मंच मिल रहा है। दिग्गज कंपनियों के साथ हमारी टीम की चर्चा राज्य में एआई -सक्षम शासन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नई राहें खोलेगी।
- भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

नौकरियों में पारदर्शिता

अगले कार्यकाल में हमारी सरकार केवल शिक्षा विभाग में ही 50,000+ युवाओं की नियुक्ति करेगी। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और गति का जो बड़ा बदलाव आया है, वह आगे भी जारी रहेगा।
- हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

सांस्कृतिक असंवेदनशीलता

हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। आज श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव का सम्मान करते हुए उनके नाम के आगे अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग "स्वामी" जोड़ दिया!
- ममता बनर्जी, सीएम, प. बंगाल

किसान हितों की अनदेखी

अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत के कृषि क्षेत्र और ऊर्जा सुरक्षा/ रणनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित व्यापार को शामिल करना साफ दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने घुटने टेक दिए हैं। इसमें किसानों के दूरगामी हितों की अनदेखी की गई है।
- सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री

करंट अफेयर

सूडान की तबाही में 'नरसंहार के स्पष्ट संकेत' दिखे : संरा

संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर के एक शहर और उसके आसपास के इलाकों में गैर-अरब समुदायों के खिलाफ सूडानी विद्रोहियों द्वारा अक्टूबर में चलाए गए अभियान में नरसंहार के संकेत दिखाई देते हैं। यह देश में जारी विनाशकारी युद्ध को लेकर एक चौंकाने वाला निष्कर्ष है। सूडान पर एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषी मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने अल-फशेर में 18 महीने की घेराबंदी के बाद बड़े पैमाने पर हत्याएं और अन्य अत्याचार किए। इसके अनुसार, इस दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने गैर-अरब समुदायों, विशेष रूप से जघावा और फुर समुदायों को नुकसान पहुंचाने के लिए सोची-समझी शर्तें लागू कीं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि दारफुर में सूडानी सेना के एकमात्र बचे गढ़ अल-फशेर पर आरएसएफ के कब्जे के दौरान कई हजार नागरिक मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर के 260,000 निवासियों में से केवल 40 प्रतिशत ही हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहे। उनमें से हजारों घायल हो गए। उन्होंने बताया कि बाकी बचे लोगों का क्या हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।

ऑफ बीट

एआई का इस्तेमाल कब न करें, यह जानना भी जरूरी

कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के प्रशिक्षण में आमतौर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि बेहतर परिणाम कैसे हासिल किए जाएं—बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, प्रश्न को कैसे परिष्कृत करें और सामग्री को अधिक तेजी से कैसे तैयार करें। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में एआई को केवल उत्पादकता बढ़ाने वाले औजार के रूप में देखा जाता है और सफलता को गति से मापा जाता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोच अधूरी है। आलोचनात्मक एआई साक्षरता अलग प्रश्न उठाती है। इसमें मैं इसका उपयोग कैसे करूं? के बजाय क्या मुझे इसका उपयोग करना भी चाहिए? और इसे तेज कैसे बनाऊं? के बजाय इस प्रक्रिया में मैं क्या खो रहा हूं? के बारे में जानना बेहद जरूरी है। एआई प्रणालियां उन पूर्वाग्रहों को साथ लेकर चलती हैं, जिन्हें अधिकतर उपयोगकर्ता देख नहीं पाते। वर्ष 2025 में 'ब्रिटिश न्यूज़पेपर आर्काइव' पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल व्यवस्था वाले विक्टोरियनकालीन अखबार वास्तव में प्रकाशित सामग्री के 20 प्रतिशत से भी कम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपलब्ध नमूना राजनीतिक प्रकाशनों की ओर झुकाव रखता है और स्वतंत्र आवाज़ों को कम दर्शाता है। ऐसे में यदि कोई शोधकर्ता इसी आधार पर विक्टोरियन समाज के बारे में निष्कर्ष निकाले, तो वह अभिलेखागार में निहित विकृतियों को दोहरा सकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 5

प्रक्रियागत स्पष्टता

आधुनिक और गतिशील बाजार अर्थव्यवस्था में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कानूनों और विनियमों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संभव है कि बाजार संबंधी बदलती परिस्थितियां समायोजन की मांग करें, या कार्यान्वयन का अनुभव स्वयं विनियमन में खामियों को उजागर कर दे। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी), 2016 का कार्यान्वयन हाल के वर्षों में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार और नियामक, भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई), ने वर्षों से दिवालियापन ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया है। इसी संदर्भ में, आईबीबीआई ने इस सप्ताह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया है, जिसका व्यापक उद्देश्य प्रक्रियात्मक स्पष्टता में सुधार करना है। इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन पारदर्शिता को बढ़ाएगा और समाधान प्रक्रिया में टकराव को कम करेगा।

जैसा कि परिचर्चा पत्र में उल्लेख किया गया है, सीओसी की बैठकों के अभिलेखों की गहराई और विवरण में काफी भिन्नता है, और विचार-विमर्श अभिलेखों में समुचित रूप से परिलक्षित नहीं होते। वाणिज्यिक निर्णयों का आधार हमेशा स्पष्ट नहीं होता। इससे बाद के चरणों में मुकदमेबाजी और देरी हो सकती है। दिवालियापन ढांचे के तहत सीओसी से अपेक्षा की जाती है कि वे समाधान योजनाओं का समुचित मूल्यांकन करें। इसलिए, चर्चा पत्र स्पष्टता में सुधार के उपायों का प्रस्ताव करता है। वर्तमान आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सीओसी से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपेक्षित वसूली की तुलना निष्पक्ष और परिसमापन मूल्य से करने की अपनी बातचीत को दर्ज करें। इसके अलावा, उन्हें समाधान प्रक्रिया के दौरान की गई बाजार खोज की पर्याप्तता को भी दर्ज करना होगा। सीओसी से यह भी अपेक्षा होगी कि वे समाधान आवेदक की विश्वसनीयता और समाधान योजना के कार्यान्वयन की निश्चितता को दर्ज करें।

मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि सीओसी द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति स्पष्ट रूप से जागरूक, सूचित और तर्क द्वारा समर्थित हो। प्रक्रिया में इस प्रकार का सुधार ढांचे को और अधिक मजबूत बनाएगा। चर्चा पत्र आगे यह भी स्पष्ट करता है कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान संचालन की निरंतरता अपेक्षित परिणामों के मूल्य और वाणिज्यिक विवेक द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। प्रस्तावित बदलावों ने विलंबित दावों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। ऐसे दावे, जिन्हें समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार्य माना गया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए और केवल उनके समाधान योजना में उपचार के संदर्भ में सिफारिश के लिए सीओसी के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में ऐसे दावे निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि सीओसी की सिफारिश अनुपस्थित थी। पत्र आगे संबंधित परिचालन ऋणदाताओं को सीओसी से बाहर करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित बदलाव दिवाला समाधान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और परिचालन स्पष्टता लाएंगे। इससे देरी कम होने की उम्मीद है। हालांकि, ऐसे बदलाव वांछित स्तर का अंतर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आईबीसी को लाने के पीछे विचार यह था कि यह दिवालियापन समाधान को न्यूनतम संभव समय में सक्षम बनाएगा, जिससे प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों में मूल्य की कुछ हद तक रक्षा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जैसा कि आईबीबीआई के नवीनतम त्रैमासिक न्यूजलेटर ने दिखाया, दिसंबर 2025 तक 1,376 सीआईआरपी में समाधान योजनाएं बनीं, जिनमें औसत समय 619 दिन लगा, जबकि अधिकतम समयसीमा 330 दिन निर्धारित की गई थी।

ढांचे की मूल समस्या, जैसा कि विशेषज्ञों ने भी रेखांकित किया है, राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) में क्षमता की कमी है। इसलिए, कानून में सुधार के साथ-साथ सरकार को क्षमता संबंधी मुद्दे को भी संबोधित करना होगा। एक अपेक्षाकृत सुगम निकास मार्ग न केवल पूंजी का कुशल पुनर्वितरण करेगा, बल्कि सामान्य रूप से निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत-अमेरिका करार के पीछे केवल व्यापार नहीं

दोनों देशों के बीच इस समझौते के चलते भारत के प्रति अमेरिका का रुख शत्रुतापूर्ण से तटस्थ हो सकता है। हमारी वृद्धि के लिए यह मायने रखता है। बता रहे हैं टीटी राम मोहन

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जिसके लिए अंतरिम करार के एक ढांचे पर सहमति बनी है, उसकी आलोचना करने वाले भी कम नहीं हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आत्मसमर्पण करार दिया है। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कई लोग विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा में हैं और समझौते को अंतिम रूप मिलने के बाद वे कह सकते हैं कि यह समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है।

हमें कुछ बातों को लेकर स्पष्ट होना होगा। पहली बात कोई देश जो ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता कर रहा हो उसे यही उम्मीद करनी चाहिए कि समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका के आर्थिक समीकरणों को दुरुस्त करने की है। वह इसके लिए अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने पर दृढ़ हैं।

विश्व युद्ध के बाद की पूरी अवधि में अमेरिका कई व्यापार साझेदारों को खुशी-खुशी बढ़त दे रहा था। वह मानता रहा है कि आर्थिक रूप से वह काफी मजबूत है। वह मानता था कि समृद्धि को शेष विश्व के साथ साझा करना विश्व शांति में मददगार होगा और दुनिया को वामपंथ से भी बचाए रखेगा।

अब ऐसा नहीं है। ट्रंप साल 2016 में यह कहकर सत्ता में आए कि अब वक्त आ गया है कि व्यापारिक रिश्तों को अमेरिका के हितों के हिसाब से तय किया जाए। वह ऐसा कर नहीं सके क्योंकि उनकी पहलों को उनकी ही कैबिनेट के उन सदस्यों का साथ नहीं मिला जो हालात को जस का तस रखना चाहते थे। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने अपने वफादारों को सरकार में शामिल किया जो उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

गत जुलाई में ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा, 'अमेरिका को व्यापार (और सैन्य मामलों!) में, दशकों से मित्रों और शत्रुओं दोनों द्वारा ठगा गया है। इसकी कीमत खरबों डॉलर रही है, और यह अब और टिकाऊ नहीं है। और कभी था भी नहीं! इसलिए किसी भी व्यापार समझौते में, लाभ अमेरिका का ही होगा।'

दूसरी बात, हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ रिश्ते इस बात पर निर्भर हैं कि ऐसा व्यापार समझौता हो जो अमेरिका को स्वीकार्य हो। यदि व्यापार समझौता नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा, हर क्षेत्र में अमेरिकी शत्रुता को आमंत्रित करना। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय, हर राष्ट्र के सामने एक विकल्प होता है: वह क्या चाहता है, अमेरिका उसका मित्र बने या शत्रु?

यूरोपीय संघ के साथ ट्रंप का समझौता इसका सटीक उदाहरण है। यूरोपीय संघ के लिए मुद्दा केवल अमेरिकी बाजार तक पहुंच का नहीं था। उसे यूक्रेन विवाद में भी अमेरिका की मदद की आवश्यकता थी। इसके तहत अहम हथियारों और खुफिया जानकारियों के साथ-साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में अमेरिकी सहयोग, सब शामिल था। अमेरिका के साथ रक्षा रिश्तों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने ऐसी शर्तें स्वीकार कर लीं जो शर्मनाक थीं।

अब यूरोपीय संघ के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 15 फीसदी का शुल्क लगता है। इसके अलावा स्टील, एल्युमीनियम और कॉपर निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लागू है। कारों का निर्यात कोटा के अधीन है। यूरोपीय संघ ने अगले तीन साल में 750 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की हामी भरी है और वर्ष 2029 तक अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। यूरोपीय संघ समस्त अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं के आयात पर शुल्क समाप्त करेगा और अमेरिकी समुद्री और कृषि उत्पादों को प्राथमिकता वाली पहुंच देगा। इससे अधिक समर्पण भला क्या होगा? ट्रंप ने ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसा ही एकतरफा समझौता किया। ये सभी अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।

भारत के लिए सबक यह है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता केवल अमेरिकी बाजार तक पहुंच से संबंधित नहीं है। भारत ने अपने निर्यात पर ट्रंप के 50 फीसदी शुल्क का अपेक्षाकृत बेहतर सामना किया है। भारत का कुल निर्यात इस शुल्क वृद्धि के बावजूद 4.4 फीसदी बढ़ा है। अप्रैल-दिसंबर 2025 में अमेरिका को हमारा निर्यात 9.8 फीसदी बढ़ा है।

भारत के लिए दिक्कत है पूंजी प्रवाह में कमी। यह ऐसे समय हो रहा है जबकि भारत का जीडीपी के 1.3 फीसदी तक का चालू खाता घाटा कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि के अनुरूप ही है। आर्थिक सुधारों के बाद के दौर में भारत के लिए इससे अधिक स्तर के घाटे का प्रबंधन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं रहा है। आज हम पर पूंजी की आवक का दबाव है और रुपया भी कमजोर है। यह तब है जबकि आर्थिक संकेतक सकारात्मक हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कैलेंडर वर्ष 2024 में 2 फीसदी गिरा। यह हाल के वर्षों में एफडीआई प्रवाह में सामान्य गिरावट के अनुरूप हो सकता है, लेकिन इस पर ही संतोष नहीं किया जा सकता। उसी समय, भारत से बाहर जाने वाला एफडीआई और भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा लाभ की वापसी तेजी से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल-नवंबर 2025 में शुद्ध एफडीआई मात्र 5.6 अरब डॉलर रहा। इस समय बड़ी समस्या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के साथ है। अप्रैल-दिसंबर 2025 में यह 3.9 अरब डॉलर ऋणात्मक रहा यानी इतनी निकासी हुई।

इसके ऋणात्मक होने के कई कारण हो सकते हैं। भारत के प्रति अमेरिकी प्रशासन का रुख एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जब भारत पर अमेरिका द्वारा दंडात्मक शुल्क व्यवस्था लागू होती है, तो फंड मैनेजरों के भारत को निवेश के लिए अच्छा स्थान मानने की संभावना कम ही रहेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री समेत वित्त विभाग में ऐसे लोग हैं जिनके वॉल स्ट्रीट से मजबूत संबंध हैं। वे विभिन्न मामलों पर फंड मैनेजरों से सीधे संपर्क करने के लिए जाने जाते हैं।

इसलिए, व्यापार समझौते के अभाव में, हमें पूंजी प्रवाह के मामले में कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, चाहे हमारे व्यापक आर्थिक संकेतक कितने भी अच्छे क्यों न हों। और कौन जानता है कि अमेरिका को सेवाओं के निर्यात भी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन न हो जाएं? जोखिम में रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पिछले दो दशकों में निर्मित संपूर्ण रणनीतिक साझेदारी भी है। इस प्रकार, वर्तमान वर्ष में भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन इस बात की गारंटी नहीं है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अभाव में इसे बनाए रखा जा सकेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार करार का मुद्दा यह नहीं है कि इसमें कई जगह झुकना पड़ रहा है, जैसे रूस से तेल आयात कम करना या अगले पांच वर्षों तक अमेरिका से वस्तुओं का आयात सालाना 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना। यह केवल 18 फीसदी शुल्क दर पाने का मामला भी नहीं है, जो हमारे कई प्रतिस्पर्धियों से कम है। असली मुद्दा यह है कि यह अमेरिका के भारत के प्रति रुख को शत्रुतापूर्ण से तटस्थ की ओर ले जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है।

झूठ-फरेब वाली बिक्री के पीछे की कहानी

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

मध्य भारत के एक कस्बे में मौजूद एक बड़े सरकारी बैंक की शाखा गत वर्ष कम लागत वाले चालू और बचत खातों (कासा) तथा खुदरा सावधि जमा में न्यूनतम वृद्धि हासिल करने में भी नाकाम रही। वास्तव में उसने तीन प्रमुख कारोबारी मानकों पर वार्षिक वृद्धि लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। कासा और सावधि जमा में गिरावट के अलावा उसके फंसे हुए कर्ज की मात्रा भी बढ़ गई।

इसके बावजूद शाखा प्रमुख विदेश यात्रा हासिल करने के मुहाने पर ही था। इसका इंतजाम बैंक के बीमा साझेदार ने किया था। उसने जीवन बीमा योजनाओं के मामले में बहुत उल्लेखनीय कारोबार किया था। जब बैंकर को पता चला कि शाखा प्रीमियम लक्ष्य से केवल 10 लाख रुपये दूर है तो उसने और बीमा एजेंट ने (जो खुद को बैंक कर्मचारी बताता था) उमा देवी (बदला हुआ नाम) नामक एक 71 वर्षीय महिला से कहा कि वे अपनी जमा राशि निकाल कर बेहतर रिटर्न वाली योजना में डाल दें।

सालों तक वह बुजुर्ग महिला पैसे निकालने और अपने स्वर्गीय पति द्वारा खोली गई सावधि जमा का नवीनीकरण कराने बैंक आती रहीं थीं। अब इनमें से दो सावधि जमा का भुगतान लेकर उन्हें जीवन बीमा योजना में निवेश कर दिया गया था। इसका सालाना प्रीमियम 10 लाख रुपये था। किसी ने यह नहीं सोचा कि अगले पांच साल तक वह कैसे यह राशि चुकाएंगी। बदले में शाखा प्रबंधक को सात दिन की विदेश यात्रा का अवसर मिला। वह 'प्रशिक्षण' के लिए अमेरिका गया।

इस साल जब बीमा कंपनी ने दोबारा प्रीमियम मांगा तो उमा देवी स्तब्ध रह गईं। वह भागी-भागी शाखा गईं। तब तक प्रबंधक की पदोन्नति हो चुकी थी और वह किसी दूसरे राज्य में जा चुका था। बीमा एजेंट जिसने बैंक कर्मी होने का स्वांग रचा था वह दूसरी कंपनी में जा चुका था।

काफी दिक्कतों के बाद शाखा ने उन्हें उनके हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव दिखाया। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी राशि वापस कर दी जाए क्योंकि अगले महीने उनकी बेटी की शादी थी। शाखा ने मना कर दिया। बीमा कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे।

उनकी बेटी इस मामले को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग तक ले गई। विभाग के सचिव एम नागराजू ने व्यक्तिगत रूप से इसकी सुनवाई करने का निश्चय किया। सुनवाई के एक दिन पहले पूरी राशि बिना किसी कटौती के उमा देवी के खाते में वापस कर दी गई।

ऐसे मामले देश भर में आम हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जीवन बीमा क्षेत्र में अनुचित व्यावसायिक चलन के अंतर्गत वर्गीकृत शिकायतें वित्त वर्ष 2025 में लगभग 14.3 फीसदी बढ़कर 26,667 हो गईं, जो वित्त वर्ष 2024 में 23,335 थीं। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो अनुचित व्यावसायिक चलन से संबंधित शिकायतें वित्त वर्ष 24 में 19.33 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 22.14 फीसदी हो गईं।

आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल को वित्त वर्ष 25 में 2,57,790 शिकायतें मिलीं। यह एक साल पहले की तुलना में 20 फीसदी अधिक थीं। इनमें से करीब 1.20 लाख शिकायतें जीवन बीमा से संबंधित और 1.37 लाख शिकायतें सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित थीं।

वित्त वर्ष 23 में जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ दर्ज कुल शिकायतों में लगभग पांच में से एक मिस-सेलिंग के बारे में थीं। निजी क्षेत्र से बहुत अधिक शिकायतें मिलीं। बीमा लोकपाल परिषद को वित्त वर्ष 2024 में 52,575 शिकायतें प्राप्त हुईं। बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत स्थापित यह परिषद पॉलिसीधारकों को बीमा कंपनियों और उनके मध्यस्थों या बीमा दलालों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करती है।

एक प्रमुख स्वतंत्र मंच पर वित्त वर्ष 25 की आखिरी तिमाही से वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के बीच में इस तरह की शिकायत में 45 फीसदी का इजाफा हुआ। इसमें मिस-सेलिंग की अहम भूमिका थी। इस पीड़ा से गुजरने वालों में कई विधवा और वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिली राशि बैंकों में जमा करते हैं। लगभग सभी घर खरीदने वालों को साथ में बीमा योजना खरीदने पर विवश किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम कर्जदारों को कर्जदाता बीमा साझेदारों की योजनाओं में निवेश पर विवश किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया है कि बीमा क्षेत्र की प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति वित्त वर्ष 25 में 74.4 लाख करोड़ रुपये हो गई। प्रीमयम राशि वित्त वर्ष 21 के 8.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 11.9 लाख करोड़ रुपये हो गई। प्रबंधनाधीन संपत्ति में 91 फीसदी हिस्सा जीवन बीमा का है।

इसके बावजूद देश में बीमा पहुंच वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 फीसदी तक रही। यह वैश्विक औसत का आधा है। जीवन बीमा क्षेत्र में पहुंच में मामूली गिरावट आई और यह 2024 के 2.8 फीसदी से कम होकर 2.7 फीसदी रह गई। इस बीच बीमा घनत्व यानी प्रति व्यक्ति प्रीमियम 95 डॉलर से बढ़कर 97 डॉलर हो गया। यानी यह कम पहुंच और उच्च लागत वाला मामला है। इसे समुचित बनाए बिना 2047 तक सबके लिए बीमा का स्वप्न पूरा नहीं होगा।

आईआरडीएआई ने एक अप्रैल 2023 से कमीशन भुगतान विनियम, 2023 और प्रबंधन व्यय (ईओएम) विनियम, 2023 लागू किए, जिन्होंने कमीशन ढांचे को उदार बनाया और कठोर उत्पाद वार कमीशन सीमा से हटकर कंपनी स्तरीय प्रबंधन व्यय की कुल सीमा पर आधारित व्यवस्था की ओर बदलाव किया। नए ढांचे में, बीमा कंपनियां अपनी स्वयं की कमीशन संरचनाएं तैयार कर सकती हैं, बशर्ते कि कुल कमीशन और अन्य व्यय निर्धारित ईओएम सीमाओं के भीतर रहें।

आईआरडीएआई ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन नियमों को आईआरडीएआई (प्रबंधन व्यय, जिसमें बीमा कंपनियों का कमीशन शामिल है) विनियम, 2024 में समेकित कर दिया, जिससे अनुपालन सरल हो गया। लेकिन यह मूल सिद्धांत बरकरार रहा कि निदेशक मंडल को कमीशन संरचना तय करने का विवेकाधिकार है बशर्ते कि यह कुल ईओएम सीमा के भीतर रहे (सामान्य बीमा के लिए 30 फीसदी और स्वास्थ्य बीमा के लिए 35 फीसदी)।

वास्तव में उदार कमीशन ढांचा और तीव्र बिक्री लक्ष्यों का संयोजन बैंक एश्योरेंस को और भी आक्रामक चैनल बना सकता है, यदि विनियमित संस्थाओं के बोर्ड संयम नहीं बरतते और बैंक प्रबंधन कर्मचारी पुरस्कारों और प्रोत्साहनों को तृतीय पक्ष आय से जोड़ना जारी रखते हैं। बैंक एश्योरेंस में बैंक और बीमा कंपनी मिलकर बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचते हैं। इस साझेदारी में बैंक कर्मचारी और टेलर ग्राहक के लिए बिक्री और संपर्क के केंद्र बन जाते हैं। जो ग्राहक शाखाओं में बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए आते हैं, विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई शाखाओं में, उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रेरित करके या दबाव डालकर ऐसे जटिल वित्तीय उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें वे न तो चाहते हैं और न ही समझते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया मसौदा संशोधन निर्देशों की यही पृष्ठभूमि है। यह वित्तीय उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग से संबंधित हैं। मिस-सेलिंग कोई अपवाद नहीं है, बल्कि अधिकांश बैंकों में वर्तमान प्रोत्साहन संरचना का एक उप-उत्पाद है। यदि वे ग्राहकों का विश्वास पाना चाहते हैं तो उन्हें इसे बेहतर बनाना होगा।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

पूरी दुनिया को मिले एआई का फायदा

इस समाचार पत्र में प्रकाशित 'भारत के समक्ष अवसर' के संदर्भ में भारत द्वारा आयोजित वैश्विक एआई सम्मेलन तकनीक के वैश्विक शासन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब एआई से जुड़े नियमों और चर्चाओं का केंद्र केवल सिलिकॉन वैली या चीन नहीं रहेंगे। भारत के नेतृत्व में 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और उभरते देश) अब अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, ताकि वे तकनीक के केवल उपभोक्ता न रहकर उसके नियम तय करने वाले भागीदार बन सकें। भारत ने आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से पहले ही दिखा दिया है कि तकनीक का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाता है और अब यही दृष्टिकोण एआई के लिए भी अपनाया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य तकनीकी असमानता को दूर करना है। वर्तमान में एआई प्रणालियां जिन डेटा सेट पर प्रशिक्षित होती हैं, उनमें विकासशील देशों की भाषाओं और सांस्कृतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों को एक मंच पर लाकर ऐसे अधिक समावेशी और प्रतिनिधि डेटा की मांग कर सकता है जो सभी समाज के लिए उपयोगी हों। यह कदम न केवल तकनीक को निष्पक्ष बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी सुरक्षित रखेगा। इस सम्मेलन का लक्ष्य तकनीकी निर्भरता को तकनीकी स्वायत्तता में बदलना है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई का भविष्य कुछ चुनिंदा शक्तियों के बजाय पूरी दुनिया के समाज की जरूरतों के हिसाब से तय हो।

अमरजीत कुमार, हजारीबाग

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई आधारित कई स्टॉल लगाए गए हैं

फ्रांस के साथ कई करार

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा दोनों देशों के बीच रिश्ते और सहयोग की नई इबारत लिख गया। इस दौरे में एरोस्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियों समेत लगभग 20 समझौते एवं घोषणाएं हुईं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है कि दोनों देश संयुक्त रूप से एयरबस के एच-125 मॉडल का निर्माण करेंगे, यह भारत की सामरिक जरूरतों के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। इनका भारत में निर्माण कर विश्व भर में निर्यात भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय कंपनी बीईएल और फ्रांस की कंपनी सैफ्रान के बीच भारत में हैमर मिसाइल निर्माण को लेकर भी करार हुआ है। रक्षा अनुसंधान, संवेदनशील तकनीक साझेदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जैसे कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की गई। चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत और फ्रांस का करीब आना यूरोप और एशिया दोनों के लिए रणनीतिक संदेश है। फ्रांस रक्षा उत्पादन में अग्रणी है, वहीं भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी प्रतिभा संपन्न देश है। दोनों देश एआई गवर्नेंस, रक्षा एवं पर्यावरण में नया संतुलन बना रहे हैं। दोनों देश तीसरा वैश्विक विकल्प कायम कर सकते हैं।

विमलेश पगारिया, बदनावर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

चंडीगढ़ में 'टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी (टीबीआरएल) में डीआरडीओ के 'रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड' (आरटीआरएस) प्रतिष्ठान में भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत 'ड्रोग पैराशूट' का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह परीक्षण इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डीआरडीओ के 'एरियल डिलिवरी रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' और टीबीआरएल की विभिन्न टीमों के सहयोग से आयोजित किया गया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दैनिक जागरण

प्रत्येक परिवर्तन चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लाता है

बोझ बनी मुफ्त की संस्कृति

यह पहली बार नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां कही जाने वाली लोकलुभावन योजनाओं पर अपनी आपत्ति और चिंता प्रकट की हो। वह कई बार यह कह चुका है कि मुफ्त की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा है। गत दिवस भी उसने सरकारों की ओर से मुफ्त सुविधाएं और वस्तुएं देने के चलन पर यह प्रश्न किया कि यदि वे इसी तरह फ्री अनाज, बिजली, साइकिल आदि देते रहे तो विकास के लिए धन कहां से आएगा? उसने इस पर भी बल दिया कि सरकारें मुफ्त की सुविधाएं और सामग्री के स्थान पर रोजगार दें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल यह मान चुके हैं कि लोकलुभावन योजनाएं चुनाव जीतने की गारंटी बन गई हैं। इसका परिणाम यह है कि चुनाव आते ही सत्तारूढ़ दल और सत्ता की चाह रखने वाले विपक्षी दल मुफ्त की योजनाओं का पिटारा खोलने में जुट जाते हैं। अब तो वे सीधे धन देने की भी घोषणा करने लगे हैं। यह तब है, जब अधिकांश राज्य घाटे में हैं। विडंबना यह है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की कमी का रोना रोते हैं और फिर भी मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। साफ है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी करते हैं।

इस पर आश्चर्य नहीं कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आते ही संबंधित राज्य सरकारों की ओर से मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की जाने लगी है। तमिलनाडु सरकार ने हर किसी को फ्री बिजली देने की पेशकश कर दी है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि यह याचिका तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने दायर की है। इसके पहले भी ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। निःसंदेह कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह निर्धन-वंचित वर्गों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान के लिए विशेष उपाय करे और उन्हें कुछ मुफ्त या रियायती सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और उन्हें अपने स्तर पर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। बीते कुछ समय से तो वोट हासिल करने के इरादे से ऐसी सुविधाएं देने की पहल होने लगी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का उपहास और संसाधनों का दुरुपयोग भी है। जब सक्षम लोगों को भी मुफ्त की योजनाओं का लाभ दिया जाता है तो लोग एक तरह से काम न करने के आदी बनते हैं और वे शासन पर बोझ बनते हैं। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, जिससे गरीब एवं अक्षम लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने का काम राज्य के आर्थिक संसाधनों के आधार पर हो, न कि मनमाने तरीके से चुनाव जीतने के लिए।

खेल और खेत

हरियाणा लंबे समय से खेलों की धरती और कृषि की पहचान दोनों को साथ लेकर चलता आया है। अब खेल बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को समानांतर गति दी जा रही है, तो यह संकेत है कि नीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। खिलाड़ियों के लिए ढांचागत सुविधाओं का विस्तार, कोचों की नियुक्ति, स्टेडियमों का उन्नयन और डाइट मनी का समयबद्ध प्रविधान ये सब उस आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, जिसने राज्य को अंतरराष्ट्रीय पदक तालिका में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। खेलों में निवेश पदकों का प्रश्न नहीं, यह अनुशासन, स्वास्थ्य और युवाओं के सकारात्मक भविष्य का निवेश है। प्रस्तावित बजट वृद्धि दीर्घकालिक लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में हरियाणा खेल अवसंरचना का राष्ट्रीय मानक स्थापित कर सकता है। इसी तरह, चार सौ करोड़ रुपये से अधिक की सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं जल संकट और बढ़ती लागत के बीच दूरदर्शी पहल हैं। जल दक्षता, ऊर्जा बचत और सामुदायिक माडल ये तीनों तत्व कृषि को टिकाऊ दिशा देते हैं। लगभग नौ हजार किसानों तक सीधा लाभ पहुंचाने वाली यह योजना केवल आर्थिक राहत नहीं, पर्यावरणीय संतुलन का भी प्रयास है।

जब राज्य प्रतिभा और उत्पादन दोनों में निवेश करता है, तभी विकास का संतुलित मानचित्र तैयार होता है

अपनों को भी अमेरिका से दूर करते ट्रंप

डा. एके वर्मा

ट्रंप की नीतियों के चलते तमाम अन्य देशों के साथ-साथ भारत जैसे अमेरिका के निकट सहयोगियों में भी उसके प्रति संदेह और अविश्वास का माहौल बना है, जो आसानी से दूर नहीं होगा

अवधेश राजपूत

पूरे विश्व में अमेरिका की प्रतिष्ठा एक आदर्श लोकतंत्र की रही है। उसके उदारवादी मूल्यों को लोकतंत्र का मानदंड माना गया है। हालांकि हाल के समय में उसके प्रति यह धारणा बदलती दिख रही है। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी संस्थानों की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उनका चुनावी नारा मेक-अमेरिका-ग्रेट-अगेन (मागा) यानी 'अमेरिका को पुनः महान बनाना है' रहा। इसमें भी एक आत्मस्वीकृति थी कि अमेरिकी लोकतंत्र अब महान नहीं रहा और ट्रंप उसका पुराना गौरव लौटाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया नहीं कि अमेरिकी महानता के कौन-कौन से स्तंभ धराशायी हो गए हैं, जिनका वे पुनरुत्थान करना चाहते हैं। जब सोवियत संघ के बिखरने के बाद एकध्रुवीय विश्व में अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया, तब ट्रंप की चिंता के क्या कारण हो सकते हैं? संभवतः बदलता भू-राजनीतिक, मौद्रिक और प्रतिरक्षा संबंधी परिदृश्य ट्रंप को चिंतित कर रहे हैं।

भू-राजनीतिक परिदृश्य पर चीन एवं भारत के उभार से 21वीं सदी एशिया की हो चली है। ट्रंप ने आर्थिक-उपनिवेशवादी मानसिकता से तमाम देशों पर टैरिफ लगाया। उससे न केवल भारत, चीन और रूस निकट आए, वरन अमेरिका के सहयोगी देश कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी चीन एवं भारत की ओर रुख कर लिया। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में अमेरिकी विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिस आक्रामकता से ट्रंप ने टैरिफ वार चलाया, जिस बड़बोलेपन का प्रयोग उन्होंने 'वैश्विक-राजनय' में किया, जिस निर्लज्जता से 'नोबेल शांति पुरस्कार' के लिए लालसा दिखाई, जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदी बनाया, जिस नव-साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोका, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि एक 'अंतरराष्ट्रीय दादा' जैसी हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय-कानून और कूटनीतिक-शिष्टाचार को धता बता कर कुछ भी करने पर आमादा हैं। एक ओर वे पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताते नहीं थकते तो दूसरी ओर उन्हें उकसाने के लिए अनर्गल प्रलाप भी करते रहे। उन्होंने आपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता का दावा किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनमी' बताया, जबकि भारत विश्व की चौथी बड़ी आर्थिकी है, जो कुछ ही समय में तीसरे पायदान पर पहुंचने के निकट है।

ट्रंप की नीतियों से न केवल एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, वरन अमेरिका के निकट सहयोगियों में भी उसके प्रति संदेह और अविश्वास बढ़ गया। इससे एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेती दिख रही है। ट्रंप इसे समझते हैं और इसीलिए उन्होंने गाजा शांति बोर्ड जैसी पहल कर स्वयं को उसका आजीवन मुखिया भी नामित कर लिया, जिसके पास अंतिम निर्णायक वीटो होगा। ऐसी पहल स्थापित अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बन उसे प्रतिस्थापित करने का कुत्सित प्रयास भी है।

मौद्रिक मोर्चे को लेकर भी ट्रंप तनाव में हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में डालर का बोलबाला है। वैश्विक मुद्रा विनिमय में अमेरिकी बैंकों तथा स्विफ्ट जैसी व्यवस्थाओं का एकाधिकार है। इनका प्रयोग अमेरिका सभी देशों के विरुद्ध हथियार के रूप में करता रहा है। जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने 2022 में रूस के मुद्रा भंडार पर रोक लगा दी। यह एक खतरे की घंटी ही थी। इससे सबक लेते हुए भारत ने अमेरिकी गोल्ड-बांड की बिकवाली की और अपने डालर भंडार को 2023 में 40 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जर्मनी, न्यूजीलैंड, रूस, बांग्लादेश, इजरायल, सिंगापुर, श्रीलंका, इंग्लैंड सहित 22 देशों के बैंकों को भारत में 'स्पेशल वोस्ट्रो रुपया अकाउंट' खोलने की स्वीकृति दी, जिससे इनके साथ डालर की जगह रुपये में व्यापार होगा। इसी बीच यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर भी सहमति बनी। इसके बाद अमेरिका पर दबाव बनना स्वाभाविक ही था, जिसका परिणाम भारत के साथ परस्पर लाभ वाले एक अंतरिम व्यापार समझौते के रूप में निकला। भारत ने अमेरिका के सामने स्पष्ट कर दिया था कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं और उसके पास विकल्पों की कमी नहीं। आखिर 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाला देश किसी के आगे झुके भी क्यों? यह भी न विस्मृत किया जाए कि अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी तो भारत की उतनी ही आवश्यकता है।

ट्रंप की एक चिंता प्रतिरक्षा तंत्र से भी जुड़ी है। भारत रक्षा उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' की डगर पर चल पड़ा है। एक तो भारत बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन की दिशा में बढ़ रहा है तो विदेशी खरीद के मामले में भी बहुत सोच-समझकर कदम बढ़ा रहा है। गत वर्ष भारत ने फ्रांस से 63 हजार करोड़ रुपये के राफेल जेट्स खरीदे, जबकि 50 प्रतिशत ट्रंप टैरिफ के कारण उनके स्ट्राइकर व्हीकल, जेवलिन मिसाइल और बोइंग पी81 एयरक्राफ्ट की खरीद रोक दी। ट्रंप ने यह संकेत भी समझा और अंततः भारत के साथ व्यापार समझौता करने और टैरिफ घटाने को बाध्य हुए। द्विपक्षीय संबंधों में अब स्थितियां भले ही सामान्य होती दिख रही हों, लेकिन ट्रंप की आक्रामकता से भारतीयों के मन में उनके प्रति संदेह और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए कुछ निराशा जरूर बढ़ी है। वैसे ट्रंप और अमेरिका एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अमेरिकी जनता का एक बड़ा वर्ग भी ट्रंप से परेशान है। सौभाग्य से भारत-अमेरिका संबंध गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। संभव है कि आगे अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक छवि और महानता की पुनर्स्थापना करे।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सिविल सेवा परीक्षा में सही सुधार

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस संस्था में समय के अनुसार लगातार सुधार और समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहती है। 2026 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के कुछ कदम स्वागतयोग्य हैं। इनके अनुसार परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने पर यदि किसी उम्मीदवार को ग्रुप ए की कोई सेवा मिल जाती है, तो उसके बाद उसे आइएएस, आइएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए केवल एक अवसर और मिलेगा। उसके बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह अपने विभाग से प्रसन्न नहीं है, तो त्यागपत्र देकर फिर से परीक्षा दे सकता है। आइएएस और आइएफएस में एक बार चुने जाने के बाद फिर से परीक्षा में बैठने की इजाजत पहले की तरह अभी भी नहीं होगी। वैसे यहां लोकतांत्रिक ढंग से एक गुंजाइश छोड़ी गई है। लगभग 23 विभागों में पांच विभाग जैसे अगर दिल्ली में दानिक्स या पुडुचेरी पुलिस आदि में ग्रुप बी की सेवा मिलती है तब जरूर उसे एक से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। इस एक सुधार से कई स्तरों पर फायदा होगा। सबसे पहले नए उम्मीदवारों के लिए ज्यादा पद खाली मिलेंगे, वरना पहले से सफल उम्मीदवार बार-बार उन्हीं पदों पर चुने जाते रहे हैं। एक बार चुने जाने वालों के लिए भी एक और अवसर देने से वे लगातार 30-35 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने के लोभ से बच जाएंगे।

सभी सेवाओं के वेतनमान और सुविधाएं लगभग बराबर ही होती हैं। पहले इन विभागों को उम्मीदवार तो आवंटित हो जाते थे, लेकिन उनमें से कितने ज्वाइन करेंगे, कोई पता नहीं होता था। कुछ फिर से परीक्षा में बैठने के लिए लगातार दो-चार वर्षों तक कई बहाने जैसे मेडिकल, मां की बीमारी आदि बताकर कोशिश करते रहते थे। इससे उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण की समस्याएं पैदा होती थीं। नतीजतन प्रशासनिक क्षमता में लगातार गिरावट आ रही थी। अब सभी विभाग बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इससे सभी विभागों की ट्रेनिंग और क्षमता भी बेहतर होगी। इस सुधार के सामाजिक परिणाम भी अच्छे आएंगे। जब जाति विशेष के कारण किसी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनंत छूट रहती है, तब तक उसके अंदर बार-बार परीक्षा देने की भूख भी कायम रहती है, लेकिन प्रश्न है कि कितने उम्मीदवारों के लिए यह संभव है? क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान पीढ़ी की क्षमता और ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? क्या यह सामाजिक-जातीय विभाजन की तरह सेवाओं में भी कमतर और बेहतर की भावना पैदा नहीं करता? उनके अभिभावक भी लगातार चिंता में डूबे रहते हैं कि उनकी परीक्षा के चक्र कब खत्म होंगे? देश को इन सबसे मुक्ति चाहिए। मौजूदा सुधार का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है और वह है राज्यवार कैडर में उम्मीदवारों का वितरण।

प्रेमपाल शर्मा

जब सभी सेवाओं में सुविधाएं बराबर ही हैं तो आयकर वाला रेलवे में काम करने वाले को नीचे क्यों समझता है?

समय के अनुरूप सुधार की राह पर यूपीएससी। फाइल

नौकरशाही के स्टील फ्रेम में आइएएस सबसे मजबूत आधार होता है। जिस राज्य के लिए उनका आवंटन होता है, वे उस राज्य में ही रहते हैं या फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, लेकिन उस राज्य में बने रहने के कुछ दुष्परिणाम अतीत में अनुभव किए गए। जैसे जब पंजाब में आतंकियों ने कहर बरपा रखा था, तब अहसास हुआ कि वहां नियुक्त कुछ अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच मिलीभगत हो गई थी। इसलिए बाद में यह फैसला किया गया कि किसी भी राज्य में वहां के रहने वाले उम्मीदवारों के एक तिहाई से ज्यादा नहीं तैनात होंगे और दो तिहाई उम्मीदवार दूसरे राज्यों के होंगे। देश की एकता में इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य राज्य में तैनात होते हैं, तो भाई-भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहती है। अब इसी में एक कदम और बढ़ाकर इसे और पारदर्शी ढंग से किया गया है। इससे उम्मीदवारों में यह अहसास और पुख्ता होगा कि पूरा देश आपका है और आपको कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है।

हालांकि सरकार नए नियमों को कितनी दृढ़ता से लागू करती है, यह एक सवाल है। पुराने अनुभवों पर नजर डालें तो 1986 में भी इससे कुछ मिलते-जुलते कदम उठाए गए थे। तब परीक्षा देने के प्रयासों पर ऐसी ही रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके खिलाफ दशकों तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई। झूठ-सच के आधार पर उम्मीदवारों ने छुट्टी ली और फिर से वर्षों तक परीक्षाएं दीं। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचा और उसकी कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ा। अफसरों के बीच जो परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसके बदले उनमें ईर्ष्या पनपने लगी। जब सभी सेवाओं की लगभग 99 प्रतिशत सुविधाएं बराबर हैं तो इनकम टैक्स में काम करने वाला रेलवे में काम करने वाले को कमतर क्यों समझता है?

अपने देश में आइएएस या आइपीएस का नशा तो सातवें आसमान पर रहता है। यह भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि वह जन्म से ही बराबरी नहीं सिखाता। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा भी है कि संविधान में तो हमने बराबरी ला दी, लेकिन समाज अभी उससे बहुत दूर है। इससे देश को नुकसान पहुंच रहा है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। यूपीएससी में अभी और सुधारों का इंतजार है। हमने ब्रिटिश शासन से स्टील फ्रेम तो ले लिया, लेकिन उसके आत्मा को आत्मसात नहीं किया। यानी कार्यक्षमता, कम उम्र में भर्ती, पाठ्यक्रम, व्यवस्थित प्रशिक्षण, काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी।

(लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संकल्प की शक्ति

संकल्प मनुष्य की वह आंतरिक ज्वाला है, जो साधारण जीवन को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा देती है। विचार जब दृढ़ निश्चय में बदल जाता है, तब वह संकल्प बनता है और संकल्प ही वह शक्ति है, जो असंभव को संभव बनाने का साहस देती है। इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों ने अपने लक्ष्य को केवल इच्छा नहीं, बल्कि संकल्प बनाया, उन्होंने युग बदल दिए।

महात्मा गांधी का संकल्प केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा के आधार पर समाज को परिवर्तित करने का था। अनेक असफलताओं, जेल यात्राओं और आलोचनाओं के बावजूद उनका निश्चय डिगा नहीं। परिणामस्वरूप, उनका व्यक्तिगत संकल्प जन-जन का विश्वास बन गया। इसी प्रकार, स्वामी विवेकानंद ने निर्धनता, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच यह संकल्प लिया कि वे भारत की आध्यात्मिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करेंगे। शिकागो धर्म संसद में उनका ओजस्वी उद्बोधन केवल वक्तृत्व का चमत्कार नहीं, अपितु उनके अटूट संकल्प का प्रतिफल था। आधुनिक भारत में डा. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी संकल्प की शक्ति का प्रेरक उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे देश को वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उनका जीवन सिखाता है कि संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि संकल्प की कमी मनुष्य को रोकती है।

संकल्प वह दीप है, जो लक्ष्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रतिभा मार्ग दिखा सकती है, परंतु उसे गंतव्य तक पहुंचाने की शक्ति संकल्प ही देता है। जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय जाग उठता है, उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं, बल्कि साधन बन जाती हैं। इसलिए जीवन में सफलता का प्रथम सूत्र यही है-सपना देखो, उसे संकल्प में बदलो और फिर अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसे जियो।

प्रो. आनंदप्रकाश त्रिपाठी 'रत्नेश'

डीपफेक से प्रताड़ित होते बच्चे

रामबाबू सोनी

डीपफेक में बच्चों की तस्वीरों को एआइ के माध्यम से अश्लील बनाया जाता है

यूनिसेफ ने इंटरपोल के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अबोध बच्चों की तस्वीरों को एआइ के माध्यम से अश्लील बनाया जाता है। इसमें बताया गया है कि पिछले एक वर्ष में विश्व में 12 लाख बच्चे डीपफेक के शिकार हुए हैं। यूनिसेफ ने कुल 11 देशों का अध्ययन किया, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में प्रताड़ित बच्चों की संख्या सर्वाधिक रही। अध्ययन में 12-17 वर्ष की आयु के 50 हजार बच्चों और उनके माता-पिता को सम्मिलित किया गया था। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कई देशों में 25 में से एक बच्चा इससे प्रताड़ित हुआ है। जिन देशों में एआइ के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कठोर कानून नहीं बने हैं, उन देशों में प्रताड़ित हुए बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे देशों की संख्या 90 प्रतिशत रही है। वर्तमान समय में एआइ का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

अध्ययन में पाया गया कि लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक प्रताड़ित हुई हैं। 64 प्रतिशत लड़कियां न्यूडिफिकेशन एवं 36 प्रतिशत लड़के आर्थिक सेक्सटार्सन के शिकार हुए हैं। न्यूडिफिकेशन में किसी की फोटो से कपड़े हटाकर या बदलकर उसे अश्लील बनाया जाता है, सेक्सटार्सन में आर्थिक ब्लैकमेलिंग और फेस स्वैपिंग में किसी दूसरे के शरीर पर आपका चेहरा लगा दिया जाता है। इसी प्रकार आपकी आवाज की नकल कर गलत आडियो संदेश भेजे जाते हैं। यह काम एआइ के माध्यम से इतनी सफाई से किए जाते हैं कि इसमें सही और गलत को पहचान पाना मुश्किल है। इंटरनेट पर उपलब्ध आधी से अधिक सामग्री ऐसी है जिसमें सही और गलत को पहचानना मुश्किल होता है।

बच्चों से जुड़े ऐसे डीपफेक वीडियो के लिए 2006 से 'इंटरनेशनल सेंटर फार मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन' नामक संस्था वैश्विक स्तर पर बनाए गए कानूनों की निगरानी कर रही है। इसके अनुसार विश्व के 196 में से 156 देशों ने यौन शोषण के विरुद्ध कानूनों को लागू किया है। 10 देशों में कोई कानून नहीं है, 111 देशों में कुछ कानून बने हैं, जबकि मात्र 27 देश ही कानूनों के माध्यम से डीपफेक को रोकने की दिशा में संपूर्ण मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे असत्य और निराधार आडियो-वीडियो से विशेषकर लड़कियां मानसिक अवसाद में जाकर आत्महत्या तक कर रही हैं। यूनिसेफ ने विश्व की सरकारों से बाल यौन शोषण सामग्री की कानूनी परिभाषाओं का विस्तार करने का आह्वान किया है। वर्तमान कानूनों के अनुसार पाक्सो एक्ट के अंतर्गत बाल शोषण से संबंधित सामग्री देखने या रखने को अपराध माना गया है, किंतु यह कानून पर्याप्त नहीं हैं। तकनीकी के विस्तार के साथ आइटी कानूनों की भी समीक्षा होती रहनी चाहिए। कठोर कानूनों के निर्माण तक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स के साथ-साथ लोगों को भी इस दिशा में जागरूक करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जनहित में हो एआइ का उपयोग

संपादकीय 'एआइ क्रांति की चुनौतियां' पढ़ा। एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आज विश्व स्तर पर परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। भारत भी इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में उभर रहा है। एआइ से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ी है, पर इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। यदि एआइ के विकास में हम विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर रहे, तो यह दीर्घकाल में आर्थिक-रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, रोजगार पर प्रभाव और तकनीक के दुरुपयोग जैसी समस्याएं भी सामने हैं। एआइ का उपयोग पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सरकार और शिक्षण संस्थानों को शोध, नवाचार और कौशल विकास पर विशेष बल देना होगा, ताकि युवा इसमें दक्ष बनें। एआइ क्रांति केवल अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सही नीतियों के साथ ही भारत इस तकनीक को जनहित और राष्ट्रहित में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

रेवड़ी संस्कृति बंद होनी चाहिए

वर्ष 1953 में मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर के. कामराज ने सबसे पहले मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन जैसी स्कीम स्कूली बच्चों के लिए शुरू की थी, जिसका विकृत रूप आने वाले वर्षों में मुफ्त की रेवड़ियां बन कर चुनावों को जीतने का स्टंट बन गया। जहां बिना काम किए भी मुफ्त राशन, गैस और बिजली उन सभी को भी मिल रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। इस तरह की योजनाओं ने राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है। उन्हें ऋण ले-लेकर हर माह इसका भुगतान करना पड़ रहा है। इससे दो नुकसान हो रहा है-एक तो ये योजनाएं जनता को अकर्मण्य आलसी बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्ज में डूब कर राज्य घी पी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस बारे में स्वाभाविक है। सरकार को इस तरह की रेवड़ी संस्कृति को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए जिसमें चुनाव आयोग की इस बारे में सिफारिशों का समावेश होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए ये एक तरह की रिश्वत ही होती है, जो चुनावी पार्टियां घोषणा करके वोटों को अपनी और खींचने के लिए जनता को देती हैं। भगवानदास छारिया, इंदौर

मेलबाक्स

सामरिक सुरक्षा की मजबूती

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष देश से जोड़ने वाला 'चिकननेक' गलियारा सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण शत्रुओं की कुदृष्टि इस संकरे मार्ग पर बनी रही है। इसकी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी भूमिगत रेलवे सुरंग परियोजना की योजना तैयार की है। यह प्रस्तावित रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के तीन माइल हाट से शुरू होकर, सिलीगुड़ी के निकट रंगापानी से होते हुए बागडोगरा तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 35.76 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के तहत दो अलग-अलग समानांतर सुरंगें बनाई जाएंगी। सुरंगों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन और कंक्रीट की मोटी सुरक्षा परतों का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना भारतीय सेना के आगामी तीन प्रमुख सैन्य बेसों के लिए 'लाइफलाइन' सिद्ध होगी: किशनगंज (बिहार), चोपड़ा (पश्चिम बंगाल) और धुबड़ी (असम)। प्रस्तावित रेल लाइन इनमें से दो क्षेत्रों (किशनगंज और चोपड़ा) के अत्यंत निकट से गुजरेगी। चूंकि यह क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बेहद करीब है, इसलिए युद्ध या मिसाइल हमले जैसी आपातकालीन स्थिति में भी पूर्वोत्तर भारत से संपर्क टूटेगा नहीं। भूमिगत होने के कारण यह मार्ग हवाई हमलों से सुरक्षित रहेगा। सुरंग के भीतर अत्याधुनिक संचार प्रणाली और सुरक्षा सेंसर लगाए जाएंगे। कंक्रीट की मोटी दीवारें इसे उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को सहने की क्षमता प्रदान करेंगी, जिससे भारतीय सेना और रसद की आवाजाही निर्बाध बनी रहेगी। vpagaria187@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी *
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय :011-43166300, नोएडा कार्यालय :0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.वी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

Be part of Community and Get Early Access to All.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ English Editorials

[National + International Editorials]